रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1972/ज्येष्ठ 27, 1894
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1972/JYAISTHA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक आदेश और अधिसूचनाएं।

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th March, 1972

NOTIFICATION

S.O. 1408.—In pursuance of rule 4(b) of the Central Information Service Rules, 1959, the Central Government as the result of the review undertaken, hereby fixes the authorised permnent strength of the following grades of the Central Information Service as on the 1st of March, 1971.

Grade	Authorised Permanent Strength
Class I :	
Selection Grade	1
Senior Administrative Grade :	
(Senior Scale)	5
(Junior Scale)	5
Junior Administrative Grade :	
(Senior Scale)	8
(Junior Scale)	7
Grade I	102
Grade II 63	
Add leave reserve @10% 19	111
Add deputation reserve @15% 29	

AUTHORISED PERMANENT STRENGTH

Class II :		
Grade III		135
Grade IV :	276	
Add leave reserve @10%	41	538
Add deputation reserve @ 5%	21	
TOTAL STRENGTH :		712

2. The total authorised permanent strength of the Central Information Service has been fixed at 712 as on the 1st March 1971.

[No. F. A. 11011/1/71-CIS]
J. SANYAL,
Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1972

एस० ओ० 1408—केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 के नियम 4(ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार किए गए पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप, एतद्द्वारा, केन्द्रीय सूचना सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों की 1 मार्च, 1971 को अधिकृत स्थायी संख्या निर्धारित करती है :—

ग्रेड	अधिकृत स्थायी संख्या
श्रेणी—1	
सेलेक्शन ग्रेड . . .	1
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—	
(सीनियर स्केल) . .	5
(जूनियर स्केल) . .	5
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—	
(सीनियर स्केल) . .	8
(जूनियर स्केल) . .	7

ग्रेड		अधिकृत स्थायी संख्या
ग्रेड—1		102
ग्रेड—2 . . .	63	
10 प्रतिशत लीव रिजर्व जोड़िये .	19	111
15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति रिजर्व जोड़िये	29	
श्रेणी—2		
ग्रेड—3 . . .		135
ग्रेड—4 . . .	276	
10 प्रतिशत लीव रिजर्व जोड़िये	41	
5 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति रिजर्व जोड़िये	21	338
कुल संख्या		712

2. केन्द्रीय सूचना सेवा की 1 मार्च, 1971 को कुल अधिकृत स्थायी संख्या 712 निर्धारित की गई है।

[संख्या एफ० ए० 11011/1/71—सी०आई०एस०]

जे० सान्याल, अवर सचिव।

ORDERS

New Delhi, the 14th March, 1972.

S.O.1409.—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approved the film specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it in column 6 of the said second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

(3) Sub-section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Saurashtra Act, XVII of 1953)

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Mahila Gram Rakshak Dal	305·00 M	Director of Informarion, Govt. of Gujarat, Ahmedabad.		Documentary film (For release in Gujarat Circuit only).

[No. F 28/1/72-FP-App. 1644]

आदेश

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1972

एस० ओ० 1409 :—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ

लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके गुजरात भाषा रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का 17 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9

(3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां सौराष्ट्र अधिनियम), की धारा 5 की उपधारा (4) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धि फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैंट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	महिला ग्राम रक्षक दल	305.00 मीटर	सूचना निदेशक, अहमदाबाद	गुजरात सरकार	डाकुमैंट्री फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिये)

[सं० का० 28/1/72-एफ० पी० परिशिष्ट 1644]

New Delhi the 12th April 1972

S.O. 1014—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexured hereto the Central Government after, considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all their language versions to be of the description specified against each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section(4) of the Section 12 and and Section 16 of the Cinomatograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953.)

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the applicant	Name of the Producer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
(1)	Maharashtra News No. 237 February, 1972.	291·00 M	Director of Publicity Government of Maharashtra, Bombay.		Film dealing with news and current events (For release in Maharashtra Circuit only.)
(2)	Chaouthi Kacoti. . .	327·36 M	Do.		Documentary film (For release in Maharashtra Circuit only).

[No. F. 28/1/72-FP App. 1651]

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1972

एस० ओ० 1401—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ

लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भाषाओं के रुपान्तरों सहित जिनका विवरण उनके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 11 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षाम सम्बन्धि फिल्म है या समाचार और सामायिक घटनाओं की फिल है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	महाराष्ट्र समाचार संख्या 237 (फरवरी, 1972)	291.00	प्रचार निदेशक बम्बई,	महाराष्ट्र सरकार	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट के लिये)
2	बचनी कसौटी	327.36 मीटर	तदैव		डाकुमैन्ट्री फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट के लिये)

[संख्या फा० 28/1/72 एफ० पी० परिशिष्ट 1651]

S.O. 1411.—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Sectiob (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1962 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (4) of Section 5 of the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act 3 of 1956).

THE SECOND SCHEDULE

Serial No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
(1)	Uttar Pradesh Samachar No. 13.	292·30 M	Director of Information, Government of Uttarpradesh, Lucknow.		Film dealing with news and current events (For release in U.P. Circuit only).

[No. F. 28/1/72-F(P)-App. 1652]

एस० ओ० 1411—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रुपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।

(2) उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1955 (1956 का 3 उत्तर प्रदेश अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4)

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धित फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 13	292.30 मीटर	सूचना निदेशक सरकार, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	समाचार और सामयिक, घटनाओं की फिल्म (केवल यू पी, सर्किट के लिये)

[संख्या फ० 28/1/72–एफ० पी० परिशिष्ट 1652]

S. O. 1412—In pursuance of the direction issued under the provision of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (4) of Section 2 of the Punjab Cinemas (Regulation) Act, 1952 (Punjab Act XI of 1952).

THE SECOND SCHEDULE

Serial. No.	Title of the film.	Length 35 mm	Name of the Applicant.	Name of the Producer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
(1)	Haryana Samachar Darshan No. 6	290·78 M	Director of Public Relation, Govment of Haryana, Chandigarh.	Film dealing with news and current events (For release in Haryana Circuit only).	

[No.F. 28/1/72-F(P) App. 1653]

आदेश

एस० ओ० 1412— इस के साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई, की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रुपान्तरी सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है। स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।

(2) पंजाब सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1952 (1952 का 11 वां, पंजाब अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4)।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धित फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरियाणा समाचार दर्शन संख्या 6	290.78 मीटर	जन सम्पर्कनिदेशक चंडीगढ़	हरियाणा सरकार	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल हरियाणा सर्किट के लिये)

[संख्या फ० 28/72/एफ० पी० परिशिष्ट 1653]

S.O. 1413—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarat to be of the description specified against it in columns 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

(3) Sub-Section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinema (Regulation) Act, (Saurashtra Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the applicant.	Name of the Producer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
(1)	Silver Jubiles of Republic Day in Gujarat.	289·56 M	Director of Information, Government of Gujarat, Gandhinagar, Gujarat.		Documentary film (For release in Gujarat only).

[No. F. 28/1/72-F(P) App. 1654]

K. K. KHAN, Under Secy.

आदेश

एस० ओ० 1413—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतदद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके गुजरात भाषा के रुपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के काल 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।

(2) बम्बई, सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का 17 वां, बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधार तथा धारा 9।

(3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां, सौराष्ट्र अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) तथा धारा 9

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई, 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धित फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैन्ट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1	सिल्वर ज्युबीली रिपब्लिक डे इन गुजारात	289.56 मीटर	सूचना निदेशक. गांधी नगर गुजरात	गुजरात सरकार.	डाकुमैन्ट्री फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिये)

[संख्या क० 28/1/72-एफ० पी० परिशिष्ट 1654]

क० क० खान, अवर सचिव।

DEPARTMENT OF SUPPLY

New Delhi the 28th March 1972

S.O. 1414.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 read with rule 34, of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industry and Supply (Department of Supply and Technical Development) No. S.R.O. 3687, dated the 12th October, 1964, as amended by notification of the Government of India in the Ministry of Supply No. S.O. 1361, dated the 2nd February, 1971, namely:—

In the Schedule to the said notification, for the entry "Deputy Director General (Administration)" wherever it occurs, the entry "Director of Administration" shall be substituted.

[No. F.17(1)/67-V.]

S. S. PURI,
Director (Vigilance).

पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1972

एस० ओ० 1414.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 9 के उपनियम (2) नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) तथा नियम 34 के साथ पठित नियम 24 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा, निदेश देते कि भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और पूर्तिमंत्रालय (पूर्ति तथा तकनीकी विकास विभाग) की तारीख 12 अक्टूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 3687 में, जो भारत सरकार के पूर्ति मंत्रालय की तारीख 2 फरवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1361 द्वारा संशोधित की गई थी, और आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "उप महानिदेशक (प्रशासन)" की प्रविष्टि के लिए, जहां भी वह आए, "प्रशासन निदेशक" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[संख्या एफ० 17(1)/67-वी]

एस० एस० पुरी,
निदेशक (सतर्कता)।

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 9th March 1972

S.O. 1415.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) read with rule 21 of the Coal Mines (Conservation and Safety) Rules 1954 the Central Government hereby renominates the following member on the Advisory Committee on Stowing as reconstituted and directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) S.O. 3989 dated the 28th October, 1967, namely:—

In the said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entires shall be substituted, Namely:—

"5. Shri L. N. Orhi, M/s Bengal Coal Co. Ltd., P. O. Dishergarh, District Burdwan.

Member, Representative of the Indian Mining Association."

[No. C4-4(1)/71.]

V. K. HARURAY, Dy. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1972

का० आ० 1415.—कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम 1954 के नियम 21 के साथ पठित कोयला खान (संरक्षण सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भराई के लिए यथा—पुर्नगठित सलाहकारी समिति में निम्नलिखित सदस्यों को एतद्द्वारा पुन: नाम निर्देशित करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के भुतपूर्व इस्पात, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3989, तारीख 28 अक्तूबर, 1967 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन किए जाएंगे अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 5 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"5. श्री एल० एन० ओहरी, मैसर्स बंगाल कोयला कम्पनी लिमिटेड, डाकघर दिशेरगढ़ जिला बर्धवान।

सदस्य, भारतीय खनन संगम के प्रतिनिधि।"

[स० को० 4-4(1)/71]

वीरेन्द्र कुमार हरुरे, उप सचिव।

(Department of Mines)

New Delhi, the 14th April, 1972

S.O. 1416.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Mines and Metals), No. S.O. 3435, dated the 21st September, 1967, the Central Government hereby appoints the following persons as the Chairman and the Members of the Coal Board, established by the notification of the Government of India in the Late Ministry of Works, Production and Supply No. S.R.O. 39, dated 8th January, 1952 namely:—

1. Shri P. K. Ghosh, Coal Controller.—*Chairman.*
2. The Director (Technical), National Coal Development Corporation Ltd., Ranchi.—*Member.*
3. Shri H. K. Banerjee, C/o Bharat Coking Coal (P) Ltd., P.O. Sijua, Dhanbad.—*Member.*
4. The Director General of Mines Safety, Dhanbad.—*Member.*
5. Shri Rajendra Singh, Secretary, Hindustan Steel Ltd., Ranchi.—*Member.*

6. The Joint Director (Coal), Railway Board, C/o General Manager Eastern Railway, Calcutta.—*Member.*

7. Shri D. K. Samanta, C/o Patherdih Colliery, Patherdih.—*Member.*

[No. 4(2)/72-C4.]

P. K. LAHIRI, Dy. Secy.

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1972

सा० का० 1416—कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० 3435, तारीख 21 सितम्बर, 1967 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों को, भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 39, तारीख 8 जनवरी, 1952 द्वारा स्थापित कोयला बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्ति करती है, अर्थात् :—

1. पी० के० घोष कोयला नियंत्रक	अध्यक्ष
2. निदेशक (तकनीकी) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० रांची	सदस्य
3. श्री एच० के० बनर्जी मार्फत भारत कोककर कोयला (प्रा०) लि० डाकघर सिजुआ, धनबाद	सदस्य
4. महानिदेशक, खान सुरक्षा धनबाद	सदस्य
5. श्री राजेन्द्र सिंह सचिव, हिन्दुस्तान स्टील लि० रांची	सदस्य
6. संयुक्त निदेशक (कोयला) रेलवे बोर्ड, मार्फत महाप्रबंधक पूर्वी रेलवे, कलकत्ता	सदस्य
7. श्री डी० के० सामन्त, मार्फत पाथेरदीह कोयला खान, पाथेरदीह	सदस्य

[संख्या 4(2)/72-को० 4]

पी० के० लाहिरी, उप सचिव ।

(Department of Mines)

ERRATUM

New Delhi, the 2nd March, 1972.

S.O. 1417.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya) Department of Mines (Khan Vibhag) No. S.O. 3158-3159, dated the 24th August 1971, published in part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated the 24th August, 1971, at pages 2619 to 2621:

(i) *at page* 2619:
in line 4, *for* "New Delhi, the 24th August 1971" *read* "New Delhi, the 19th August, 1971".

(ii) at page 2621:
(i) in line 16, *for* "village Farjara" *read* "village Jarjara";
read plot No. "432".

[No. F. C3-2(3)/71.]

N. S. BHATNAGAR, Dy. Secy.

(खान विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

एस० ओ० 1417.—भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 24 अगस्त, 1971 के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में के पृष्ठ 2621 से 2625 तक प्रकाशित भारत सरकार, इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग की अधिसूचना संख्या का० आ० 3158–3159, तारीख 24 अगस्त, 1971 में :—

पृष्ठ सं० 2621 पर
पंक्ति 4 में "नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1971" के स्थान पर "नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1971" पढ़ा जाये ।

[सं० फा० को० 3–2(3)/71]

एन० एस० भटनागर, उप सचिव ।

(Department of Mines)

CORRIGENDA

New Delhi, the 4th April, 1972

S.O. 1418.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya), Department of Mines (Khan Vibhag), No. S.O. 3630, dated the 10th August, 1971, published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated the 9th October, 1971, at page 5172:—

(i) in line 26, *for* "Kuher" *read* "Muher";
(ii) in line 31, *for* "throuh" *read* "through";
(iii) in line 32, *for* "though" *read* "through";
(iv) in lines 32 and 33 for "Kolbhoora" *read* "Kolbhowra";
(v) in line 34, *for* "village Muhar" *read* "village Muher".

[No. F. C3-2(1)/71.]

K. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

(खान विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1972

सा० का० 1418.—भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की भारत के राजपत्र तारीख 9 अक्तूबर,

1971 भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०का० 3630 तारीख 10 अगस्त, 1971 में पृष्ठ संख्या 5173 और 5174 में

1. पृष्ठ संख्या 5173 में

(1) पंक्ति 8 में 'की' शब्द के स्थान पर 'के' पढ़ा जाए;

(2) पंक्ति 9 में 'खान' शब्द के स्थान पर 'रेखांक' पढ़ा जाए;

(3) पंक्ति 27 के अंक '18' के स्थान पर '181' पढ़े जाए;

(4) पंक्ति 29, क्रम संख्या 8 में 'कुहेर' शब्द के स्थान पर 'मुहेर' पढ़ा जाए;

2. पृष्ठ संख्या 5174 में

(5) पंक्ति 4 में 'चिगीटोली' शब्द के स्थान पर 'चिगीटोला' पढ़ा जाए ।

[सं० एफ० सी० 3-2(1)/71]

के० सुब्रह्मण्यन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDERS

New Delhi, the 24th March, 1972.

S.O. 1419.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 123 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S O. 5495, dated the 11th December, 1971, namely:—

In paragraph 2 of the said Order,

(i) for the words "ammunition, explosives or inflammable substances", the words "ammunition or explosives" shall be substituted;

(ii) for items (1) to (9), the following items shall be substituted, namely:—

"(1) Rule 22 of the Explosives Rules, 1940.

(2) The Kandla Port Regulations 1967 in so far as it relates to the handling of ammunition or explosives.

(3) Rules regulating the handling of explosives in the Port of Bombay.

(4) The Marmagao Port Rules, 1966, in so far as it relates to the handling or ammunition or explosives.

(5) Regulations for the import, transportation and handling of Government explosives at the Port of Cochin by the Indian Navy, issued with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. 1231, dated the 24th May, 1969

(6) The Explosives (Madras Port) Supplementary Rules, 1961.

(7) The Vishakhapatnam Port Dock Regulations, 1967, in so far as it relates to the handling of ammunition or explosives.

(8) The Paradip Port Rules 1966, in so far as it relates to the handling of ammunition or explosives.

(9) Rules regulating the handling of explosives in the port of Calcutta, issued with the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Mines and Power No. P. 103, dated the 11th March, 1947."

[No. F. 11/29/71-LI-II.]

S.O. 1420—In pursuance of sub-rule (2) of rule 123 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 5497, dated the 13th December, 1971, namely:—

In the said Order,

(i) in paragraph 1, for the words "ammunition, explosives or inflammable substances", the words "ammunition or explosives" shall be substituted;

(ii) in paragraph 2 for the word 'Schedules" the word "Schedule" shall be substituted;

(iii) for the word and figure "Schedule I", the word "Schedule" shall be substituted.

[No. F. 11/29/71-LI(II).]

C. BALASUBRAMANIAM, Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS

New Delhi, the 19th February 1972

S.O. 1421—In pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the Indian Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), the Central Government hereby appoints for a period of two years from the date of publication of this notification, a Central Advisory Committee consisting of the following persons, namely:—

Chairman

Secretary, Ministry of Shipping and Transport.

Members

1. Director General Shipping, Bombay.
2. Nautical Adviser to the Government of India.
3. Financial Adviser, Ministry of Shipping & Transport.
4. Chief Hydrographer, Indian Navy.
5. Deputy Secretary incharge of the Department of Lighthouses and Lightships in the Ministry of Shipping & Transport.
6. Shri Ahamed Usman Sait, C/o The Indian Chamber of Commerce, P O. Box No. 236, Cochin-2
7. Captain G. H. Johnson of British India Navigation Co. Ltd., Machinnon Mackenzie Building, Shoorji Vallabhdas Marg, Bombay-1.
8. Capt. A. K Bansal, Superintendent, S.P. & L. South India Shipping Corporation Ltd. 'Dhun Buildngi', 175/1 Mount Road, Madras-2.
9. Capt. B. D. Kataria, General Manager, Shipping Division, J.K. Chemicals Ltd, J.K. Building, Ballard Estate, Bombay-1
10. Shri C P. Srivastava, Chairman & Managing Director, The Shippng Corporation of India Steelcrete House, Dineshaw Wacha Road, Bombay.
11. Shri D.M. Parekh, President, Federation of the All-India Sailing Vessels Industry, Bombay.
12. Shri M. Jaggannatha Rao, M A LLB, Managing Director, Bharat Marines Private Ltd Bunder Masulipatnam-3.

13. Shri S. K. Somayajullu, Deputy Conservator, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam-1.

14. Shri Ramubhai Ravjibhai Patel, Member, Lok Sabha, Amli, P. O. Silbssa, Dadra and Nagar Haveli.

15. Shri S. G. Sardesai, Member, Rajya Sabha, 479-D, Rupra Sardar Vallabhai Patel Road, Bombay-4.

16. The Director General of Lighthouses & Light-ships, New Delhi (*ex-officio*), Member Secy.

[No. F. 4-MI.(7)/71.]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

दीपघर व दीपपोत

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1972

का० आ० 1421.—भातीय दीपघर अधिनियम, 1927 (1927 का 27) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय ।	अध्यक्ष
1. नौवहन महानिदेशक बम्बई ।	सदस्य
2. भारत सरकार का नौसलाहकार ।	
3. नौवहन और परिवहन मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार ।	
4. भारतीय नौसेना का मुख्य जल सर्वेक्षक ।	
5. नौवहन और परिवहन मंत्रालय में दीपघर और दीपपोत विभाग के प्रभारी उपसचिव ।	
6. श्री अहमद उस्मान सेठ, द्वारा दी इंण्डियन चैम्बर आफ कामर्स पी० ओ० बाक्स सें० 236, कोचीन–1 ।	
7. ब्रिटिश इंडिया के कैप्टन जी० एच० जानसन नेवीगशन कम्पनी, शूरजी बल्लभदास मार्ग, बम्बई–1 ।	
8. कैप्टन एस०के० बन्सल, अधीक्षक एस०पी०, एण्ड एल० साउथ इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन लि० धून बिल्डिंग 175/1, माउन्ट रोड, मद्रास–2 ।	
9. कैप्टन बी० डी० कटारिया महाप्रबन्धक, शिपिंग डिवीजन, जे० के० केमिकल्स लिमिटेड, जे० के० बिल्डिंग, ब्लाड इस्टेट, बम्बई ।	
10. श्री सी० पी० श्रीवास्तव, अध्यक्ष और महाप्रबन्धक निदेशक, शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, स्टीलस्ट्रीट हाउस, दिनशावाचा रोड, बम्बई ।	
11. श्री डी० एम० पारेख, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पाल जहाज, उद्योग संघ, बम्बई ।	
12. श्री एस० जगन्नाथ राव, एम० ए०, एल० एल० बी०, प्रबन्ध निदेशक, भारत मेरीनस, प्राइवेट लि०, बन्दर मसलीपत्तनम–3 ।	
13. श्री एस० के० सोमयाजुलु, उपसंरक्षक, विशाखापत्तनम, पत्तनन्यास, विशाखापत्तनम–1 ।	
14. श्री रामुभाई रावजी भाई पटल, संसद सदस्य लोक सभा, आमली डाकघर खिलवस्सा, दादरा नगर हवली ।	
15. श्री एस० जी० सरदेसाई, संसद सदस्य, राज्य सभा, 479, डी रुप्रसागर बल्लभभाई पटेल रोड, बम्बई–4 ।	
16 दीपघर दीपपोत के महानिदेशक, नई दिल्ली, पदेन सदस्य सचिव ।	

[सं० फा० 4–एम० एल० (7)/71]

New Delhi, the 7th April, 1972

S.O. 1422.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with rules 3 and 7 of the Shipping Development Fund Committee (General) Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Shri M. G. Pimputkar, Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping and Transport, as a member of the Shipping Development Fund Committee with effect from the 25th March, 1972 *vice* Shri S. K. Datta, and makes the following further amendments in notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) (Transport Wing) No. S.O. 628, dated the 17th March, 1959 namely:—

In the said Notification—

(a) In the first paragraph, for item (1) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted namely:—

"(1) Shri M. G. Pimputkar, Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping and Transport 25-3-72,"

(b) for the second paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) Shri M. G. Pimputkar shall be the Chairman of the said Committee."

[No. 35-MD(12)72.]

B. K. SAHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अप्रैल 1972

का०आ० 1422.—नौवहन विकास निधि समिति (सामान्य) नियम, 1960 के नियम 3 और 7 के साथ पठित व्यापार पोत अधिनियम 1968 (1968 का 44) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० के० दत्ता के स्थान पर श्री एम० जी० पिम्पुटकर, सचिव, भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय को नौवहन विकास निधि के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना और का० आ० 628, दिनांक 17 मार्च, 1959 में और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में :—

(क) पहले पैरा में, मद (1) और तत्सम्बन्धी, प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"(1) श्री एम० जी० पिम्पुटकर, सचिव, भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय ..... 25–3–1972,"

(ख) दूसरे पैरे के लिये, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(2) श्री एम० जी० पिम्पुटकर उक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।"

[सं० 35—एम.डी(12)/72]

बी० के० साही, अवर सचिव।

(Transport Wing)

MERCHANT SHIPPING

New Delhi, the 22nd March, 1972

S.O. 1423—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 218 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with rules 3 and 4 of the National Welfare Board for Seafarers, Rules, 1963, the Central Government herby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S. O. 255 dated the 1st January 1972, namely :—

In the said notification, under the heading "Members" for the existing entries against Serial Numbers 10, 14, 17, 18, 21 and 23, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

"10. Shri R. K. Budhbhatti, Director of Ports, Government of Gujarat, Ahmedabad.	Representative of the Government of Gujarat."
"14. Shri P.R. Narasimhan, Secretary, Cochin Port Trust, Cochin.	Representative of the Cochin Port Trust."
"17. Shri S. K. Somayajulu, Deputy Conservator, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.	Representative of the Visakhapatnam Port Trust."
"18. Shri N. K. Sen, Chairman, Calcutta Liners' Conference (Crews), 16, Strand Road, Calcutta-1.	Representative of the Shipowners."
"21. Capt. J.C. Anand, Managing Director, Pent Ocean Steamships Pvt. Ltd., Fort House, Dr. D. N. Road, Bombay—1.	Do
"23. Shri K. K. Khadilkar, Working President, National Union of Seafarers of India, 4, Goa Street, Bombay—1.	Representative of the Seafarers."

[No. 14-MT (4)/70.]

(परिवहन पक्ष)

व्यापारपोत

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1972

का० आ० 1423.—राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 3 और 4 के साथ पठित व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 218 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 255 दिनांक 1 जनवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "सदस्यों", शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 10, 14, 17, 18, 21 तथा 23 के सामने मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"10. श्री आर० के० बुद्धभट्टी, पत्तन निदेशक, गुजरात सरकार, अहमदाबाद।	गुजरात सरकार के प्रतिनिधि।"
"14. श्री पी० आर० नरसिंहन, सचिव, कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन।	कोचीन पत्तन न्यास के प्रतिनिधि।"
"17. श्री एस० के० सोमयाजुलू, उप संरक्षक, विशाखापत्तनम, पत्तन न्यास, शिाखपत्तनम।"	विशाखापतनम् पत्तन न्यास के प्रतिनिधि।"
"18. श्री एन० के० सेन, अध्यक्ष, कलकत्ता, लाइनर सम्मेलन (कर्मी दल) 16 स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता—1	जहाज मालिकों के प्रतिनिधि"।
"21. कैप्टन ज० सी० आनन्द प्रबंध निदेशक, पेंट ओशन स्टीमशिप्स प्राइवेट लिमिटेड, फोर्ट हाऊस, डा० डी० एन० रोड, बम्बई—1	—यथोक्त—
"23. श्री के० के० खाडिल्कर, कार्यकारी अध्यक्ष, नैशनल यनियन आफ इंडिया, 4, गोआ स्ट्रीट, बम्बई—1	नाविकों के प्रतिनिधि"

[सं 14—एम० टी (4)/70]

New Delhi, the 5th April, 1972

S.O. 1424.—In exercise of the powers conferred by paragraph 37 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Transport and Shipping (Transport Wing) No. S.O. 1011, dated the 12th March, 1968, the Central Government, after consulting the Board of Trustees of the Seamen's Provident Fund and having regard to the resources of the Fund available for meeting its normal administrative expenses, hereby fixes, with effect from the 1st April, 1972, the administrative charges payable under paragraph 35 of the said Scheme, at two and a half per cent.

[No. 5-MT(3)/72.]

J. K. BHATTACHARYA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1972

का० आ० 1424.—नाविक निर्वाह निधि योजना 1966 के पैरा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1011, दिनांक 12 मार्च,

1968 के अतिक्रमण में नाविक निवाह निधि के न्यासी बोर्ड से परामर्श करने के बाद और निधि के सामान्य प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए निधि के उपलब्ध साधनों की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, 1 अप्रैल, 1972 से अड़ाई प्रतिशत पर उक्त योजना के पैरा 35 के अन्तर्गत देय प्रशासनिक प्रभार निर्धारित करती है ।

[सं० 5-एम०टी(3)/72]

जे० के० भट्टाचार्य, उप सचिव ।

(Transport Wing)

(MERCHANT SHIPPING)

New Delhi, the 15th April, 1972

S.O. 1425.—In pursuance of clause (a) of Sub Section (1) of Section 283 of the Merchant Shipping Act, 1958, (44 of 1958), the Central Government hereby declares that the Government of Singapore have accepted the International Convention on Load Lines signed in London on the 5th day of April 1966, as amended from time to time.

[No. F. 42 MA(1)/70.]

A. R. BANERJEE, Under Secy.

(परिवहन पक्ष)

व्यापार पोत

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1972

का० आ० 1425.—व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 283 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि सिंगापुर की सरकार ने 5 अप्रैल, 1966 को लन्दन में हस्ताक्षरित समय समय पर यथा संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा संगमन को स्वीकार कर लिया है ।

[सं० फ० 42-एम० ए०(1)/70]

ए० आर० बनर्जी, अवर सचिव ।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 9th March, 1972

S.O. 1426. In pursuance of sub-rule (2) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 1111 dated the 19th February, 1971, namely:—

In the said notification,—

(i) in the First Schedule—

(a) against the entry "Director of Regulations and Information" in column 1, in the corresponding entry in column 2, for the figures "12", the figures and letter "12, 83A" shall be substituted;

(b against the entry "Controller of Aerodromes" in column 1, in the corresponding entry in column 2, for the figures "82, 89", the figures and letter "82, 83A, 89" shall be substituted;

(c) against the entry the "Senior Aerodrome Officer" in column 1, in the corresponding entry in column 2, for the figures "82", the figures and letter "82, 83A" shall be substituted;

(d) against the entry "Aerodrome Officer" in column 1, in the corresponding entry in column 2, for the figures "82", the figures and letter "82, 83A" shall be substituted;

(e) against the entry "Assistant Aerodrome Officer Incharge of Acrodrome" in column 1, in the corresponding entry in column 2, for the figures "82", the figures and letter "82, 83A" shall be substituted;

(ii) In the Second Schedule, after Sl. No. 83 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3
"83A	Rule 81A	To permit entry into Movement area of an aerodrome,"

[No. F. AV.11016/1/72-A/AR/1937(1)/1972.]

S. N. KAUL, Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1972

का०आ० 1426.—वायुयान नियम, 1937 के नियम के उप-नियम (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1111 तारीख 19 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

(i) प्रथम अनुसूची में —

(क) स्तम्भ 1 में "विनियमन और सूचना निदेशक" प्रविष्टि के सामने स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में "12" अंकों के स्थान पर "12, 83क" अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्तम्भ 1 में "हवाई अड्डा नियंत्रक" प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में "82, 89" अंकों के स्थान पर "82, 83क, 89" अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) स्तम्भ 1 में "ज्येष्ठ हवाई अड्डा अधिकारी" प्रविष्टि के सामने स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में "82" अंकों के स्थान पर "82 और 83क" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) स्तम्भ 1 में "हवाई अड्डा अधिकारी" प्रविष्टि के सामने, स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में

"82" अंको के स्थान पर "82 और 83क" अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) स्तम्भ 1 में "हवाई अड्डे का भार साधक सहायक हवाई अड्डा अधिकारी" प्रविष्टि के सामने स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में "82" अंको के स्थान पर "82 और 83क" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) द्वितीय अनुसूची में क्रम संख्या 83 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"83क	नियम 81क	हवाई अड्डे के संचलन, क्षेत्र में प्रवेश अनुज्ञात करने के लिए

[सं० फा० एवी. 11016/1/72-क/एआर/1937(1)/1972]

एन० एन० कौल, उप सचिव ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Community Development)

New Delhi, the 22nd March 1972

S.O. 1427.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby further extend up to 31st August, 1972, the period within which the Commission of Inquiry to look into the affairs and accounts of Bharat Sevak Samaj, appointed by the Government of India in the Department of Community Development *vide* Notification No. 9(2)/68-LKK dated 21st February, 1969, shall make its report to the Central Government.

[No. L.14012/1/72-PC.]

M. RAMAKRISHNAYYA Add. Secy.

कृषि मंत्रालय

(सामुदायिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1972

एस० ओ० 1427.—जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस कालावधि को जिसके भीतर भारत सेवक समाज के मामलों और लेखाओं की जांच करने के लिए भारत सरकार के सामुदायिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 9(2)/68-एल० के० के० दिनांक 21 फरवरी, 1969 द्वारा नियुक्त जांच आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगा, एतद्द्वारा 31 अगस्त, 1972 तक और बढ़ाती है ।

[सं० एल० 14012(1)/72-पी० सी०]

एम० रामकृष्णय्या, अतिरिक्त सचिव ।

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 11th April 1972

S.O. 1428.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby extends the date specified for the purpose of inviting objections and suggestions on the draft of the Sheekakai Powder Grading and Marking Rules, 1971, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) No. S.O. 1210, dated the 20th February, 1971 (*see Annexure*), from the 7th April, 1971 to a date one month from the date of publication of this notification.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules on or before the date so extended will be considered by the Central Government.

ANNEXURE

Rules

Sheekakai Powder Grading and Marking Rules, 1971

1. *Short title and application.*—(1) These rules may be called the Sheekakai Powder Grading and Marking Rules, 1971.

(2) They shall apply to Sheekakai Powder prepared in India.

2. *Definitions.*—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Sheekakai Powder" means the produce obtained by grinding pods of Acacia Concinna;

(b) 'Agricultural Marketing Adviser' means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(c) 'Schedule' means Schedule appended to these rules.

3. Grade designations.—Grade designations to indicate the quality of sheekakai powder shall be as set out in column 1 of Schedule II.

4. *Definition of quality.*—The quality of sheekakai powder indicated by the respective grade designations shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 5 of Schedule II.

5. *Grade designation marks.*—(1) The grade designation marks in the case of sheekakai powder packed in polythene or paper bags shall consist of a design incorporating the number of certificate of authorisation, the word 'Agmark' and the grade approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) The grade designation mark in case of sheekakai powder packed in containers of jute or cloth as also in containers in which sealed polythene bags or paper cortons of graded sheekakai powder are packed, shall consist of a label, specifying the grade designation and bearing the design (consisting of an outline map of India with the word 'Agmark' and the figure of rising sun, with the words 'Produce of India' and भारतीय उत्पाद resembling the one as set out in Schedule I.

6. *Method of Marking.*—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each container in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall also be clearly and indelibly marked on each container, namely:—

(a) Date of packing in code or plain letters.

(b) Lot number, and

(c) Net weight.

(3) An authorised packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container, in a manner approved by the said Officer, provided that the private trade mark does not represent a quality or grade different from that indicated by the grade designation mark affixed to or printed on the container in accordance with these rules.

7. *Method of packing.*—(1) Only sound, new, clean and dry containers, made of Polythene, jute, cloth or paper bags shall be used for packing sheekakai powder and they shall be free from insect infestation or fungus contamination and free from undesirable smell. These shall be closed and sealed in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) When more than one packet is put in a large container, all the packets shall bear Agmark labels and outer container shall also bear Agmark label.

8. *Special condition of Certificate of Authorisation.*—In addition to the conditions specified in rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, the following special conditions shall also be observed by the authorised packers to the satisfaction of the Agricultural Marketing Adviser.

(1) An authorised packer shall provide such facilities as may be necessary to the Inspecting Officers duly authorised by the Agricultural Marketing Adviser in this behalf to discharge their duties under these rules.

(2) An authorised packer shall make such arrangements for testing Sheekakai Powder as may be prescribed and samples of sheekakai powder shall be forwarded to such control laboratory as may be notified from time to time by the Agricultural Marketing Adviser.

SCHEDULE I

(*See* Rule 5)

Design of grade designation mark

SCHEDULE II

(*See* Rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Sheekakai Powder

Product	Moisture (per cent) maximum	Total ash* (per cent) maximum	Acid insoluble ash* (per cent) maximum	General characteristics
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Special	10	5	1	(1) The sheekakai powder shall be prepared by grinding clean soapnut pods (Acacia Concinna) and shall contain not less than 99·0% by weight of such ground powder.
General	15	6	2	(2) When passed through a standard seive of 500 Micron not more than 1·0% shall be retained on the seive.
				(3) The sheekakai powder shall be free from dirt, mould growth, insect infestation and all types of adulterants.

*Expressed on moisture free basis.

[No. F. 13-11/70-C & M]

T. D. MAKHIJANI, Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1972

का० आ० 1428.—कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शीकाकाई पाउडर श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1971 के प्रारूप पर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के भूतपूर्व, खाद्य, कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 1210, तारीख 20 फरवरी, 1971 (उपाबंध देखें), के साथ प्रकाशित विनिर्दिष्ट तारीख को 7 अप्रैल, 1971 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास तक की तारीख तक बढ़ाती है ।

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में इस प्रकार बढ़ाई गई तारीख को या उसके पूर्व किसी भी व्यक्ति से जो भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगें उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

उपाबन्ध

नियम

शिकाकाई पाउडर श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1971

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना** :—(1) इन नियमों को शीकाकाई पाउडर श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1971 कहा जा सकेगा ।

(2) वे भारत में तैयार किये गये शीकाकाई पाउडर पर लागू होंगे ।

2. **परिभाषाय** :— इन नियमों में यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) शीकाकाई पाउडर से 'एकेशिया कोनसिन्ना' की पलियों को पीसकर प्राप्त किया जाने वाला उत्पाद अभिप्रत है ।

(ख) कृषि विपणन सलाहकार से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ।

(ग) 'अनुसूची' से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. **श्रेणी अभिधान**:—शीकाकाई पाउडर की क्वालिटी उपदर्शित करने वाले श्रेणी अभियान वे होंगे जो अनुसूची 2 के स्तंभ 1 में उपवर्णित है ।

4. **क्वालिटी की परिभाषा** :—विभिन्न श्रेणी अभिधानों द्वारा उपदर्शित शीकाकाई पाउडर की क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 से 5 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित हैं ।

5. **श्रेणी अभिधान चिह्न** :—(1) पालिथिन या कागज के थैलों में पैक किये गये शिकाकाई पाउडर की दशा में श्रेणी अभिधान चिह्न एक ऐसे डिजाइन का होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र

की संख्या, एगमार्क शब्द और कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित श्रेणी दी गई होगी :

(2) जूट अथवा कपड़े के आधानों और ऐसे आधानों में, जिनमें श्रेणीकृत शीकाकाई पाउडर के पौलिथिन के सीलबन्द थैले अथवा कागज के डिब्बे पैक किये गये हों, पैक किए गए शीकाकाई पाउडर की दशा में श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और जिसमें अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट डिजाइन के अनुरूप (एगमार्क शब्द के साथ भारत के मानचित्रक की रुपरेखा और और "भारतीय उत्पाद" शब्दों के साथ उगते हुए सूर्य की आकृति से मिलकर बना) डिजाइन होगा ।

6. **चिह्नन की पद्धति.**—(1) श्रेणी अभिधान चिह्न कृषि विपणन सलाहकार अनुमोदित रीति से प्रत्येक आधान पात्र पर सुरक्षित रूप से चिपकाया या अंकित किया जाएगा ।

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त प्रत्येक आधान पात्र पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट एवं अमिट रूप से चिह्नित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) पैकिंग की तारीख, सांकेतिक या सादे अक्षरों में

(ख) लाट संख्या और

(ग) निवल भार

(3) कृषि विपणन सलाहकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्राधिकृत पैकर किसी आधान पात्र पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से चिह्नित कर सकेगा, परन्तु यह प्राइवेट व्यापार चिह्न इन नियमों के अनुसार आधार पर चिपकाये अथवा अंकित किये गये श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी को निरुपित न करता हो ।

7. **पैकिंग की पद्धति.**—(1) शीकाकाई पाउडर की पैकिंग के लिये केवल मजबूत, नये साफ और नमी रहित, पौलीथिन, जूट कपड़े या कागज के थैलों के बने आधान पात्र ही उपयोग में लाये जाएंगे और वे जन्तु आधा, या प्रफूद संदूषण और अवांछनीय गंध से रहित होंगे । वे कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से बंद और सील किए जाएंगे ।

(2) जब किसी बड़े आधान पात्र में एक से अधिक पैकिट रखे जाऐं तो सभी पैकिटों पर एगमार्क लेबल लगा होगा और बाह्य आधान पात्र पर भी एगमार्क लेबल लगाया जाएगा ।

8. **प्राधिकार प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें.**—साधारण श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1937 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त कृषि विपणन सलाहकार के निम्न धान प्रदरूप से निम्नलिखित विशेष शर्तों का भी अनुपालन प्राधिकृत पैकर किया जाएगा ।

(1) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलकाहर द्वारा इस निमित्त समुचित रूप से प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारियों को इन नियमों के अधीन कर्त्तव्य पालन के लिए आवश्यक सुविधायें देगा ।

(2) प्राधिकृत पैकर शीकाकाई पाउडर के परीक्षण के लिए विहित व्यवस्थाएं करेगा, और शीकाकाई पाउडर के नमूने समय-समय पर कृषि विपणन सलकाहर द्वारा अधिसूचित नियंत्रण प्रयोगशाला को अग्रेषित किये जायेंगे ।

अनुसूची 1

(नियम 5 देखिए)

श्रेणी अभिधान चिह्न का डिजाइन

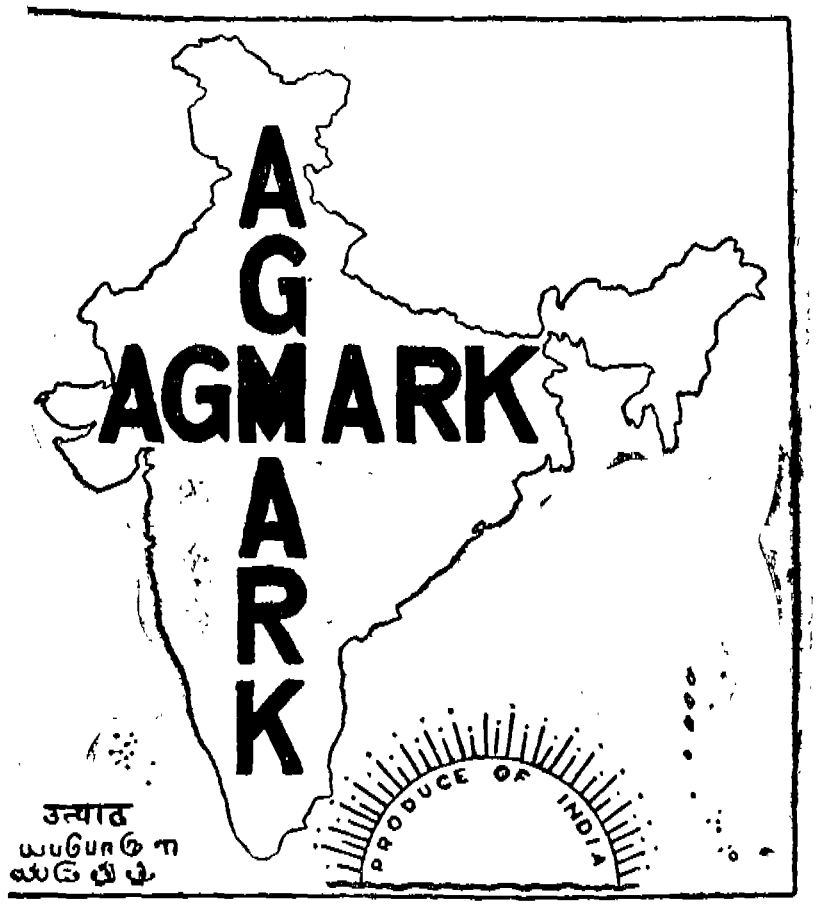

अनुसूची 2

(नियम 3 और 4 देखिये)

शीकाकाई पाउडर के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

उत्पाद	नमी (प्रतिशत) अधिकतम	*कुल भस्म (प्रतिशत) अधिकतम	*अविलेय भस्म (प्रतिशत) अधिकतम	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5
विशेष	10	5	1	(1) शीकाकाई पाउडर स्वच्छ रीठा क्ली (एकेशिया कौनसिन्ना) को पीस कर तैयार किया जायेगा और उसमें ऐसा पिसा हुआ पाउडर वजन के अनुसार 99 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
साधारण	15	6	2	(2) 500 मिक्रोन की मानक छलनी में से छाने जाने पर 1 प्रतिशत से अधिक छलनी में नहीं बचेगा।
				(3) शीकाकाई पाउडर गर्व, फ्यूदि वृद्धि, जन्तु बाधा एवं सभी प्रकार के मिलावट तत्वों से रहित होगा।

*नमी मुक्त आधार पर अभिव्यक्त।

[सं० फा० 13-11/70-निपण०० तथा ऋण०]

टी० डी० माखीजानी, अवर सचिव।

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5593.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार फल उत्पाद आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) यह आदेश फल उत्पाद (संशोधन) आदेश, 1971 कहा जा सकेगा ।

(2) यह प्रथम जनवरी 1972 को प्रवृत्त होगा ।

2. फल उत्पाद आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 में,—

(i) उपखंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गग) "फल मकरंद" से पूरी तरह पके और अच्छे फलों से निकाले गए गूदे या रस से तैयार किया गया पेय अभिप्रेत है ;'

(ii) उपखंड (घ) में,—

(क) मद (V) में, "परोसे जाने के लिए तैयार पेय" शब्दों के पश्चात् "फल मकरंद" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (XIII) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(XIV) फ्रूट सीरियल फ्लेक ;"

(ग) विद्यमान मद (XIV) उसकी मद (XV) के रूप में पुनःसंख्याकित की जाएगी ;

(iii) इस प्रकार संशोधित उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(घघ) "लेबिल" से किसी फल उत्पाद के आधान पर लिखित मुद्रित, छिद्रित, स्टेंसिल कृत, समुद्र-भूत या स्टाम्पित विषय का सप्रदर्शन अभिप्रेत है ;

(iv) उपखंड (ज) में "उन्हें विक्रय के लिए पैक करता है" शब्दों के स्थान पर "उन्हें विक्रय के लिए पैक करता है या लेबिल लगाता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(v) उपखंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ञ) "शर्बत" से कोई गैर-एल्कोहाली मधुरीकृत पेय या सिरप अभिप्रेत है, जिसमें 10 प्रतिशत से कम फलों का रस हो या जो गुलाब, खस, केवड़ा, आदि जैसे फलेतर सुवास से सुवासित हो ।

3. उक्त आदेश के खंड 3 के उपखंड (1) में, मद (1) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(ii) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) का एक प्रतिनिधि"

4. उक्त आदेश के खंड 5 में—

(i) उपखंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) निम्नलिखित फीसें, जो समुचित फीसें हैं, उपखंड (1) के अधीन एक अवधि या उसके भाग के लिए संदेय होगी, अर्थात् :—

(क) गृह मापमान	100 रुपए
(ख) लघु मापमान क 1	600 रुपए
(ग) लघुमापमान क 2	400 रुपए
(घ) लघुमापमान ख	200 रुपए
(ङ) बहत मापमान	1000 रुपए
(च) स्लिब्लर	500 रुपए"

(ii) उपखंड (3) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां उपखंड (4) के अधीन अनुज्ञप्ति न दी जाए या जहां अनुज्ञप्ति फीस मंजूर शुदा अनुज्ञप्ति के लिए संदेय रकम के अधिक्य में संदत्त की जाए वहां, यथास्थिति, संदत्त अनुज्ञप्ति फीस या अधिक्य की रकम आवेदक को प्रतिदत्त कर दी जाएगी ।"

5. उक्त आदेश के खंड 8 के उपखंड (1) के मद (घ) में; "ऐसा फल उत्पाद" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"कोड संख्या ऐसी होगी कि वह पढ़ी जा सके और अंग्रेजी या हिन्दी संख्यांकों या वर्णमाला या दोनों में दी जाएगी । अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व, विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक कोड संख्या अनुज्ञापन अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और उसमें, अनुज्ञापन अधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा" ।

6. उक्त आदेश के खंड 11 के उपखंड (2) में, "शब्द "सश्लिष्ट" इतने स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाएगा जितना कि उत्पाद का नाम' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"सश्लिष्ट" शब्द , जहां भी इसका प्रयोग किया जाए, इतना स्पष्ट और इसके अक्षरों का आकार और

रंग वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उत्पाद के नाम के लिए प्रयुक्त किया जाता हो और यह ऐसे नाम के ठीक पूर्व आना चाहिए ।'

7. उक्त आदेश के खण्ड 16 में, मद (ii) में, "दो सौ पौंड" शब्दों के स्थान पर "एक सौ किलोग्राम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त आदेश का प्रथम अनुसूची में--

(i) प्ररूप 'क' में,--

(क) मद 2 और 3 के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

"2. कारखाने /फर्म* का पता

3. उन फल उत्पादों का वर्णन जिनका/(जिन पर आवेदक विनिर्माण करना/ फिर से लेबिल लगाना चाहता है* ।"

(ख) मद 8 के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:--

"8. पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित/फिर से लेबिल लगाए गए फल उत्पादों का कुल मूल्य ।";

(ग) अन्त में, निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात:--

"*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।" ;

(ii) प्ररुप 'ख' में,--

(क) मद 2 के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:--

"2. विनिर्मित करने/फिर से लेबिल लगाने के लिए प्राधिकृत परिसरों का पता*।";

(ख) सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

विधिमान्यकरण और नवीकरण

विधिमान्यता की अवधि	विनिर्मित करने/फिर से लेबिल लगाने के लिए प्राधिकृत फल उत्पादों का नाम	अनुज्ञप्तिधारी का प्रवर्ग	संदत्त अनुज्ञप्ति फीस	अनुज्ञापन अधिकारी के हस्ताक्षर

9. उक्त आदेश की द्वितीय अनुसूची में,--

(1) भाग 1 (क) में,--

(i) पैरा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

"3. फल उत्पादों के विनिर्माण के लिए अनुमोदित उपस्कर और विनिर्माण परिसर फल उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपायकर अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए नीचे दी गई शर्तों के अधीन के सिवाए प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे:

यदि अनुज्ञप्ति परिसर का प्रयोग फल उत्पादों और मछली, मांस और अण्डा उत्पादों दोनों के विनिर्माण के लिए किया जाए तो जब मछली, मांस और अण्डा उत्पादों से फल उत्पादों में परिवर्तन किया जाए तब कम से कम एक मास का अन्तराल होगा ।

स्पष्टीकरण :

मछली, मांस और अण्डा उत्पादों से फल उत्पादों में परिवर्तन की प्रस्तावित तारीख संबंधित प्रादेशिक अधिकारी को लिखित रुप में प्रज्ञापित की जाएगी और स्टेशन बाह्य कारखानों की दशा में, प्रज्ञापना रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा देनी होगी ।

(ii) पैरा 13 में, "कुटीर मापमान प्रवर्ग" से संबद्ध प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:--

"गृह मापमान प्रवर्ग.....वर्ष में एक बार" ।

(2) भाग 1 (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित भाग प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"भाग 1 (ख)

कारखानों को निम्न प्रकार से प्रवर्गों में रखा जाएगा:

(क) **बृहत मापमान**.--एक मीटरिक टन प्रति दिन से अधिक संस्थापित क्षमता वाला या 250 मीटरिक टन से अधिक कुल वार्षिक उत्पादन वाला कारखाना ।

(ख) **लघु मापमान**.--एक मीटरिक टन प्रतिदिन तक की संस्थापित क्षमता और 250 मीटरिक टन कुल वार्षिक उत्पादन वाले कारखाने ।

(ग) **गृह मापमान**:--डिब्बा बंद सब्जियों के सिवाए, 10 मीटरिक टन से अनधिक कुल वार्षिक फल उत्पादन वाले कारखाने ।"

बृहत और लघु मापमान के कारखानों को नीचे यथा परिभाषित क 1, क 2, और ख उप-समूहों में और आगे समूहीकृत किया जा सकता है.

प्रवर्ग क 1 : ताजा फलों और सब्जियों से बनाए गए फल उत्पादों के विनिर्माण के अनुज्ञप्त कारखाने ।

प्रवर्ग क 2 : अनन्यतः परिरक्षित उत्पादों से बनाए गए फल उत्पादों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्त कारखाने ।

प्रवर्ग ख : संश्लिष्ट गिरपों और संश्लिष्ट सिरके के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्त कारखाने ।

ऊपर वर्णित प्रवर्गों के अधीन अनुज्ञप्त कारखाने निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे :—

जल :—

प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी कम से कम एक किलोलिटर पेय जल की व्यवस्था करेगा और उसकी उपलभ्यता उत्पादन के अनुसार पर्याप्त रुप से बढ़ायी जाएगी । प्रसंस्करण हाल में खुले पाइप से बहता हुआ जल उपलभ्य किया जाएगा ।

भंडारकरण स्थान की अपेक्षाएं:—

ताजा फलों, सब्जियों, तैयार उत्पादों और अन्य कच्ची सामग्री के भण्डारकरण के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी ।

भण्डार और कार्यालय स्थान को अपवर्जित कर के, विनिर्माण परिसर का न्यूनतम स्थान—

	प्रवर्ग क 1	प्रवर्ग क 2	प्रवर्ग ख
*1. वृहत मापमान :	350 वर्ग मीटर	175 वर्ग मीटर	100 वर्ग मीटर
लघु मापमान :	150 वर्ग मीटर	100 वर्ग मीटर	50वर्ग मीटर

*(मशीनरी से घिरा हुआ क्षेत्र इस क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा)

3. गृह मापमान : 25 वर्ग मीटर

तकनीकी कर्मचारी और प्रयोगशाला की अपेक्षाएं :—

वृहत मापमान :—

फल उत्पादों का विनिर्माण ऐसे रसायनज्ञ द्वारा जिसके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से एक होनी चाहिए, पर्यवेक्षित किया जाएगा :—

(क) फल परिक्षण कारखाने में कम से कम एक वर्ष के अनुभव सहित खाद्य प्रौद्योगिकी या रासायनिक इंजीनियरी के साथ बी० एस सी० (प्रौद्योगिकी) ।

(ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, या कालामासरी पालिटेक्निक या केरल गवर्नमेंट पालिटेक्निक से फल परिक्षण डिप्लोमा सहित बी० एस सी० ।

(ग) एक विषय के रूप में रसायन या कृषि सहित बी० एससी० और फल और सब्जी परिक्षण कारकों में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

कारखाने में, इस आदेश की द्वितीय अनुसूची के अधीन अधिकथित विशिष्टियों के अनुसार, एक प्रयोगशाला होगी जिसमें सभी सामान होगा, जिसका भू-क्षेत्र 50 वर्ग मीटर होगा तथा जिसमें फल-उत्पादों के विश्लेषण के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी ।

लघु मापमान:—

फल उत्पादों के विनिर्माण ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से एक होगी, पर्यवेक्षित किया जाएगा :—

(क) एक विषय के रूप में रसायन या कृषि सहित बी० एस सी०;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से, फल परिरक्षण में कम से कम तीन मास की अवधि के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र ;

मशीनरी और उपस्कर की बाबत न्यूनतम अपेक्षाएं

क्रम संख्या	संक्रियाएं	लघु मापमान	वृहत मापमान
1.	(क) कच्ची सामग्री की धुलाई	कृत्रिम पेंदी सहित दो आयाताकार सीमेंट या एल्यूमिनियम धातु के टैंक विमाएं-1×0.75×0.75 मीटर	कृत्रिम पेंदी सहित तीन या अधिक आयाताकार सीमेंट या एल्युमिनियम के टैंक विमाएं-1×0.75×0.75 मीटर या धुलाई की मशीन
	(ख) बोतलों की धुलाई	1. बोतलें धोने की मशीन 2. बोतलें रखने के रैक	1. बोतलें धोने की मशीन 2. बोतलें रखने और लाने-लेजाने के लिए ट्रालियां ।

क्रम संख्या	संक्रियाएं	लघु मापमान	वृहत मापमान
2.	फल और सब्जियों को तैयार करना	1. मेज जिसके ऊपर का तख्ता 4 वर्ग मीटर क्षेत्र का एल्युमिनियम या जंगरोधी इस्पात या जंग न लगने वाली सामग्री का हो	1. एल्युमिनियम या जंगरोधी इस्पात या जंग न लगने वाली सामग्री की मेज जिसका क्षेत्र-फल 10 वर्ग मीटर हो या जिसके पर्याप्त कंवेयर बेल्ट हो
		2. जंगरोधी इस्पात के बने पोलिंग, स्लाइसिंग, ट्रिमिंग और कोटरिंग चाकू	2. जंगरोधी इस्पात के बने कोट्रिक्यूरिंग और कटिंग मशीन उपस्कर
		3. जहां संसाधन और लीचिंग के लिए लकड़ी के वेट या सीमेंट के टैंक प्रयुक्त किए जायें वहां ये समुचित रूपसे ढके हुए होने चाहिए	3. संसाधन और लीचिंग के लिए उचित ढकनों सहित लकड़ी के वेट और सीमेंट के टैंक
		4. एल्युमिनियम या जंगरोधी इस्पात की 12 से अन्यून तश्तरियां	4. एल्युमिनियम या जंगरोधी इस्पात की 50 से अन्यून तश्तरियां
3.	रस निकालना गूदा निकालना और मिश्रन	1. जूस एक्स्टैक्टर और/या बास्केट प्रेस या रोजिंग उपस्कर	1. शक्ति-चालित एक्सटैक्टर या हाइड्रालिक प्रेस
		2. जंगरोधी इस्पात की या एल्युमी-नियम की चलनी	2. गूदा निकालने की मशीन
		3. एल्युमिनियम या जंगरोधी इस्पात के 100 लिटर से अन्यून धारिता के ड्रम	3. जंग न लगने वाले जंगरोधी इस्पात के टैंक जिनकी कुल धारिता 500 लिटर से कम न हो
		4. जंगरोधी इस्पात या एल्युमिनियम के बकेट	
		5. टमाटर उत्पादों और आम के गूदे के लिए मलपर	
4.	ऊष्मा संसाधन	1. स्टीम जाकेट देगचियों सहित बायलर या गैस कुकिंग	1. बायलर
		2. थर्मामीटर और हाईड्रोमीटर	2. स्टीम जाकेट देगचियां
		3. रिफ्रेक्टोमीटर	3. थर्मामीटर
			4. परिरक्षकों के लिए सुग्राह्यतुला
			5. रिफ्रेक्टोमीटर
			6. अर्क निकले हुए सिरके लिए पास्तुरीकर्ता
5.	भरना और मुद्राबंद करना	1. बोतलें भरने की मशीन	1. बोतलें भरने की मशीन
		2. बोतलों को मुद्राबंद की मशीन	2. बोतलों को मुद्राबंद करने की मशीन
		3. क्राउन कार्क लगाने की मशीन	3. भारी कार्क लगाने की मशीन
		4. वजन करने की तुला	4. वजन करने की तुला
6	बिब्बा बंद और बोतल बंद करने के लिए वायु-निष्कासन, मुद्राबंद करना और संसाधन	1. वायु–निष्कासन के लिए छेदों वाल टैंक	1. वायु-निष्कासन बाक्स
		2. अर्ध-स्वचालित इक्सल-सीमर	2. अर्ध-स्व-चालित इक्सल-सीमर
		3. कूलिंग टैंक	3. कूलिंग टैंक (पर्याप्त धारिता)
		4. न्यूनतम रिटार्टिंग धारिता 100 क $2\frac{1}{2}$ कैन प्रति चार्ज	4. रिटार्टिंग धारिता 250 क $2\frac{1}{2}$ कैन प्रति चार्ज
		5. प्रेशर कैन टैस्टर	4. प्रेशर कैन टैस्टर

प्रवर्ग के 2 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के विनिर्माताओं के लिए फलों के लिए अपेक्षित मशीनरी और उपस्कर की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं ।

(3) भाग II में,—

(i) प्रथम स्तंभ में "सर्वेक्षण और आसव-मकरंद से भिन्न मकरन्द" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"सर्वेक्षण ।" ;

(ii) चतुर्थ स्तम्भ में "5" अंक के स्थान पर "10" अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(iii) अन्त में निम्नलिखित पाद-टिप्पण जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"स्लाइम जूस वासू परोसने के लिए तैयार पेयों को छोड़ कर, फलों के रस का न्यूनतम प्रतिशत 6। रहेगा"

(4) भाग II के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग II (क)

फल मकरद के लिए विनिर्देश

उत्पाद	किस्म	विशेष लक्षण		साधारण लक्षण
		उत्पाद में कुल विलेय घनों का न्यनतम प्रतिशत	अन्तिम उत्पाद में फल रस का न्यूनतम प्रतिशत	
1	2	3	4	5
फल मकरद (संतरे और अनानास मकरंद को अपवर्जित करके)	कोई उपयुक्त प्रकार या किस्म	15	20	मंकरद पूरे पके, अच्छे फलों के गूदों से तैयार किए जायेंगे, तैयार उत्पाद में अच्छी सामग्री, एक समान रंग और गूदे के अन्य प्रभाग या फल के लिए स्वाभाविक अन्य सेलुलर पदार्थ होगा । गूदे या जल के साथ केवल जो पदार्थ मिलाया जा सकता है वह है जल ,शकरा, इन्वर्ट शुगर या लिक्विड ग्लुकोस, एस्कार्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड । उत्पाद के साइट्रिक एसिड और एल्कोहाल अन्तर्वस्तु के रूप में अम्लता क्रमश :1.5 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । इसमें कोई परिरक्षक, कृत्रिम, रंग या मुधरकर्ता पदार्थ नहीं होना चाहिए । तैयार उत्पादों में फल का लक्षणगत स्वाद होना चाहिए और यह जलने के या आपत्तिजनक दागों और स्वाद से युक्त होना चाहिए । यह लार्वा और अन्य फल कीटों से मुक्त होना चाहिए । उत्पाद में डिब्बाबंद किए जाने पर समुद्र स्तर पर कोई ठोस दाब नहीं होना चाहिए और 37° सें० पर एक सप्ताह तक उष्मायन किए जाने पर जीवाणु पैदा होने के कोई चिह्न नहीं होने चाहिए ।"
संतरा और अनानास मंकरद	कोई उपयुक्त प्रकार या किस्म	15	40	

(5) भाग IV में,—

(i) सारणी में, चतुर्थ स्तंभ में, "सार" शब्द के पश्चात् "रस (कम से कम 10%)" शब्द, कोष्ठक अंक और संक्षेपाक्षर अन्तःस्थापित किए जायेंगे ;

(ii) पाद-टिप्पण में, 'संश्लिष्ट सिरपों पर स्पष्ट लिखा जाएगा कि "इन में कोई फलों का रस नहीं है', शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

'यदि संश्लिष्टसिरप के रूप में घोषित उत्पाद में ऊपर यथाविनिर्दिष्ट विहित फलों का रस नहीं हो, तो उत्पाद पर "इस में कोई फलों का रस नहीं है" स्पष्ट रूप से चिन्हित होना चाहिए ।"

(6) भाग vii में, सारणी के नीचे पाद-टिप्पण में, निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा अर्थात् :—

"संश्लिष्ट जेली के आन से लेबिल पर निम्नलिखित सहजदृश्य रूप से अंकित होना चाहिए, अर्थात् :—

'(1) संश्लिष्ट जेली——————————सुवासित (संबद्ध सुवास का नाम खाली स्थान में लिखा जाना चाहिए); और

(2) उत्पाद किसी फल से बना नहीं है ।' "

(7) भाग X में, अन्तिम स्तंभ में—

(i) "अनुज्ञात परिरक्षक" शब्दों के स्थान पर "अनुज्ञात रंग और और परिरक्षक)" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(ii) अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जायेंगे, अर्थात् :—

"हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेयक्षार 0.5% डब्ल्यू/डब्ल्यू से अधिक नहीं होगा ।"

(8) भाग XIII में तृतीय स्तंभ में, "1.2%" अंकों और संक्षेपाक्षरों के स्थान पर "1.0%" अंक और संक्षेपाक्षर प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(9) भाग XIII (क) में,—

(i) शीर्षक में, "सोयाबीन सास" शब्दों के पश्चात्, "और टमाटर सास" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे ;

(ii) अन्तिम स्तंभ में, "अनुज्ञात रंग" शब्दों के पश्चात् "(लाल या लाल रंग की किसी पेड से भिन्न)" कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे ;

(iii) पाद-टिप्पण में "लेबिल पर" शब्दों के स्थान पर "लेबिल पर और लेबिल पर टमाटरों की कोई तस्वीर नहीं होगी" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(10) भाग XIV में,—

(i) तृतीय स्तंभ में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"अर्क निकला हुआ सिरका——————3.75 ग्राम एसिटिक अम्ल प्रति 100 मि० लि०

संश्लिष्ट सिरका——————3.75 ग्राम एसिटिक अम्ल प्रति 100 मि० लि०;"

(ii) अन्तिम स्तंभ में, प्रविष्टि 3 में, "आसिटियस आक्साइड" शब्दों के स्थान पर "संख्या की मात्रायें" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(11) भाग 16 में, अन्तिम स्तंभ में, "लहसुन" शब्द के पश्चात् "बन्जोइक अम्ल" शब्द जोड़ दिए जायेंगे ।

(12) भाग 18 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 18 (क)

आम्र सीरियल फ्लेक्स के लिए विनिर्देश

उत्पाद	किस्म	लक्षण	साधारण लक्षण
आम्र सीरियल फ्लेक्स	समुचित किस्म का फल	नमी 2.5 प्रतिशत से अनधिक / अम्ल में अविलय क्षार 0.5 प्रतिशत से अनधिक / प्रोटीन 3.0 प्रतिशत	उत्पाद कीट या फंगस से मुक्त साफ अच्छे आमों से तयार किया जाएगा केवल जो पदार्थ मिलाये जा सकते हैं वे हैं फल का गूदा, गेहूं की स्टार्च सुक्रोस, ग्लुकोस, सोडियम बाइकारबोनेट और पक्टिन ।

1	2	3	4
		से अन्यून 1 स्टार्च 250 प्रतिशत से अनधिक	उत्पाद में स्वाद और सुरसता फल के लक्षणानुसार होनी चाहिए। उत्पाद भुरभुरा होना चाहिए किन्तु सख्त या चमड़े जैसा नहीं इसमें कोई संश्लिष्ट सुरसकारक नहीं मिलाया जाएगा।

प्रयुक्त फल की किस्म और संयोजन लेबिल पर घोषित किया जाएगा।

(13) भाग 20 में, पैरा 2 में, मद (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(घ) विनिर्माता या ब्रांड स्वामी का नाम और पता"।

(14) भाग 21 में, सारणी में :—

(i) द्वितीय और तृतीय स्तंभों में, क्रम सं०"1-सीसा" से संबंधित प्रविष्टियों में, मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"द्वितीय स्तंभ	तृतीय स्तंभ
"(iii) (क) मृदुपेय संकेन्द्रणों को अपवर्जित करके	शून्य";

(ii) क्रम सं० "2 तांबा से संबंधित प्रविष्टियों में,

(क) द्वितीय स्तंभ में, मद (i) में, "सम्मिलित करके" शब्दों के स्थान पर "अपवर्जित कर के" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) तृतीय स्तंभ में, "70" अंक के स्थान पर, "50" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या "3 संखिया" से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, तृतीय स्तंभ में,—

(क) "आर्सिनियस आक्साइड-0.66" शब्द और अंक लुप्त कर दिए जायेंगे ;

(ख) "अर्सिनियम आक्साइड—1.5" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1.00 पी० पी० एम" अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) क्रम स० "4.टीन" से संबंधित प्रविष्टियों में, द्वितीय और तृतीय स्तंभों में, मद (1) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जायगी, अर्थात्:—

द्वितीय स्तंभ	तृतीय स्तंभ
"(i क) मृदु पेय संकेन्द्रणों को अपवर्जित करके	100.0" ;

(v) क्रम संख्या "5. जस्ता" से सम्बन्धित प्रविष्टियों में,द्वितीय और तृतीय स्तंभों में, मद (ii) और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

द्वितीय स्तंभ	तृतीय स्तंभ
(ii) "इस आदेश के अन्तर्गत आने वाले फल उत्पाद	19 पी० पी० एम."

(15) भाग 22 में,—

(i) पैरा (1) में "खाद्य वस्तु" शब्दों के स्थान पर "फल उत्पाद" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैरा 2 में, सारणी में,—

(क) लाल रंग और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों से संबंधित मद 1 के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"1 लाल——पोन्सियु 4 आर——185 एजो
कारमोयसीन———— 17.9 एजो
तेज लाल ई ———182 एजो
अमरंथ————184 एजो
इरिथ्रोसीन———773 एक्जेन्थीन" ;

(ख) नीले रंग और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों से संबंधित मद 3 के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात् :—

"3 नील——इंडिगो कारमाइन————1180 इंडिगायड";

(ग) काले रंग और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों से सम्बन्धित मद 4 लुप्त कर दी जाएगी।

(iii) पैरा (3) में, "0.46" अंकों के स्थान पर "0.20" अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

(16) भाग 23 में,—

(i) "नीचे सूचीगत फल उत्पादों में केवल एक परिरक्षक प्रयुक्त किया जाएगा—"

शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"विभिन्न फल उत्पादों में प्रयुक्त किए जाने के लिए अनुज्ञात अलग अलग परिरक्षकों की मात्राएं नीचे की सारणी में यथावर्णित होनी चाहिए ;

(ii) सारणी में,—

(क) मद 1 से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, तृतीय स्तंभ में, "3,000" अंकों के स्थान पर "5,000" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) मद 7 से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, तृतीय स्तंभ में "50" अंक के स्थान पर, "350" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) मद 9 और 10 से सम्बन्धित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी । अर्थात् :—

9. फलों और सब्जियों से बने आचार और चटनी	सल्फर डाय आक्साइड*	——	100
	या		
	बेन्जोइक अम्ल	——	250
10. टमाटर और अन्य साम	——	बेंजोइक अम्ल	—— 750"

(घ) सारणी के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"*यदि सल्फर डायाक्साइड का प्रयोग अचारों और चटनियों में परिरक्षक के रूप में किया जाता है तो उत्पाद टीन आधानों से भिन्न आधानों में पैक किया जाना चाहिए ।

स्पष्टीकरण:—उन फल उत्पादों की दशा में जिन में दो विभिन्न परिरक्षकों का प्रयोग अनुज्ञात किया गया है,

इन दो परिरक्षकों का मिश्रण भी इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रयुक्त किया जा सकता है कि इस प्रकार प्रयुक्त परिरक्षक की मात्रा पूर्वोक्त सारणी के तृतीय स्तंभ में उस परिरक्षक के लिए विहित भागों में से भागों की ऐसी संख्या से अधिकन हो जो उस अनुपात के आधार पर जिसके अनुसार ऐसे परिरक्षक मिश्रित किए जायें, निकाली जाए ।"

[सं० 21/31/71-तक 1]

जी० सी० एन० चैहल, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF COMMUNICATION

(P. & T. Board)

New Delhi, the 24th April 1972

S.O. 1429.—In exercise of the powers conferred by Sections 31 and 32 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Ninth Amendment), Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 72 of the Indian Post Office Rules, 1933, in Sub-Rule (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that articles containing Government currency notes or bank notes or gold coin or bullion or gold ornaments or articles of gold or any combination of these shall be insured for the actual value of the contents."

[No. 12-3/71-CI.]

B. SRINIVASAN,
Sahayak Mahanideshak (M).

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 1972

एस० ओ० 1429.—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 31 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय डाकघर (नवां संशोधन) नियम 1972 कहे जायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय डाकघर नियम, 1933 के नियम 72 के उपनियम (1) में द्वितीय परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"बशर्ते कि वे वस्तुएं जिनमें सरकारी मुद्रा नोट अथवा बैंक नोट अथवा सोने के सिक्के अथवा बुलियन अथवा सोने के आभूषण अथवा सोने की वस्तुएं अथवा इनके कोई वस्तु हो तो वे अन्तर्वस्तु के वास्तविक मूल्य के बराबर बीमा की जायेगी" ।

[सं० 12-3/71-सी-1]

बी० श्रीनिवासन,
सहायक महानिदेशक (एम०)

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

New Delhi, the 14th March 1972

S.O. 1430.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum S.O. No. 1589 dated 31st March, 1971 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas, the Competent Authority, has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to his notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further, in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from Road BDW-BDI to G.G.S.I.

STATE : Gujarat	DIST : Kaira	TALUKA : Matar		
Village	Survey No.	Hectare	Are	P. Are
NAWAGAM	753/1	0	2	75
	754	0	11	00
	756	0	6	15
	746	0	2	00

[No. 11(4)/71-Lab.&Legis.]

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1972

का० आ० 1430.—यत: पैट्रोलियम, पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1589 तारीख 31-3-1971 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने, सभी बंधकों से मुक्त रूप मे, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

सड़क बी० डी० डब्ल्यू०-बी० डी० आई० से जी० जी० एस० आई० तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात	जिला : केरा		तालुका : मातार	
गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए० आर० ई०	पी० ए० आर० ई०
नवागांव	753/1	0	2	75
	754	0	11	00
	756	0	6	15
	746	0	2	00

[सं० 11(4)/71-लेबर एण्ड लेजिस]

S.O. 1431.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 1683 dated 31st March, 1971 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas, the Competent Authority, has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further, in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Laying Pipeline from D.S. BEF to G.G.S. Line

STATE : Gujarat DIST : Kaira TALUKA : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	P. Are
NAWAGAM	468	0	7	75
	469/2	0	3	75
	470/2	0	1	10

[No. 11(4)/ 71-Lab.&Legis.]

I. M. SAHAI, Dy. Secy.

का० आ० 1431.—यतः पैट्रोलियम, पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ०सं० 1683 तारीख 31-3-71 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बंधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

डी० एस० बी० ई० एफ० से जी० जी० एस० लाइन तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : केरा तालुका : मातार

ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए० आर० ई०	पी० ए० आर० ई०
नवागांव	468	0	7	75
	469/2	0	3	75
	470/2	0	1	10

[सं० 11(4)/71-लेबर एण्ड लेजिस]

इन्द्र मोहन सहाय, उप सचिव ।

New Delhi, the 22nd March 1972

S.O. 1432.—In exercise of the powers conferred under Section 8 of the Oilfields (Regulation & Development) Act, 1948, the Central Government hereby directs that subject to its control, the powers exercisable by a State Government under the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 (as amended from time to time), framed under the said Act, shall also be exercisable, in any Union Territory of Delhi, the Andamans and Nicobar Islands, The Lacadive, Minicoy and Amindivi Islands, Dadra & Nagar Haveli, Goa, Daman & Diu, Pondichery, Chandigarh, Mizoram and Arunachal Pradesh by the Administrator of the respective Union Territory.

[No. 13(4)/70-Lab.&Legis.]

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1972

का० आ० 1432.—तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1958 के खण्ड 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उसके नियंत्रण के अधीन, उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत रचित पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 ('जिसका समय समय पर संशोधन किया गया था) के अन्तर्गत एक राज्य सरकार द्वारा प्रयोज्य शक्तियां, दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लकाद्वीप, मिनिकाय एवं अमिनदिवि. दादर तथा नागर हवली, गोआ, दमनद्विव, पांडिचेरी (चण्डीगढ़ मिजोरम और अरुणांचल प्रदेश के उनके संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा भी प्रयोग की जायेंगी।

[सं० 13(4)/70-लेब० एण्ड लेजिस०]

New Delhi, the 24th March 1972

S.O. 1433.—Where by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3522 dated 30th August, 1971 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas, the Competent Authority, has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And further, in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM D. S. K-151 To G.G.S.V.

State : Gujarat Dist : Mehsana Tal : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	P.Area
ISAND	583/1	0	00	96
	582	0	7	25
	581/5	0	3	17
	581/4	0	2	81
	581/3	0	3	79
	581/9	0	2	32
	581/2	0	2	68
	635/6	0	6	47
	640	0	9	03
	639/2	0	1	83
	638	0	9	15
	68	0	9	90
	669	0	8	91
	671	0	6	34
	676	0	14	88

[No. 11(4)/71-Lab.&Legis.]

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1972

का०आ० 1433.—यतः पैट्रोलियम, पाइप लाइन (भमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० स० 3522 तारीख 30-8-71 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिओं के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृति गैस आयोग में, सभी बंधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

डी० एस० के०-151 से जी० जी० एस० वी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : महसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	पी० ए आर ई
इसन्द	583/1	0	00	96
	582	0	7	25
	581/5	0	3	17
	581/4	0	2	81
	581/3	0	3	79
	581/9	0	2	32
	581/2	0	2	68
	635/6	0	6	47
	640	0	9	03
	639/2	0	1	83
	638	0	9	15
	668	0	9	90
	669	0	8	91
	671	0	6	34
	676	0	14	88

[सं० 11(4)/71-लेबर एण्ड लेजिस०]

S.O. 1434.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3523 dated 30th August, 1971 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas, the Competent Authority, has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And,further,in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of resting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WELL No. 154 TO G.G.S. V

State : Gujarat Dist : Mehsana Tal : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	P.Are.
OLA	363/1	0	3	70
	378	0	13	85
	376	0	5	43
	377/Paiki	0	13	88
ISAND	660	0	23	18
	661/1	0	0	50
	661/2	0	6	22
	661/3	0	1	46
	661/4	0	13	18
	662	0	9	68
	663/Paiki	0	1	32
	663/1	0	10	03
	674/1	0	7	32
	673	0	3	54
	672	0	5	35
	676	0	8	71
	681	0	2	32
	682	0	5	00

[No. 11(4)/71-Lab.&Legis.]

का० आ० 1434.—यतः पैट्रोलियम, पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3523 तारीख 30-8-71 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बंधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कुओं संख्या 154 से जी० जी० एस० 5 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : महसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	पी० ए आर ई
ओला	363/1	0	3	70
	378	0	13	85
	376	0	5	43
	377/पैकी	0	13	88
इसन्द	660	0	23	18
	661/1	0	0	50
	661/2	0	6	22
	661/3	0	1	46
	661/4	0	13	18
	662	0	9	68
	663/पैकी	0	1	32
	663/1	0	10	03
	674/1	0	7	32
	673	0	3	54
	672	0	5	35
	676	0	8	71
	681	0	2	32
	682	0	5	00

[सं० 11(4)/71—लेबर० एण्ड लेजिस०]

S.O. 1435.—Whereas by a notificaton of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3524 dated 30th August, 1971 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas, the Competent Authority, has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines.

And further, inexercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free ffom all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WELL No. 142 TO G.G.D. VII

State: Gujarat Dist : Gandhinagar

Tal : Gandhinagar

Village.	Survey No.	Hectare	Are.	P. Are.
TITODA	869/1	0	4	71
	V. P. Cart track	0	0	31
	874/1 & 2	0	6	66
	875	0	4	33
	885	0	4	20
	884	0	6	35
	883	0	7	46
	898 & 899	0	18	11
	919/2	0	5	00
	919/1 & 920	0	5	61
	938	0	10	98
	939	0	0	50
	940/2	0	9	83
	941	0	10	49
	V. P. Cart track	0	0	37
	958	0	2	14
	957	0	19	76
	960	0	1	00
UVARSAD	1211	0	2	92
	1212	0	3	42
	1210	0	17	94
	1198	0	28	55
	1209	0	1	71
	V. P. Cart track	0	0	50
	1199	0	0	50
	1208	0	17	45
	1200	0	19	51
	1204	0	0	50
	1205	0	5	98
	V. P. Cart track	0	0	56
	1180/Paiki	0	26	35
	1181/1/Paiki	0	12	63
	1183/1/Paiki	0	14	51
	V.P. Cart track	0	0	50
	1147/1	0	9	15
	1149/1/Paiki	0	26	26
	V. P. Cart track	0	0	50
	1109/Paiki	0	5	61
	1108	0	4	76
	1107	0	10	68

[No. 11(4)/71-Lab.&Legis.]

B. R. PRABHAKAR, Under secy.

का० आ० 1435.—यतः पैट्रोलियम, पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3524 तारीख 30-8-71 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिओं के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बंधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कुआं संख्या 142 से जी० जी० एस० 7 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : गांधीनगर तालुका : गांधीनगर

गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	ए आर ई	पी० ए० आर० ई०
टिटोडा	869/1	0	4	71
	वी०पी० कार्टट्रैक	0	0	31
	874/1 व 2	0	6	66
	875	0	4	33
	885	0	4	20
	884	0	6	35
	883	0	7	46
	898 व 899	0	18	11
	919/2	0	5	00
	919/1 व 920	0	5	61
	938	0	10	98
	939	0	0	50
	940/2	0	9	83
	941	0	10	49
	वी०पी० कार्टट्रैक	0	0	37
	958	0	2	14
	957	0	19	76
	960	0	1	00
उवरसाड	1211	0	2	93
	1212	0	3	42
	1210	0	17	94
	1198	0	28	55
	1209	0	1	71
	वी०पी० कार्टट्रैक	0	0	50
	1199	0	0	50
	1208	0	17	45
	1200	0	19	51
	1204	0	0	50
	1205	0	5	98
	वी०पी० कार्टट्रैक	0	0	56
	1180/पेकी	0	26	35
	1181/पेकी	0	12	63
	1183/1/पेकी	0	14	51
	वी०पी० कार्टट्रैक	0	0	50
	1147/1	0	9	15
	1149/1/पेकी	0	26	26
	वी०पी० कार्टट्रैक	0	0	50
	1109/पेकी	0	5	61
	1108	0	4	76
	1107	0	10	68

[सं० 11(4)/71-लेबर० एण्ड लेजिस०]

वी० आर० प्रभाकर, अवर सचिव ।

New Delhi, the 10th April, 1972

S. O. 1436—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site No. 101 to G.G.S.V, in Kalol oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of the section (1) of section 7 of the said Act, on 22-12-1970.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Rules, 1963 the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FROM D.S. 101 to GGSV

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Govt. of India Gazette	Date of termination of operation
PETROLEUM & CHEMICALS. . .	CHHATRAL	3773	16-10-1971	22-12-1970

[No. Prodn/DDN/61(1)/71]

नई दिल्ली, 10 अप्रैल 1972

का० आ० 1436—यत : संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के कलोल क्षेत्र में व्यधन स्थल संख्या 101 से जी०जी० एस०-V तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है ।

और यत : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 2-12-70 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की धारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट संक्रिया को पर्यवसित कर दिया है ।

अब, अत : पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को, ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

व्यधन स्थल 101 से जी जी एस V तक पाइपलाइन की संक्रिया का पर्यवसान :—

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पैट्रोलियम और रसायन	छत्त ाल	3773	16-10-71	22-12-70

[संख्या प्रोडक्शन/डी० डी० एन०/61(i)/71]

S.O. 1437—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site Kadi-11 to Kadi-4 in Kalol oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of the section (1) of section 7 of the said act on 8-11-1971.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroloum Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Rules, 1963 the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FROM D.S. KADI-11 to KADI-4

Name of the Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Govt. of India Gazette	Date of termination of operation
PETROLEUM & CHEMICALS	KADI	3776	16-10-1971	8-11-1971

[No. Prodn/DDN/61(1)/71]

का० आ० 1437--अत : संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के कलोल क्षेत्र में व्यधन स्थल का डी--II से का डी--4 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है ।

और यत: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 8--11--1971 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की धारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट संक्रिया को पर्यवसित कर दिया है ।

अब, अत : पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को, ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

व्यधन स्थल काडी--II से काडी--4 तक पाइपलाइन की संक्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पैट्रोलियम और रसायन	काडी	3776	16--10--1971	8--11--1971

[संख्या प्रोडक्शन/डी०डी०एन०/61(i)/71]

S.O. 1438--Whereas by the notification of Government of India shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site NKJ to KADI-I in Mehsana Oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in Clause (i) of the Section (1) of section 7 of the said act on 31-5-1970.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Rules, 1963 the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FROM D.S. NKJ TO KADI

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Govt. of India Gazettee	Date of termination of operation
PETROLEUM & CHEMICALS	CHALASAN	3526	25-9-1971	31-5-1970

[No. Prodn /DDN/61(1)/72.]

का० आ० 1438--यत : संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के महसाना तेल क्षेत्र में व्यधन स्थल एन के जे से काडी-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है ।

और यत : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 31--5--1970 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की धारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट संक्रिया को पर्यवसित कर दिया है ।

अब, अत : पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को, ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

व्यधन स्थल एन० के० जे० से काडी--1 तक पाइपलाइन की संक्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पैट्रोलियम और रसायन	चालासन	3526	25--9--71	31--5--70

[संख्या प्रोडक्शन/डी० डी० एन०/61 (1)/72]

S.O. 1439.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the Schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petrolcum from drill site SBH to G.G.S. I in Mehsana Oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of the section (1) of section 7 of the said act on 20-6-1971.

NOW THEREFORE under Rule 4 of the Petroleum Pipelines(Acquisition of Right of user in land) Rules, 1963 the Competent Authority Hereby notifies the said date as the date of termination of operation referred to above.

SCHEDULE

TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FROM D.S. SBH. TO G. G. S. I

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Govt. of India Gazette.	Date of termination of operation.
PETROLEUM & CHEMICALS . .	KUKAS HEBUVA	3627	9-10-1971	20-6-1971

[No. Prod/DDN/61(1)/72]
Sd. Illigible,
Competent Authority under the Act for Gujarat.

का० आ० 1439.—यत : संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (i) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के महसाना तेल क्षेत्र में व्यधन स्थल एस बी एच से जी० जी० एस०—I तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है। और यत : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 20-6-1971 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की धारा (I) के खंड (i) में निर्दिष्ट संक्रिया को पर्यवसित कर दिया है।

अब, अत : पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को, ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

अनुसूची

व्यधन स्थल एस बी एच से जी जी एस-I तक पाइपलाइन की संक्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख	संक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	कूकास हेबुवा	3627	9-10-1971	20-6-1971

[संख्या प्रोडक्शन/डी०डी०एन०/61(1)/72]

गुजरात के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 2nd March 1972

S.O. 1440.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 12 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Central Government hereby exempts the Edward Textile Mills Ltd., Bombay from payment of whole of the fees leviable under rule 21 of the Textiles Commitee Rules, 1965 for the period from April, 1966 to July, 1967.

[No. F. 25011/1/72 Tex-A.]

H. K. BANSAL, Dy. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

का० आ० 1440.—वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 12 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एडवर्ड टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, मुम्बई, को अप्रैल, 1966 से जुलाई, 1967 तक की अवधि के लिए वस्त्र समिति नियम, 1965 के

नियम 21 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण फीसों के संदाय से एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० फा 25011/1/72-टैक्स-ए०]

एस० के० बंसल, उपसचिव ।

New Delhi, the 24th March 1972

S.O. 1441.—The Government of Jammu & Kashmir having nominated the Managing Director, J & K Industries Ltd., Srinagar to be a member of the Central Silk Board in place of Shri Bazle Karim under clause (h) of sub-section (3) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby appoints the Managing Director, J & K Industries Ltd., Srinagar as a member of the Central Silk Board upto the 8th April, 1973 and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 1522, dated the 23rd April, 1970, namely:—

In the said notification against serial number 18A, the following shall be substituted namely:—

"18A. The Managing Director,
J & K Industries Ltd.,
Srinagar."

[No. F.21/1/70-Tex(F).]

M. L. GUPTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1972

का० आ० 1441.—केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) के अन्तर्गत, जम्मू और काश्मीर की सरकार द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जम्मू और काश्मीर इंडस्ट्रीज लि० श्रीनगर को, श्री बजले करीम के स्थान पर, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने पर केन्द्रीय सरकार प्रबन्ध निदेशक, जम्मू और काश्मीर इंडस्ट्रीज लि० श्रीनगर को 8 अप्रैल, 1973 तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1522 दिनांक 23 अप्रैल, 1970 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपरोक्त अधिसूचना में क्रमांक 18क के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"18क. प्रबन्धक निदेशक,
जम्मू और काश्मीर इंडस्ट्रीज, लि०,
श्रीनगर"

[सं० फा० 21/1/70—टैक्स (एफ०)]

एम० एल० गुप्ता, उपसचिव ।

(RUBBER CONTROL)

New Delhi, the 30th March 1972

S.O. 1442.—In pursuance of sub-section 3(a) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) the Central Government have appointed Professor K. M. Chandy, as Chairman, Rubber Board, Kottayam, for a period of two years with effect from forenoon of 14th March 1972 *vice* Shri T. V. Swaminathan, I.A.S.

[No. 21(1)Plant(B)/72.]

रबड़ नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1972.

का० आ० 1442.—रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा 3 (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री टी० वी० स्वमीनाथन् आई० ए० एस० के स्थान पर, प्रोफेसर के० एम० चंडी को 14 मार्च, 1972 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 21(1) प्लाट (बी)/72]

CARDAMOM CENTRAL

New Delhi, the 19th April, 1972

S.O. 1443.—In supersession of this Ministry's notification No. S.O. 3810, dated the 17th September, 1971, published in the Gazette of India dated the 16th October, 1971 in part II section 3 sub-section (ii), Shri I. L. Sankaranarayanan, Secretary, Cardamom Board, Ernakulam, is granted 80 days earned leave with effect from 6th May, 1971 and 120 days commuted leave thereafter on medical grounds upto and inclusive of 21st November, 1971.

In pursuance of sub-section (2) of section 7 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), the Central Government hereby appoints Shri R. Viswanathan, Accounts Officer in the Cardamom Board, to officiate as Secretary, Cardamom Board, in addition to his own duties, during the period of leave of Shri I. L. Sankaranarayanan.

[No. F.29(14)Plant(B)/70.]

N. N. MALHAN, Dy. Director.

इलायची नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1972

का० आ० 1443.—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 16 अक्तूबर, 1971 को प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3810, दिनांक 17 सितम्बर, 1971 के अधिक्रमण में श्री आई० एल० शंकरनरायणन, सचिव, इलायची बोर्ड, एर्नाकुलम, को 6 मई, 1971 से 80 दिन की अर्जित छुट्टी तथा उसके पश्चात् डाक्टरी आधार पर 21 नवम्बर, 1971 तक की 120 दिन की परिणत छुट्टी, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रदान की जाती है ।

इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इलायची बोर्ड में लेखा अधिकारी श्री आर० विश्वनाथन को, श्री आई० एल० शंकरनरायणन की छुट्टी की अवधि के दौरान उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त सचिव, इलायची बोर्ड, के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 29(14) प्लांट (बी)/70]

एन० एन० मल्हन,
उप-निदेशक ।

New Delhi, the 17th June, 1972.

S.O. 1444.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Ceramic Products (Inspection) Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Ceramic Products (Inspection) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 7th July, 1972.

(2) In the Export of Ceramic Products (Inspection) Rules, 1969- for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. Inspection fee-subject to a minimum of rupees twenty for each such consignment, a fee at the rate of 30 paise for every hundred rupees of F.O.B. value of each such consignment shall be paid as inspection fee under these rules."

[No. 6(2)/72-EI&EP.]

M. K. B. BHATNAGAR, Dy. Director.

नई दिल्ली, 17 जून, 1972

का० आ० 1444.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सेरेमिक उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सेरेमिक उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1972 होगा ।

(2) ये 7 जुलाई 1972 को प्रभावी होंगे ।

2. सेरेमिक उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 में—

नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. निरीक्षण फीस—प्रत्येक ऐसे परेषण के लिए न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे परेषण के पोत पर्यन्त मूल्य के प्रति 100 रुपए के लिए 30 पैसे की दर से फीस, इन नियमों के अधीन निरीक्षण फीस के रूप में, संदत्त की जायेंगी ।

[सं० 6(2)/72-ई०आई०एंड ई०पी०]

एम० के० बी० भटनागर,

उप निदेशक ।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDERS

Bombay, the 9th July 1971

SUBJECT:—*Cancellation of licence No. P/U/1331313 of 23-4-70 Customs purposes copy issued to M/s. Kamlesh Industries, 97 Kakar Industrial Estate, Lady Jamshedji Road. Mahim, Bombay. 16.*

S.O. 1445.—M/s. Kamlesh Industries, Bombay-16 have been granted licence No. 1331313 of 23rd April, 1970 for Rs. 5146 for import of shopping list item against Sr. No. A.66.4.

They have applied for duplicate copy of Customs purposes copy of the said licence on the ground that the original licence has been lost.

It is further stated that the said licence is not registered with the Customs and is not utilised.

In support of their claim applicant have filed in an affidavit.

I am satisfied that the original copy of Customs purposes copy of licence No. 1331313 of 23rd April, 1970 has been lost and direct that the duplicate copy of the Customs purposes copy should be issued to the applicant firm.

The original Customs purposes copy of the licence is cancelled.

[No. 96/198206/OD.69/L/EPSC.IIC/206.]

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, बम्बई

आदेश

बम्बई 9 जुलाई 1971

विषय:—सर्वश्री कमलेश इण्डस्ट्रीज, काकर इण्डस्ट्रियल एस्टेट लेडी जमशेदजी रोड, महिम, बम्बई—16 को जारी किए, गए लाइसेंस संख्या : पी/यू/1331313, दिनांक 23—4—70 की सीमा-शुल्क प्रति को रद्द करने का आदेश ।

एस०ओ० 1445.—सर्वश्री कमलेश इण्डस्ट्रीज, बम्बई—16 को क्रम संख्याए० 66.4 के सामने की पणन सूची मद के आयात के लिए 5146 रुपये काएक लाइसेंस सं० 1331313, दिनांक 23—4—70 प्रदान किया गया है ।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया है ।

आगे यह उल्लेख किया गया है कि उक्त लाइसेंस सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं किया गया है और उसका उपयोग नहीं किया गया है ।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस सख्या 1331313, दिनांक 23-4-70 की मूल सीमा-शुल्क प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक फर्म को इस की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए ।

लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति रद्द की जाती है ।

[सं० 96/198206/ओ०डी० 69/एल०/ई०पी०एस०सी०—2-सी/206]

Bombay, the 27th August 1971

SUBJECT:—*The cancellation of licence No.* 1350444 *dt.* 16-9-70 *and licence No.* 1346506 *dt.* 23-11-70 *Customs purposes copy issued to M/s. Gandhi Industries Bombay.*

S.O. 1446.—M/s. Gandhi Industries Bombay have been granted licence No. 1350444 dt. 16th September, 1970 and licence No. 1346506 dt. 23rd November, 1970 for import of Acrylic Moulding Powder etc. Acrylic Sheets and etc.

They have applied for duplicate copy of Customs Purpose of the said licences and the ground that the original licences have been lost.

It is further stated that the said original licence is not registered with Customs and is not utilised.

In support of their claim applicant have filed an affidavit.

I am satisfied that the original copies (Customs Purpose) of licence No. 1350444 dt. 16th September, 1970 and licence No. 134506 dt. 23rd November, 1970 have been lost and direct that the duplicate copies of the licences should be issued to the applicant firm.

The original Customs Purpose Copy of the licence is cancelled.

[No. 2/71/EPS.CIII.]

बम्बई 27 अगस्त, 1971

विषय :- सर्वश्री गांधी इन्डस्ट्रीज, बम्बई के नाम जारी किए गए लाईसेंस सं० 1350444 दिनांक 16-9-70 तथा लाइसेंस सं० 1346506 दिनांक 23-11-70 (सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति) को रद्द करना।

एस० ओ० 1446.—सर्वश्री गांधी इंडस्ट्रीज, बम्बई को एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर आदि, एक्रिलिक शीट्स और आदि के आयात के लिए लाइसेंस सं० 1350444 दिनांक 16-9-70 लाइसेंस सं० 1346506 दिनांक 23-11-70 स्वीकृत किए गए थे।

उन्होंने उक्त लाइसेंसों की अनुलिपि सीमा शुल्क कार्य संबंधी प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गये है।

आगे यह बताया गया है कि उक्त मूल लाइसेंस सीमाशुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत नहीं कराए गए है और उनका उपयोग नहीं किया गया है।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है।

मैं इससे संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० 1350444 दिनांक 16-9-70 और लाइसेंस सं० 1346506 दिनांक 23-11-70 की मूल सीमा-शुल्क कार्य संबंधी प्रतियां खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियां जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य-संबंधी प्रतियां रद्द की जाती हैं।

[सं० 2/71/ई०पी०एस०सी०-III]

Bombay, the 13th October 1971

SUBJECT:—*The Cancellation of licence No. 1339856 dt 2-2-1971 (Customs Purpose Copy) issued to M/s. Gandhi Industries Bombay.*

S.O. 1447.—M/s. Gandhi Industries, Bombay, have been granted licence No. 1339856 dt. 2nd February, 1971 for Import of Acrylic Moulding Powder, Cellulose Acetate Flakes etc.

They have applied for Duplicate copy of Customs Purposes of the said licence on the Ground that the Original copy of licence have been lost.

It is further stated that the said original copy of licence is not registered with the Customs and is not utilised.

In support of their claim applicant have filed an affidavit.

I am satisfied that the original copy (Customs Purposes) of licence No. 1339856 dt. 2nd February, 1971 has been lost and direct that the duplicate copy of the licence (Customs Purposes copy) should be issued to the applicant.

The Original Customs Purposes copy of the licence is cancelled.

[No. 3/71/EPSC.III.]

बम्बई 13, अक्टूबर 1971

विषय:—सर्वश्री गांधी इण्डस्ट्रीज, बम्बई के नाम में जारी किए गए लाइसेंस सं० 1339856 दिनांक 2-2-71 (सीमा-शुल्क कार्य-सम्बन्धी प्रति) को रद्द करने का आदेश।

एस०ओ० 1447.—सर्वश्री गांधी इण्डस्ट्रीज, बम्बई को एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर, सेलूलोस एसिटेट पलेक्स इत्यादि के आयात के लिए लाइसेंस सं० 1339856 दिनांक 2-2-71 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य-सम्बन्धी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल प्रति खो गई है।

आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की उक्त मूल प्रति सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराई गई है और उसका उपयोग नहीं किया गया है।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं इससे सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० 1339856 दिनांक 2-2-71 की मूल सीमा शुल्क कार्य-सम्बन्धी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्य-सम्बन्धी प्रति रद्द की जाती है।

[सं० 3/71/ई०पी०एस०सी०-3]

Bombay, the 23rd October 1971

SUBJECT:—*The cancellation of lience No. 1019066 dt. 22nd March, 1971 and licence No. 1347202 dt. 7th December, 1970 (Exchange Purpose copies.*

S.O. 1448.—M/s. Montana Sports (India) Pvt. Ltd., Bombay-1 have been granted licence No. 1019066 dt. 22nd March, 1971 and licence No. 1347202 dt. 7th December, 1970 for Import of CAB Moulding Powder and Cellulose Acetate Flakes etc.

M/s. Montana Sports Bombay applied for Duplicate copies for Exchange Purpose of the said licences on the ground that the Original Licences for exchange control purposes have been lost.

It is further stated that the said original copies of licences are not utilised.

In support of their claim applicant have filed an affidavit.

I am satisfied that the original copies (Exchange Purposes) of licence No. 1019066 dt. 22nd March, 1971 and licence No. 134202 dt. 7th December, 1970 have been

lost and direct that the duplicate copies of the licences should be issued to the applicant firm.

The original Exchange Purposes copies of the licences are cancelled.

[No. 1/71/EPSC.III.]

बम्बई, 23 अक्टूबर, 1971

विषय :— लाइसेंस सं० 1019066 दिनांक 22–3–71 तथा लाइसेंस सं० 1347202 दिनांक 7–12–70 (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों) को रद्द करने का आदेश।

एस० ओ० 1448:—सर्वश्री मोनताना स्पोर्टस (भारत) प्रा० लि०, बम्बई–1 को सी ए बी मोल्डिंग पाउडर तथा सेलिलोस एसिटेट आदि के आयात के लिए लाइसेंस संख्या 1019066 दिनांक 22–3–71 तथा लाइसेंस सं० 1347202 दिनांक 7–12–70 स्वीकृत किए गए थे।

सर्वश्री मोनताना स्पोर्टस, बम्बई ने उक्त लाइसेंसों की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं।

आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की उक्त मूल प्रतियों का उपयोग नहीं किया गया है।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं इससे संतुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या 1019066 दिनांक 22–3–71 तथा लाइसेंस सं० 1347202 दिनांक 7–12–70 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं और निदेश देता हूं कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियां जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां रद्द की जाती हैं।

[संख्या 1/71/ई०पी०एस० सी० III]

Bombay, the 30*th November* 1971

SUBJECT:—*Cancellation of licence No. P/P/*2598051 *dated* 25*th September*, 1969 *issued to M/s Gaco, Varanasi.*

S.O. 1449.—M/s. Gaco, Varanasi, have been granted licence No. P/P/2598051 dated 25th September, 1969 for Rs. 3992 for import of (1) Dyes & Chemicals Permissible types Rs. 1996 & (2) Items of Embellishment Rs. 1996 as per AM-68 Policy Book as amended from time to time. They have applied for duplicate Custom purposes copy of the said licence on the ground that the original licence has been misplaced or lost.

It is further stated that the said original licence was not registered with any Customs House and not utilised.

In support of their claim applicant has filed an Affidavit. I am satisfied that the original copy of Customs purposes of licence No. P/P/2598051 dated 25th September, 1969 has been lost and direct that the duplicate copy of the licence should be issued to the applicant firm.

The original Customs copy of the licence is cancelled.

[No. F. 177-IV/PSF/568/65-66/EP-I/EP. Erstwhile.]

D. D'SOUZA,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.
For Jt. Chief Controller.

बम्बई, 30 नवम्बर 1971

विषय :—सर्वश्री गेको वाराणसी को जारी किए गए लाइसेंस सं० पी/पी/2598051 दिनांक 25–9–69 को रद्द करना

एस०ओ० 1449.—सर्वश्री गेको, वाराणसी को समय समय पर यथासंशोधित अप्रैल मार्च 1968 नीति पुस्तक के अनुसार (1) 1996 रु० के स्वीकृत किस्म के रंग और रासायनों तथा (2) 1996 रु० की अलंकरण मदों के आयात के लिए 3992 रु० का एक आयात लाइसेंस सं० पी/पी/2598051 दिनांक 25–9–69 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस अस्थानस्थ हो गया है या खो गया है।

आगे यह बताया गया है कि उक्त मूल लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं करवाया गया था और उसका उपयोग नहीं किया गया था।

इस दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/पी/2598051 दिनांक 25–9–69 की मूल सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को इसकी अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति रद्द की जाती है।

[सं० 177-4/पी०एस०एफ०/568/65-66/ईपी-1/ईपी-ईरिस्टव्हाइल से आरी]

डी० डीसोजा,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Calcutta, the 10*th September* 1971

SUBJECT:—*Order cancelling Exchange Control Copy of Import licence No. P|S|*1328562*|C|XX|*38*| C|*31-32 *dt.* 28*th January*, 1971 *in connection with the issue of duplicate copy of the same interms of GLI* 10/67 *dt.* 23*rd March*, 1967.

S.O. 1450.—M/s. Bhalotia Metal Mfg. Co. 2, Digamber Jain Temple Road, Calcutta-7 were granted licence No. P/S/1328562/C/XX/38/C/31-32 dated 28-1-71 for Rs. 5000. They have applied for duplicate copy of the Exchange Control Copy of the said licence on the ground that the original of the same has been lost. It is further stated that the original licence has not been registered with any Customs authorities and the full value of licence (*i.e.* Rs. 5000/- remained unutilised.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit to the effect that the original Exchange Control Copy of the licence has been lost. I am satisfied that the original Exchange Control Copy of the licence No. P/S/1328562/-C/XX/38/C/31-32 dated 28-1-71 for Rs. 5000/- has been lost and directed that duplicate copy of the same should be issued to the applicant. The original Exchange Costrol Copy of the licence is cancelled.

[No. 47-I/P/DI/15/70-71/AU-IV/VI.]

P. B. SAHA,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

(संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय कलकत्ता)

आदेश

कलकत्ता, 10 सितम्बर, 1971

विषय :— आयात लाइसेंस सं० पी।एस।1328562।सी। एक्स एक्स।38।सी 31. 32 दिनांक 28—1—71 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करना और जी एल आई 10/67 दिनांक 23—3—67 के अनुसार इस संबंध मे अनुलिपि प्रति जारी करने का आदेश।

एस० ओ० 1450:—सर्वश्री भलोटिया मैटल मेनुफैक्चरिंग कं० 2, दिगम्बर जैन टेम्पल रोड कलकत्ता-7 को 5000रु० के लिए आयात लाईसेंस सं० पी।एस।1328562/सी/एक्स एक्स/38।सी/31-32 दिनाक 28—1—71 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाईसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल लाईसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था और लाईसेंस के पूरे मूल्य यानि (5000 रु०) का प्रयोग नहीं किया गया था।

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने यह बताते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि मूल लाईसेंस खो गया है। मैं इससे संतुष्ट हूं कि लाईसेंस सं० पी।एस।1328562।सी।एक्स एक्स।38 सी।31. 32 दिनाक 28—1—71 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता हू कि आवेदक को उसी की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। लाईसस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या : 47—1/पी०/डी० आई०/15।70—71/ए०यू०—4/6]

पी० बी० साहा,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात—निर्यात।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

(CLA)

ORDERS

New Delhi, the 14th October 1971

S.O. 1451.—M/s. Balkishan Das & Sons. 1083-84 & 88, Farash Khana, Delhi-6, were granted Import L. No. P/S/1612258/C/XX/29/D/25/26 dated 18th October, 1968, and P/S/1612259/C/XX/29/D/25-26 dated 18th October, 1968 for the Import of Pandulam Clocks and Lever Clocks Parts as per the list attached thereto for Rs. 10000 (Ten Thousand only) and Rs. 2623 (Two Thousand Six Hundred and Twenty Three only) respectively. They have applied for the issue of duplicate copies of both the copies of the said licences on the ground that original ones have been lost without having been registered with any custom authorities and utilised at all.

2. The applicants have filed affidavits on stamped paper in support of their contention as required under para 312(2) *read* with appendix 8 of the I.T.C. Hand Book of Rules and procedure, 1971. I am satisfied that the above said original licences (both copies) have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me, under clause 9 (cc) import (control) order, 1955 Dt. the 7th December, 1955 as amended uptodate, I order, cancellation of both copies of licences No. P/S/1612258/C/XX/28/D/25-26 and P/S/1612259/C/XX/D/25-26 both dated 18th October, 1968.

The applicants are now being Issued Duplicate Copies of the said two Import Licences in accordance with Para 312(2) of I.T.C. Hand Book of Rules and procedure 1971.

[No. F. B-52/AM-63/AU.UT.CLA.]

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर 1971

एस० ओ० 1451.—सर्वश्री बाल किशन दास एण्ड संस, 1083—84 और 88, फराश खाना, दिल्ली—6 को लाइसेंस संख्याएं, पी/एस/1612258/सी/एक्सएक्स/29/डी/25/26, दिनांक 18—10—68 और पी/एस/1612259/सी/एक्स एक्स/29/डी/25—26, दिनांक 18—10—68 उन के साथ संलग्न सूची के अनुसार पैण्डुलम घड़ियों और लीवर घड़ियों के आयात के लिए क्रमशः 10,000/ रुपये (दस हजार रुपये) और 2,623 रुपये (दो हजार छः सौ तेईस रुपये मात्र) के लिए प्रदान किए गए थे। उन्होंने उक्त लाइसेंस की दोनों प्रतियों की अनुलिपियां जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां किसी सीमा शुल्क प्राधिकारी मे पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गई है।

2. आवेदक फर्म ने अपने तर्क के समर्थन में आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा प्रक्रिया हैंण्डबुक, 1971 के परिशिष्ट 8 के साथ पढ़ी जाने वाली कंडिका 312(2) में यथा अपेक्षित स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त मूल लाइसेंस (दोनों प्रतियां) खो गई हैं/अस्थानस्थ हो गई हैं।

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 की धारा 9 (सीसी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं लाइसेंस संख्या पी/एस/1612258 सी/एक्सएक्स/28/डी/25—26 और पी/एस/1612259/सी एक्सएक्स/डी/25—26 दिनांक 18—10—68 की दोनों प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं।

4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा प्रक्रिया हैण्डबुक, 1971 की कंडिका 312(2) के अनुसार उक्त दोनों लाइसेंसों की अनुलिपियां जारी की जा रही हैं।

[संख्या बी० 52/ए० एम० 68/ए०यू०यूटी०सी०एल०ए०]

New Delhi, the 12th January 1972

S.O. 1452.—M/s. The Shadow Electronics, 2359-Kucha Chalan, Darya Ganj, Delhi, were granted licence No. P/S/1621150, dated 23rd September, 1970 for Rs. 5,000 only (Rupees Five Thousand only). They have applied for issue of duplicate Customs purposes copy of the licence on the ground that the original Custom Purposes Copy has been misplaced after having been registered at Bombay Custom House, and utilized partly upto Rs. 3,000 leaving a balance of Rs. 2,000 only.

The Applicant has filed an affidavit on stamped paper in support of their contention as required under para 312(2) read with appendix 8 of ITC Hand Book of Rules and Procedure, 1971. I am satisfied that the original Custom Purposes Copy has been misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under clause 9(CC) imports (Control) Order, 1955, dated 7th December, 1955 as amended upto date, I order the cancelation of the Custom Purposes Copy of licence No. P/S/1621150, dated 23rd September, 1970.

The applicants case will now be considered for the issue of duplicate Custom Purpose Copy of the said licence in accordance with para 313(I) & 2 of I.T.C. Hand Book of Rules and Procedure, 1971.

[No. F. P/S/14/DELAM71/AU.UT.CLA.]

D. S. MORKRIMA,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports.
for Jt. Chief Controler of Imports & Exports.

नई दिल्ली 12 जनवरी, 1972

एस० ओ० 1452.—सर्वश्री शैडो इलैक्ट्रानिक्स, 2359, कूचा चेलान, दरियागंज, दिल्ली को 5000 रु० (पांच हजार रुपये मात्र) के लिये एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/162/150 दिनांक 23-9-70 प्रदान किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि बम्बई सीमा शुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराने, 3000 रुपये तक आंशिक उपयोग करने और केवल 2000 रु० मात्र शेष रहने के बाद मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है।

आवेदक ने अपने तर्क की पुष्टि में आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा प्रक्रिया पुस्तक, 1971 के परिशिष्ट 8 के साथ पढ़ी जाने वाली कंडिका 212(2) के अनुसार यथा अपेक्षित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है।

अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं लाइसेंस संख्या पी/एस/1621150 दिनांक 23-9-70 की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं।

उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिये अब आवेदकों के मामले पर आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा प्रक्रिया पुस्तक, 1971 की कंडिका 313(1) तथा (2) के अनुसार विचार किया जायेगा।

[संख्या० पी०/एस०/14/डी० ई० एल० ए० एम० 71/ए० यू० टी० सी० एल० ए०]

डी० एस० मोरक्रीमा,

उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

CANCELLATION ORDER

Bombay the 27th September, 1971

SUBJECT:—*Order for Cancellation of Custom Purpose Copy of the Import Licence No P/A/ 1017955 dated 11/2/71 for Rs. 1,12,488/-M/s. Fancy Corporation Ltd. Bombay.*

S.O. 1453.—M/s. Fancy Corporaton Ltd., Bombay were granted the Import Licence No. P/A/1017955 dated 11/2/71, for Rs. 1,12,488/- for import of all Permissible Spare Parts for the Foreign made Textile Machinery installed in the licence-holder's Factory, as appearing in the Machinery Manufacture's catalogue but not specifically banned elsewhere in the I.T.C. Policy for AM-71 period. They have applied for a duplicate copy of the Custom purpose copy of the above import licence on the ground that original Custom Purpose copy of the licence has been lost/misplaced. It is further stated that the original Custom Purpose Copy of the licence was utilised to the extend of Rs. 8,672/- and that the duplicate is to be issued for the balanced value of the licence namely 1,03,816/-.

In support of this contention, the above referred firm has filed an affidavit on stamp paper duly signed before the Notary. I am satisfied that the original Custom Purpose Copy of he import licence No. P/A/ 1017955 dated 11-2-71, has been lost or misplaced and direct that a duplicate copy of the Custom Purpose Copy of the licence should be issued to the firm.

The original Custom Purpose Copy of the import licence No. P/A/1017955 dated 11-2-71, may be deemed to have been cancelled.

In view of above and also urgency of the matter the firm has already been issued duplicate Custom Purpose Copy *vide* D-2463084 dated 16-8-71.

[No. 385/MC.No.457949/AM-71/AU-2.]

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

बम्बई 27 सितम्बर, 1971

विषय :—सर्वश्री फैन्सी कारपोरेशन लि०, बम्बई को 1,12,488 रु० के लिये जारी किए गए आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति को रद्द करने के लिए आदेश।

एस० ओ० 1453.—सर्वश्री फैन्सी कारपोरेशन लि०, बम्बई को उनके कारखाने में संस्थापित विदेश-निर्मित कपड़ा मशीनरी के सभी अनुमेय फालतू पुर्जों मशीनरी-विनिर्माण सूचिका में यथा

प्रदर्शित परन्तु अप्रैल—मार्च, 71 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक में और कहीं विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं है, के आयात के लिए 1,12,488 रु० के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1017955 दिनांक 11—2—71 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति का 8,672 रु० की सीमा तक उपयोग किया गया था और लाइसेंस के शेष मूल्य अर्थात् 1,03,816 रु० के लिए अनुलिपि जारी करनी है।

इस तर्क की पुष्टि में उपर्युक्त फर्म ने नोटरी के सामने विधिवत् हस्ताक्षरित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/ए/1017955 दिनांक 11—2—71 की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि इस की अनुलिपि फर्म को जारी की जाए।

आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1017955 दिनांक 11—2—71 की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द कर दी गई समझी जाए।

उपर्युक्त कथन को ध्यान में रखते हुए और मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए अनुलिपि प्रति पी/ए/डी—2465084 दिनांक 16—8—71 पहले ही फर्म को जारी कर दी गई है।

[सं० 385/एम० सी० नं० 457949/ए० एम० 71/ए० यू०-2]

Bombay, the 21st January, 1972.

SUBJECT:—*Cancellation of licence No. G/G/2455062/C dated 9-11-70 (Custom Purposes Copy) issued to The Registrar, Tata Institute of Fundamental Research, Holiday Camp, Colaba, Bombay-5.*

S.O. 1454.—The Registrar, Tata Institute of Fundamental Research, Holiday Camp, Colaba, Bombay-5 have been granted Import Licence No. G/G/2455062/C dated 9-11-70, for Rs. 62500/- (Rupees Sixty-two thousands Five hundred only) for Import of Electronic & Wireless Components, Semi conductors and Semi conductors devices etc.

They have applied for issue of duplicate copy of Customs Purposes Copy of the said licence for the balance amount of Rs. 40,057/- on the ground that the original Customs Copy of the said licence has been lost.

In support of their claim the applicant have filed an affidavit declaring that the Customs Purposes Copy of the said licence issued to them for the Import of Electronic and Wireless components from G.C.A. has been misplaced after having been registered with Customs House, Ballard Estate, Bombay-1, and utilised partly i.e. Rs. 22443/-.

I am satisfied that the original copy of Customs Purpose of licence No. G/G/2455062/C dated 9-11-70, has been lost and direct that a duplicate copy of the Customs purpose copy of the said licence for the balance amount of Rs. 40,057/- should be issued to the applicant firm.

The original Customs purpose copy is cancelled.

[No. 116/M/C.No. 399126/Govt./AM'71/AU.IV.]

S. P. DIWAN,
Dy. Chief Controller,
for Joint Chief Controller of Imports & Exports.

बम्बई, दिनांक 21 जनवरी, 1972

विषय :—पंजीयक, टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, हालीडे कैम्प, कोलाबा, बम्बई—5 को जारी किए गए लाइसेंस सं० जी/जी/2455062/सी/ दिनांक 9—11—70 (सीमाशुल्क निकासी प्रति) को रद्द करना।

एस० ओ० 1454.—पंजीयक, टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, हालीडे कैम्प, कोलाबा, बम्बई—5 को इलैक्ट्रानिक तथा बेतार-संघटकों अर्ध चालकों और अर्ध-चालक-यंत्रों आदि के आयात के लिए एक आयात लाइसेंस सं० जी/जी/2455062/सी दिनांक 9—11—70, 62500 रु० (बासठ हजार पांच सौ रुपये मात्र) के लिए प्रदान किया गया था।

उन्होंने शेष राशि 40057 रु० के लिए उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क निकासी प्रति खो गई है।

आवेदकों ने अपने दावे के समर्थन में यह घोषित करते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि उनको सामान्य मुद्रा क्षेत्र से इलैक्ट्रानिक तथा बेतार संघटकों के आयात के लिए जारी किए गए उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति, सीमाशुल्क कार्यालय, बेलार्ड इस्टेट, बम्बई—1 में पंजीकृत कराने और उसका आंशिक उपयोग अर्थात् 22443 रु० तक करने के बाद खो गई है।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० जी/जी/2455062/सी दिनांक 9—11—70 का मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि शेष धन राशि 40057 रु० के लिए आवेदक फर्म को जारी की जानी चाहिए।

मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द की जाती है।

[सं० 116/गवर्नमेंट/एम०/सी०—399126/ए० एम० 71/ए० यू० 4]

एस० पी० दीवान,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Kanpur, the 23rd December, 1971

S.O. 1455.—The following licences for the import of ball bearings non-banned non-restricted types and permissible types of Taper Roller Bearings were issued to M/S Khatauli Agro Industries, Pucca Bagh,

Gaushala, Khatauli (Distt. Muzaffarnagar), in the category of actual users.

(i) P/S/1656427 dated 28th October, 1970 for Rs. 5,000/-.

(ii) P/S/1656428 dated 28th October, 1970 for Rs. 5,000/-.

Thereafter a show cause notice No. Enf. II (102)/1971/Kan/3027 dated 25th October, 1971 was issued asking them to show cause within fifteen days of the date of receipt of notice as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that their factory had closed and the licences would not serve the purpose for which they were granted.

2. The said show cause notice has been returned undelivered by the postal authorities with the remarks that the addresssee has left the premises without further address.

The undersigned has carefully considered the case and has come to the conclusion that the said M/S Khatauli Agro Industries, Khatauli have avoided a reply as they have no defence to urge, have actually closed down and that the licences will not serve the purpose for which they were granted.

Having regard to what has been stated in the preceding para the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered in effective. Therefore, the undersigned, in exercise of powers vested in him under clause 9 sub-clause (cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended from time to time hereby cancels the licences No. P/S/1656427 dated 28th October, 1970 for Rs. 5,000/- and P/S/1656428 dated 28th October, 1970 for Rs. 5,000/- issued in favour of M/S Khatauli Agro Industries, Pucca Bagh, Gaushala, Khatauli.

[No. ENF.II(102)/1971/KAN.]

O. N. ANAND,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

(उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

कानपुर, 23 दिसम्बर, 1971

एस०ओ० 1456—सर्वश्री खतौली एग्रो इंडस्ट्रीज पक्का बाग, गौशाला, खतौली (जिला मुजफ्फर नगर) को बिना निशेध वाली और अप्रतिबन्धित किस्म के बाल बेयरिंग और स्वीकृत किस्म के टेपर रोलर बेयरिंग के आयात के लिए वास्तविक उपभोक्ता की श्रेणी में होने के कारण निम्नलिखित आयात लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :—

(1) पी/एस/1656427 दिनांक 28-10-1970 मूल्य 5,000 रु०

(2) पी/एस/1656428 दिनांक 28-10-1970 मूल्य 5,000 रु०

तत्पश्चात उन्हें एक कारण बताओ सूचना सं० इन्फ० 2(102)/1971/कान/3027 दिनांक 25-10-71 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि उक्त सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिए जाने चाहिएं और वे इस आधार पर कि उनका कारखाना बन्द हो गया था और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे, वे उसे पूरा नहीं करेंगे ।

उपर्युक्त कारण बताओ सूचना डाक प्राधिकारियों द्वारा इस टिप्पणी के साथ बिना बांटे वापिस लौटा दी गई है कि पेढ़ी ने अगला पता दिए बिना ही वह स्थान छोड़ दिया है ।

अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस परिणाम पर पहुंचा है कि उक्त खतौली एग्रो इंडस्ट्रीज, खतौली ने उत्तर देने में आना-कानी की है क्योंकि अपने बचाव के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं है वास्तव में उनका कारखाना बन्द हो गया है और उपर्युक्त लाइसेंस जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जारी किए गए थे, उसे पूरा नहीं करेंगे ।

पूर्व की कंडिका में जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, दिनांक 7-12-55 की धारा 9 उपधारा (सी सी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस संख्याएं पी/एस/1656427 दिनांक 28-10-1970 मूल्य 5000 रु० और पी/एस/1656428 दिनांक 28-10-1970 जो सर्वश्री खतौली एग्रो इंडस्ट्रीज, पक्का बाग गोशाला, खतौली को जारी किए गए थे एतद्द्वारा रद्द करता है ।

[संख्या : इन्प. 2(102)/1971/कान]

ओ० एन० आनन्द,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

(Office of the Assit. Iron & Steel Controller N.H.IV. Faridabad.)

CANCELLATION ORDER

Faridabad, the 14th December 1971

S.O. 1456.—M/s. New Captain Cycle Industries, 110/ Lajpat Nagar, Ludhiana were granted one import Licence No. P/6851592/C/xx/39/31-32, dated 28th April, 1971 for Rs. 5000 issued under G.C.A. for the item Sheet cutting 1.6mm & Thinner excluding all coated sheet cutting and defective sheet for the period April-March, 1971 with the port of registration Bombay. They have applied for Duplicate Custom Clearance Purpose copy of this licence on the ground that the original Custom clearance Purpose copy of this licence has been lost. It is stated the original Licence in Custom clearance purpose copy were not registered with any Custom Authority and were not utilised at all.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Custom Clearance Purpose copy of Import Licence No. P/S/-8551592/C/XX/39/D/31-32 dated 28th April, 1971 have been lost and direct that the Duplicate Licence (In Custom Clearance Purpose Copy) should be issued to applicant in cancellation of the original Custom Clearance Purpose copy of licence in question.

[No. P/S-31/A.M.71/NU/AU-PB/ISCD.]

M. G. GOMBAR,
Dy. Chief Controller of Import & Exports.

(सहायक नियंत्रक, लोहा तथा इस्पात का कार्यालय)

प्रवेश

फरीदाबाद, 14 दिसम्बर, 1971

एस० ओ० 1456.—सर्वश्री न्यू कैप्टेन साइकिल इन्डस्ट्रीज, 110-लाजपत नगर, लुधियाना को अप्रैल-मार्च, 1971 अवधि के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र से सभी कोटिङ शीट कटिंग और नुक्स-वाली शीट को छोड़कर 1.6 एम एम तथा इससे पतली शीट कटिंग मदों के आयात के लिए बम्बई पत्तन से पंजीकरण के साथ 5000 रु० का एक आयात लाइसेंस सं० पी/8551592/सी/एक्स एक्स/39/31.32 दिनांक 28-4-71 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी कार्यसंबंधी प्रति खो गई है। यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था और उसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया था।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं इससे संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/एस/8551592/सी/एक्स एक्स/39/डी/31/32 दिनांक 28-4-71 की मूल सीमाशुल्क निकासी कार्य संबंधी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि विषयाधीन लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी कार्यसंबंधी प्रति को रद्द कर आवेदक को अनुलिपि लाइसेंस (सीमाशुल्क निकासी कार्य संबंधी प्रति) जारी किया जाना चाहिए।

[मिसिल सं० पी०/एस०-31/ए० एम० 71/एन० यू०-पी० बी०/आई० एस० सी० डी०]

एम० जी० गोम्बर,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Bombay, the 20th December 1971

SUBJECT:—*Cancellation of Customs Purposes Copy of licence No. P/S/1672054/C/XX/37/X/31-32 dated 2nd November, 1970 for Rs. 1,500/-*

S.O. 1457.—M/s. Kala Corporation, No. 6, Mamulpet, Bangalore 2 were granted import licence No. P/S 1672054/C/XX/37/X/31-32 dated 2nd November, 1970 for import of Aromatic Chemicals, Natural Essential Oils and Resinoids. They have now applied for duplicate copy of Customs Purposes Copy of the above licence on the ground that the original of the above Customs Purposes Copy of the licence has been lost without having been registered with any Customs Authorities and not utilised at all and that the duplicate copy of Customs Purposes Copy of the above licence now required is for the full value of licence Rs. 1,500/-.

In support of the above contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the Original Customs Purposes Copy of the above licence has been lost and direct that a duplicate copy of the Customs Purposes Copy of the above licence should be issued to the applicant. The original customs purposes copy of the above licence is hereby cancelled.

[No. ITC.SSIA.55.A.M.71.NP.]

(उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

बंगलौर, 20 दिसम्बर, 1971

विषय :—1,500 रु० के लिए जारी किये गये लाइसेंस सं० पी/एस/1672054/सी/एक्स एक्स/37/एक्स/31.32 दिनांक 2-11-1970 को सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति को रद्द करना।

एस० ओ० 1457.—सर्वश्री कला कार्पोरेशन, सं० 6, मामुलपेट, बंगलौर 2 को एरोमेटिक केमिकल्ज, प्राकृतिक सुगंधित तेल और रेजिनायडूस के आयात के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1672054/सी/एक्स एक्स/37/एक्स/31.32 दिनांक 2-11-1970 स्वीकृत किया गया था। अब उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास बिना पंजीकृत कराए और बिना उपयोग किए ही खो गई है और अब उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रति की आवश्यकता लाइसेंस के पूरे मूल्य यानी 1500 रु० के लिए है।

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्य संबंधी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है

[आई० टी० सी० एस० एस० आई० ए०ए०एम० 71 एन० पी०]

Bangalore, the 28th January 1972

SUBJECT:—*Cancellation of Customs Purposes Copy of Licence No. P/S/1673689/C/XX/38/X/31-32 dated 24th March, 1971 for Rs. 20,025/-.*

S.O. 1458.—M/s. Electronic Industrial Corporation 113, Brigade Road., Bangalore were granted import licence No. P/S/1673689/C/XX/38/X/31-32 dated 24th March 1971 for Rs. 20,025/- for import of Components of Tape Recorders. They have now applied for duplicate copy of Customs Purposes Copy of above licence on the ground that the original of the above Customs Purposes Copy of above licence has been lost/misplaced after having been registerd with the Central Excise Department, Bangalore and utilised partly for Rs. 489/- and that the duplicate copy of Customs Purposes Copy of above licence now required is for the balance value of Rs. 19,536/-.

In support of the above contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the Original Customs Purposes Copy of the above licence has been lost/misplaced and direct that a duplicate copy of Customs Purposes Copy of above licence should be issued to the applicant. The Original Customs Purposes Copy of above licence is hereby cancelled.

[No. ITC/SSI/2295/B.290/A.M '72/NP.]

बंगलौर, 28 फरवरी 1972

विषय :—लाइसेंस सं० पी/एस/1673689/सी/एक्स एक्स/38/एक्स 31–32 दिनांक 24–3–1971 की सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति को रद्द करना ।

एस० ओ० 1458.—सर्वश्री इलैक्ट्रानिक इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, 113, ब्रिगेड रोड, बंगलौर को टेप रिकार्डर के संघटकों के आयात करने के लिए 20,025 रु० का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1673689 सी/एक्स एक्स/38/एक्स/31–32 दिनांक 24–3–1971 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने अब उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति केन्द्रीय राजस्व विभाग के पास पंजीकृत करने के बाद और 489 रु० के लिए उसका आंशिक रूप से उपयोग करने के बाद खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है और अब शेष 19,538 रु० के लिए उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी प्रति की आवश्यकता है ।

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति जारी की जानी चाहिए । उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

[सं० आईटी सी/एस एस आई/2295/बी० 290/ए एम० 72/एन पी]

S.O. 1459.—M/s. Sree Mahalaxmi Agarbathi Works Door No. 25, Upstairs, Chemarajpet, 3rd. Main Road Bangalore. 18 were granted import licence No. P/S/-1672619/R/KN/7/X/31 32/ML dated 26th December, 1970 for import of Aromatic Chemicals, Natural Essential Oils and Resinoids. They have now applied for duplicate copy of Customs Purposes Copy of the above licence on the ground that the original of the above Customs Purposes Copy of the licence has been lost without having been registered with any Customs Authorities and not utilised at all and that the duplicate copy of Customs Purposes Copy of the above licence now required is for the full value of licence Rs. 2,500/-.

In support of the above contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the Original Customs Purposes Copy of the above licence has been lost and direct that a duplicate copy of the Customs Purposes Copy of the above licence should be issued to the applicant. The Original Customs Purposes Copy of the above licence is hereby cancelled.

[No. ITC/SSI/A.16/A.M.71/NP.]

विषय :—2,500 रुपये के लिये लाइसेंस सं० पी/एस/1672619/आर/के एन/37/एक्स/31–32/एस एल, दिनांक 26–12–1970 की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति को रद्द करना ।

एस ओ० 145 .—सर्वश्री महालक्ष्मी अगरबत्ती वर्क्स, डोर नं० 25 अपस्टेयर, चामराजपेट, थर्ड मेन रोड, बंगलौर–18 को एरोमेटिक केमिकल्स, प्राकृतिक सुगन्धित तेल तथा रेजिनायड्स के आयात के लिए लाइसेंस संख्या पी/एस/1672619/आर/के० एन/ 37/एक्स/31–32/एम एल, दिनांक 26–12–1970 प्रदान किया गया था । अब उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की उपर्युक्त सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की मूल प्रति खो गई है । यह न तो किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करायी गई थी और न उसका उपयोग ही किया गया था । और अब उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति की आवश्यकता लाइसेंस के पूरे मूल्य 2,500 रुपये के लिए है ।

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए । उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति इसके द्वारा रद्द की जाती है ।

[संख्या आई.टी.सी.एस.एस.आई.ए.16 ए.एम.71.एन.पी]

Bangalore, the 17th February 1972

S.O. 1460.—M/s. Sri Srinivasa Agarbathi Works, No. 84, Thigularpat, Bangalore-2, were granted import licence No. P/S/1676198/R/ML/40/X/33-34 dated 21-9-1971 for import of Aromatic Chemicals, Natural Essential Oils and Resinoids. They have now applied for duplicate copy of Customs Purposes Copy and Exchange Control Purposes Copy of the above licence on the ground that the original of the above Customs Purposes Copy and Exchange Control Purposes Copy of the licence have been lost without having been registered with any Customs Authorities and not utilised at all and that the duplicate copy of Customs Purposes Copy and Exchange Control Purposes Copy of the above licence now required is for the full value of licence Rs. 5,000/-.

In support of the above contention, the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the Original Customs Purposes Copy and Exchange Control Purposes Copy of the above licence have been lost and direct that a duplicate copy of the Customs Purposes Copy and Exchange Control Purposes Copy of the above licence should be issued to the applicant. The Original Customs Purposes Copy and Exchange Control Purposes copy of the above licence are hereby cancelled.

[No. ITC/SSI/A.90/A.M.72/NP.]

K. JAYARAMAN,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

बंगलौर, 17 फरवरी, 1972

विषय :—लाइसेंस सं० पी/एस/1676198/आर/एम एल/40/एक्स/33–34 दिनांक 21–9–1971 मूल्य 5000 रु० की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करना ।

एस०ओ० 1460.—सर्वश्री श्रीनिवास अगरबत्ती वर्क्स, नं० 84 थिगालरपेट, बंगलौर–2 को सुगन्धित रासायनिकों प्राकृतिक सुगन्धित तेलों और रेजिनाइड्स के आयात के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1676198/आर/एम/एल/40/एक्स/33–34 दिनांक 21–9–71 प्रदान किया गया था । अब उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर

आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी सीमाशुल्क प्राधिकारियों से पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल उपयोग किए बिना खो गई है और यह कि अब सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपियों की आवश्यकता लाइसेंस के पूर्ण मूल्य 5000 रु० के लिए है।

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि इनकी अनुलिपियां आवदक को जारी की जानी चाहिएं। उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या आई टी सी/एस एस आई/ए.90/ए एम.72/एन पी]

के० जयारामन,
उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Calcutta, the 16th November, 1971.

SUBJECT: *Order cancelling Exchange Control purpose copy of Licence No. I/A/1011470/C/XX/34/C/30., dated 17th February, EFSZ in connection with the issue of duplicate copy of same in terms of GLI No. 10/67, dated 23rd March, 1967.*

S.O. 1461.—The Controller of Stores, Calcutta Port Commissioners, Calcutta was granted licence No. I/A/1011470/C/XX/34/C/30, dated 17th February, 1970 for Rs. 67,228 for import of wireless equipment and spares under I.T.C. Serial No. 289-90/iv. He applied for duplicate copy of Exchange Control purposes of the said licence on the ground that the original of the same has been misplaced. It has been further stated that the original licence has been registered in the Calcutta Customs and full value has been fully utilised. This required for the remittance of foreign exchange purposes.

In support of this cancellation the applicant has filed an affidavit to that effect that original exchange control copy of the licence has been misplaced. I am satisfied that the original Exchange Control copy of the licence No I/A/1011470/C/XX/34/C/30, dated 17th February, 1970 for Rs. 67,228 has been misplaced, and the duplicate copy of the same should be issued to the applicants. The original copy of exchange control purposes of licence is cancelled.

[No. 289-90-iv/14/69-70/Au-II(II).]

T. T. LA,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports,
for Jt. Chief Controller of Imports Exports.

(संयुक्त-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

कलकत्ता, 16 नवम्बर, 1971

विषय.—लाइसेंस संख्या आई/ए/1011470/सी/एक्स/एक्स/34/सी/30, दिनांक 17-2-70 की मुद्रा विनियम नियंत्रण, प्रति को रद्द करना और जी एल आई 10/67, दिनांक 23-3-71 के अनुसार उसी की अनुलिपि प्रति जारी करने का आदेश।

एस० ओ० 1461.—दि कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर, कलकत्ता को आयात व्यापार नियंत्रण क्रम संख्या 289-90/4 के अन्तर्गत वायरलेस उपकरण और फालतू पुर्जों के आयात के लिये 67228/- रुपये का आयात लाइसेंस संख्या आई/ए/1011470/सी/एक्स एक्स/34/सी/30, दिनांक 17-2-70 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम प्रति अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस कलकत्ता सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत करवाया गया है और उसके पूरे मूल्य का उपयोग कर लिया गया है। विदेशी मुद्रा विनिमय प्रेषण कार्य के लिये इसकी आवश्यकता है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने यह बताते हुये एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है। मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या आई/ए/1011470/सी/एक्स एक्स/34-सी/30, दिनांक 17-2-80 मूल्य 67228/- रुपये की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अस्थानस्थ हो गई है और आवेदक को अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिये लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण कार्य सम्बन्धी प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या 289-90-4/14/69-70-ए यू-3(2)]

टी० टी० ला,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Dy. Asstt. Iron & Steel Controller)

ORDER

Madras, the 1st December 1971

SUBJECT:—*Cancellation of Exchange Control and Customs Clearance Purposes copies of licence Nos. P/S/8539111/C/XX/38/M/31-32/19/516, P/S/8539112/T/OR/38/M/31-32/19/516 and P/S/8539113/KR/ML/38/M/31-32/19/516 all dated 7-1-71 for Prime C.R.C.A. Sheets below 5MM in thickness and Mild Steel Sheet Cuttings and Defectives in straight lengths or in coils excluding all Sheet Cuttings and Defective Sheets for a value of Rs. 5000/- Rs. 2,500/- and Rs. 2,500 respectively in favour of M/s. Crown Castings Private Limited, B-49/1, and 2 Industrial Estate, Hyderabad-18.*

S.O. 1462.—M/s. Crown Castings Private Limited, B-49/1&2, Industrial Estate, Sanatnagar, Hyderabad-18 were issued three licences bearing Nos. P/S/8539111/C/XX/38/M/31-32/19/516 P/S/8539112/T/OR/38M 31-32 19/516 and P/S/8539113/KP/ML/38/M/31-32/19/516 all dated 7th January 1971 for the period April 70/March, 71 for import of Prime C.R.C.A. Sheets below 5mm in thickness and Mild Steel Sheet Cuttings and defectives in straight lengths or in coils excluding

all Sheet Cuttings and defective sheets as per the policy for 70-71 for a value of Rs. 5000, Rs. 2500 and Rs. 2500 respectively. The firm have applied for duplicate copies of Exchange Control and Customs Purposes copies of the licences in question on the ground that the original Exchange Control and Customs Clearance copies have been lost. In support of this contention they have filed three Affidavits to the effect that the said Exchange Control and Customs Clearance Purposes copies have been lost without having been Registered with any Customs Authority and not utilised at all.

I am satisfied that the Exchange Control copies and Customs Clearance Purpose copies of the import licences Nos. P/S/8539111/C/XX/38/M/31-32/19/516, P/S/8539112/T/OR/38/M/31-32/19/516 and P/S/8539113/KR/ML/38/M/31-32/19/516 all dated 7th January, 1971 have been lost and direct that duplicate Exchange Control and Customs Purposes copies of the import licences should be issued to this applicant.

The original Exchange Control and Customs Clearance Purposes copies of the licences No. P/S/8539111/C/XX/38/M/31-32/19/516, P/S/8539112/T/OR/38/M/31-32/19/516 and P/S/8539113/R/ML/38/M/31-32/19/516 all dated 7th January, 1971 are hereby cancelled.

[No. IMP/SM/L.III/29-30/516.]

M. VIRARAGHAVAN,
Dy. Chief Controller of
Imports and Exports.

(उप मुख्य नियंत्रक, लोहा तथा इस्पात का कार्यालय)

आदेश

मद्रास, 1 दिसम्बर, 1971

विषय :— सर्वश्री क्राउन कास्टिंक प्रा० लि०, बी. 49/1 तथा 3 इंडस्ट्रियल इस्टेट हैदराबाद–18 को सभी किस्म की शीट्स कटिंग्स और नुक्सवाली को छोड़कर 5 एम एम से कम मोटाई वाली प्राइम सी०आर०सी०ए०शीट्स और सीधी लम्बाई में नुक्सवाली अथवा लच्छों में नर्म इस्पात शीट्स कटिंग्स के आयात के लिए क्रमशः 5000 रु०, 2500 रु० तथा 2500 रु० के लिए जारी किये गए आयात लाईसेंस संख्या पी/एम/8539111/सी/एक्स एक्स/38/एम 31–32/19/516, पी/एस/8539112/टी/ओ आर/38/एम/31.32/19/516 तथा पी/एस 8539113/के आर/एम एल/30/एन3/1.32 19/516सभी दिनांक 7–1–71 की मद्रा विनियम नियंत्रण तथा सीमाशुल्क निकासी कार्य संबंधी प्रतियों को रद्द करना।

एस० ओ० 1462:—सर्वश्री क्राउन कास्टिंग प्रा०लि०, बी49 1 तथा 2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सनात नगर, हैदराबाद 18 को अप्रैल 1970-मार्च 1971 अवधि के लिए 70–71 नीति के अनुसार सभी किस्म की शीट्स कटिंग्स और नुक्सवाली को छोड़कर 5 एम एम से कम मोटाई वाली प्राईम सी० आर०सी०ए०शीट्स और सीधी लम्बाई में नुक्सवाली अथवा लच्छों में नर्म इस्पात शीट्स कटिंग्स के आयात के लिए क्रमशः 5000रु०, 2500रु० तथा 2500 रु० के लिए लाईसेंस संख्यां पी।एस।8539111।सी एक्स एक्स 38/एम/31.32/19/516, पी/एस/8539112/टी/ओ आर 38/एन/31.32/19/516 तथा पी/एस/8539113/के आर/एम एल/38/एम/31.32/19/516 सभी दिनांक 7-1-1971 को स्वीकृत किए गए थे। फर्म ने विषयाधीन लाईसेंसों की अनुलिपी सीमाशुल्क कार्य संबंधी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क काय संबंधी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने तीन शपथ पत्र यह बताते हुए दाखिल किए हैं कि उक्त सीमाशुल्क कार्य संबंधी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां बिना किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाये और बिना उपयोग किए ही खो गई हैं।

मैं इससे संतुष्ट हूं कि लाईसेंस संख्या एपी/एस/8539111/सी एक्स एक्स/38/एम/31.32/19/516, पी/एस/8539112/टी/ओ/आर/38।एम/31.32/19/516 तथा पी/एस/8539113 के आर/एमएल/38/एन/31–32/19/516 सभी दिनांक 7-1-71 की मूल सीमाशुल्क कायसंबंधी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं और निदेश देता हूं कि आवेदक को उपर्युक्त आयात लाईसेंसों की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिए।

लाईसेंस संख्याएं पी/एस/8539111/सी/एक्स एक्स।38। एम/31.32/19/516, पी/एस/8539112/टी ओ आर/38/एम/31–32/19/516 तथा पी/एस/8539113/आर/एम एल/38/एम/31–32/19/516 सभी दिनांक 7–1–71 की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या आई एम पी/एस एम/एल–3/29.35/516]

एम० वीराराघवन,

उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

Madras, the 11th February, 1972.

SUBJECT:—*Cancellation of licence bearng No. P/S/1701523 (both Customs and Exchange) dated 10th August, 1971.*

S.O. 1463.—M/s. Halima Industries, 39, Kandappa Chetty Street Madras, 1. were issued a licence bearing No. P/S/1701523/C/XX)40)31-32, dated 10th August, 1971 for Rs. 2,500 for April/March, 1971 period for import of the items "Aromatic Chemicals and Natural Essential Oils. The firm have applied for issue of duplicate copies of both Customs and Exchange Control copies of licences in question on the ground that the original licences have been misplaced without having been utilised at all. In support of this contention, they have filed an affidavit.

I am satisfied that both the Customs and Exchange Control copies of the original licences have been lost and duplicate of the same may be issued to the firm.

The original customs and exchange control copies of the licences in question are hereby cancelled.

[No. Agar/560/AM.71/SSI.I.]

SUBJECT:—*Cancellation of Exchange Control Copy of licence bearing No. P/S/1669213 dated the 15th January, 1971.*

S.O. 1464.—M/s. M.S.T.V. Neethimohan and Company Madurai, were issued a licence bearing No. P/S/1669213 dated 15th January, 1971, for April/March 1971 period for import of the items "Aromatic Chemicals" (S. No. 22:31/V) for Rs. 20,502/. The firm have applied for issue of duplicate of the Exchange Control copy of the above licence in question on the ground that the original Exchange Control Copy has been lost

after partly utilising the same for Rs. 16404. In support of this contention, they have filed an affidavit.

I am satisfied that the Exchange Control Copy of the original licence has been lost and duplicate of the same be issued to the firm.

The original Exchange Control Copy of the licence in question is hereby cancelled.

[No. Agar/233/AM.715SSI.I.]

M. VIRARAGHAVAN,
Dy. Chief Controller of Imp. & Exp.

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Bombay the 20th December, 1971

S.O. 1465.—Licences Nos. P/S/8023177 and P/S/8023178 both dated 20th October, 1970 of the value of Rs. 5,000/- each for import of (1) Prime Quality MSCCA/HP Sheets of 1.6 mm and thinner (2) Prime Quality Spring Steel wire 0:254 mm and thinner were issued to M/s. Vasuki Engineering Works, 38/D, Indusfrial Estate, Rajkot-2, subject to the conditions that they would submit clarifications of the discrepancy in the surnames of their partners shown in the application and I.V.C. Memo.

2. Thereafter, a show cause notice No. 1/71/71/I&S/Enf. dated 9th August, 1971 was issued asking them to show cause within 15 days as to why the said licences in their favour should not be cancelled on the ground that they have failed to fulfil the said conditions of the licences in terms of Clause 9, sub clause (cc).

3. The show cause notice addressed to M/s. Vasuki Engineering Works, Rajkot has been received back with the remark "Not claimed".

4. Having regard to what has been stated in the preceeding pargaraph, the undersigned is satisfied that the licences in question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. Therefore the undersigned in exercise of the powers vested in him under Clause 9 sub-clause (cc) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the licences Nos. P/S/8023177 and P/S/8023178 both dated 20th October, 1970 for Rs. 5,000/- each issued in favour of M/s. Vasuki Engineering Works, 38-D, Industrial Estate, Rajkot-2.

[No. 1/71/71/I&S/Enf.]

N. BANERJI,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रण का कार्यालय)

आदेश

बम्बई, 20 दिसम्बर 1971

एस० ओ० 1465.—सर्वश्री वासुकी इंजीनियरिंग वर्क्स, 38/डी, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजकोट 2 को लाइसेंस संख्याएं पी० 8023177 और पी० एस० 8023178 दोनों का दिनांक 20/10/1970 था और प्रत्येक का मूल्य 5000 रु० था, वे (1) 1.6 मि० मी० की और इससे पतली एम एस सी० आर० सी० ए० बी० पी० शीस्ट (2) 0.254 मि० मी० के ओ प्रारइम क्वालिट स्प्रिंग वायर के आयात के लिए इस शर्त के अधीन जारी किए गए थे कि वे आवेदन पत्र और आयकर सत्यापन प्रमाणपत्र आवेदन में प्रदर्शित अपने भागीदारों के उपनामों में विसंगत का स्पस्टीकरण प्रस्तुत करेंगे ।

2. इसके बाद एक कारण बताओ नोटस सं० 1/71/71 आई एंण्ड एस०/इन्फ दिनांक 9-8-1971, यह पूछते हुए जारी किया गया था कि 15 दिनों के भीतर यह बतावें कि उनको जारी किए गए उक्त लाइसेंस इस आधार पर रद्द क्यों न कर दिए कि वे धारा 9, उपधारा (सी०सी०) के अनुसार लाइसेंसों की उक्त शर्तें पूर्ण करने में असफल रहें हैं ।

3. सर्वश्री वासुकी इंजीनियरिंग वर्क्स, राजकोट के नाम सम्बोधित किया गया कारण बताओ नोटिस "नहीं लिया गया" "अभ्युक्ति के साथ वापस प्राप्त हो गया है ।

4. पूर्वोक्त कंडिका में उल्लिखित तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषययाधीन लाइसेंसों को रद्द कर दिए जाने चाहिएं या अन्यथा अप्रभावित कर दिए जाने चाहिए इसलिए, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 उपधारा (सी०सी) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री वासुकी इंजीनियरिंग वर्क्स, 38-डी, इंनिजियरिंग इस्टेट, राजकोट-2 को प्रत्येक 5000 रु० के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्याएं पी/एस/8023177 और पी/एस/8023178 दिनांक 20-10-1970 को एतद्द्वारा रद्द करता है ।

[स० 1/71/71 आई०एंडएस०/एन्फ]

एन० बनर्जी,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 19th January 1972

S.O. 1466.—M/s. Sikand Limited, Faridabad were granted import licence No. P/D/2184612 dated 30th July, 1971 from General Area for the import of spare parts for Rs. 58,850. They have requested for the issue of duplicate customs copy of the licence on the ground that the original custom copy have been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence has been fully utilised. The licence was registered with Bombay Custom House, Bombay.

In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the import licence No. P/D/2184612 dated 30th July, 1971 (Custom copy) has been lost and directs that duplicate customs copy of the said licence should be issued to them. The original customs copy of the licence is cancelled.

[No. NB/12.B/76.71/RMI/3165.]

A. K. SARKAR,
Dy. Chief Controller,
for Chief Controller of Imports & Exports.

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली 19 जनवरी 1972

एस० ओ० 1466—सर्वश्री सिकन्द लि०, फरीदाबाद को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से फालतू पुर्जों के आयात के लिए 58,850 रु० के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2184612 दिनांक 30-7-1971 प्रदान किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की सीमा-शुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति उनसे खो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइसेंस का उपयोग सम्पूर्ण मूल्य के लिए कर लिया गया है। लाइसेंस सीमाशुल्क कार्यालय, बम्बई में पंजीकृत कराया गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक फर्म ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। निम्नहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2184612 दिनांक 30-7-1971 (सीमाशुल्क निकासी प्रति) खो गया है और निदेश देता है कि आवेदक फर्म को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या :—एन बी/12/बी/70-71/आर एम. 1/3165]

ए० के० सरकार,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Bombay, the 25th January, 1972.

SUBJECT:—*Order of cancellation of Customs purposes copy of licence No. P/S/1661709/C/XX/39/R/31-32, dated 28th June, 1971, for Rs. 6,675/- 2nd half AM. EPSE issued in favour of M/s. Shanti Industries, Rajkot.*

S.O. 1467.—M/s. Shanti Industries, Rajkot, was granted import licence No. P/S/1661709/C/XX/39/R/31-32 dated 28th August, 1971 for Rs. 6,675/- for the import of Taper Roller Bearings, Copper Tubes, Oil seals and Sodium Cyanide for the licensing period April/March 71 from GCA. They have applied for duplicate copy of Customs purpose copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purpose copy of the licence has been lost or misplaced. It is further stated that the original Customs purpose copy of the licence was not registered with any Customs House and not utilised.

2. In support of their contention, the applicant has filed an affidavit on stumped paper duly attested before Taluka Magistrate, Rajkot. I am satisfied that the original Customs purpose copy of licence No. P/S/1661709/XX/39/R/31-32 dated 28th June, 1971 has been lost or misplaced and direct that a duplicate Customs purpose copy of licence should be issued to the applicant. The original licence No. P/S/1661709 dated 28th June, 1971 is cancelled.

[No. 2/72.]

B. C. BANERJEE,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports,
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कार्यालय

आदेश

बम्बई जनवरी 1972

विषय.—सर्वश्री शान्ति इंडस्ट्रीज, राजकोट को अप्रैल मार्च 71 के द्वितीय अर्ध वर्ष के लिए जारी किये गए लाइसेंस सं० पी/एस/1661/709/सी/एक्स एक्स/39/आर/31-32 दिनांक 28-6-71 मूल्य 6675 रू० की सीमाशुल्क निकासी प्रति को रद्द करने का आदेश।

एस० ओ० 1467—सर्वश्री शान्ति इंडस्ट्रीज, राजकोट को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से टेपर रोलर बियरिंग्स, तांबा ट्यूब्स, तेल सील और सोडियम साइनाइड के आयात के लिए लाइसें अवधि अप्रैल मार्च 71 के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/एस/1661/1709/सी एक्स एक्स/39 आर/31-32 दिनांक 28-8-1971 मूल्य 6675 रु० प्रदान किया गया था। उन्होंने उपयुक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति किसी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराई थी और उसका उपयोग नहीं किया था।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने ताल्लुक मजिस्ट्रेट, राजकोट के सामने विधिवत साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं० पी/एस/166/1709/सी/एक्स एक्स/38/आर/31-32 दिनांक 28-6-71 की मूल सीमा शुल्क प्रति खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है और निर्देश देता हूं कि लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रति की अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल लाइसेंस सं० पी/एस/1661/1709 दिनांक 28-6-71 रद्द किया जाता है।

[संख्या 2/72]

बी० सी० बनर्जी,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 3rd February 1972

S.O. 1468.—M/s. Hindustan Steel Ltd. P.O. Hinco, Ranchi (Bihar), were granted an import No. G/A/1045214/C/XX/30/H/31-32/ML-II dated 16th April,

1971 for Rs. 18,800/- for the import of Fecit electric calculators for Rs. 14,000/- and electric typewriters for Rs. 4800/- from General Currency Area. They have now requested for the issue of Duplicate Custom Clearance Permit only of the licence on the ground that the original licence (Customs Clearance Permit only) No.G/A/1045214 dated 16th April 1971 has been misplaced/lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence (CCP only) was misplaced/lost without its being utilised at all. The said Customs copy of the licence has not been registered with any Customs authority.

In support of their contention the aplicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Custom copy of the licence No. G/A/1045214 dated 16th April, 1971 has been lost and directs that a duplicate copy of the said licence (custom clearance permit) should be isued to them. The original licence (CCP only) is cancelled.

[No. F. 57/OM/70-71/ML-II.]

S. K. USMANI,
Dy. Chief Controller of Imports and Exports,
for Chief Controller of Imports and Exports.

(मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1972

एस० ओ० 1468-सर्वश्री हिन्दुस्तान स्टील लि०, डाकखाना हिनको, रांची (बिहार) को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से 14,000 रु० के लिए फेसिट विद्युत् गणक और 4800 रु० के लिए विद्युत् टाइप राइटर के आयात के लिए 18,800 रु० का एक आयात लाइसेंस सं० जी/ए/1045214/सी/एक्स एक्स/39/एच/31-32/एम एल-2 दिनांक 16-4-71 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उपयुक्त लाइसेंस की केवल अनुलिपि सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस) केवल सीमा-शुल्क निकासी परमिट) सं० जी/ए/1045214 दिनांक 16-4-1971 उनके द्वारा खो गया है/अस्थानस्थ हो गया है । लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस (केवल सीमा-शुल्क निकासी परमिट) बिना उपयोग किए ही अस्थानस्थ हो गया था/खो गया था । लाइसेंस की उपयुक्त सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराई गई है ।

8 उपयुक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि लाइसेंस सं० जी/ए/1045214 दिनांक 16-4-71 की मूल सीमा शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को उपयुक्त लाइसेंस की अनुलिपि (सीमा शुल्क निकासी परमिट) प्रति जारी की जानी चाहिए । मूल लाइसेंस (केवल सीमा शुल्क निकासी परमिट) रद्द किया जाता है ।

[संख्या 57/ओ एम/70-71/एम-एल-2]

एस० के० उस्मानी,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 1972.

S.O. 1469.—M/s. Tribeni Tissues Ltd., 8, Middleton Street, Calcutta-16 were granted an import licence No. P/C/2061578/S/KQ/35/H/29-30/KQ'68/Sp. Cell dated 23-6-1970 for Rs. 3,75,000/- (Three Lakhs and Seventy Five Thousand only). They have surrendered the licence to this office for cancellation as they are no longer interested in operating the same.

2. I am accordingly satisfied that the Company does not want to utilise the said licence. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes/ Exchange Control Purposes Copy of Licence No. P/C/ 2061578 dated 23-6-1970 issued to M/s. Tribeni Tissues Ltd., Calcutta-16 is hereby cancelled.

[No. Spcl./T.3/KL.6/69-70.]

S. R. MINOCHA,
Jt. Chief Controller of Imports and Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली 3 फरवरी, 1972

एस०ओ० 1469—सर्वश्री त्रिवेणी टिसू लि०, 3 मिडलटन स्ट्रीट, कलकत्ता—16, को 3,75,000/- रूपये (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) के लिये एक आयात लाइसेंस संख्या : पी/सी/2061578/एस/के क्यू/35/एच/29-30/के क्यू. 68/ विशेष प्रकोष्ठ, दिनांक 23-6-1970 प्रदान किया गया था । चूंकि लाइसेंस को आगे परिचालन करना नहीं चाहते इसलिए उन्होंने लाइसेंस को रद्द करने के लिए इस कार्यालय को समर्पित कर दिया है ।

2. तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि कम्पनी उक्त लाइसेंस का उपयोग करना नहीं चाहती । इसलिए यथा संशोधित, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री त्रिवेणी टिसू लि०, कलकत्ता—16 को जारी किये गये लाइसेंस संख्या : पी/सी/2061578, दिनांक 23-6-1970 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन/मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

[संख्या स्पेशल/टी.3/केएल/6/69-70]

श्रीराम मिनोचा,
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 18th March 1972

S.O. 1470.—M/s. Patliputra Drinks Pvt. Ltd., New Delhi were granted an import licence No. P/C/ 2050454/A/SH/29/H/28/CG.III dated 13th December,

1968 for Rs. 5,14,900/-(Rupees Five Lakhs Fourteen Thousands and Nine Hundred only). They have applied for the issue of a duplicate copies for Customs Purposes and Exchange Control Purposes, of the said licence on the ground that the original customs purposes and exchange control copies have been lost/misplaced. It is further stated that the original customs purposes copy was not registered with any Customs House and both the Custom purposes and Exchange Control purposes copies of the licence were not utilised at all.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit and I am accordingly satisfied that the original custom purposes and exchange control purposes copies of the said licence have been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9 (cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended, the said original customs purposes and exchange control purposes copies of licence No. P/C/2050454/A/SH/29/H/28/CG.III dated 13th December, 1968 issued to M/s. Patliputra Drinks Pvt. Ltd., New Delhi are hereby cancelled.

3. A duplicate customs purposes copy and a duplicate Exchange Control purposes copy of the said licence are benig issued separately to the licence.

[No. 26/12/68-69/CG.III/3226.]

S. A. SESHAN,
Dy. Chief Controller Of Imports and Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972

एस० ओ० 1470—सर्वश्री पाटलिपुत्र ड्रिन्क्स प्रा० लि०, नई दिल्ली को 5,14,900/- रुपये (पांच लाख चौदह हजार नौ सौ रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या/पी/सी/2050454/ए/एस एच/29/एच/28/सी जी-3, दिनांक 13-12-1968 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपियों के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति किसी सीमा शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराई गई थी और सीमाशुल्क निकासी प्रति तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति दोनों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया था।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है और तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सीसी) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री पाटलिपुत्र ड्रिन्क्स प्रा० लि०, नई दिल्ली को जारी किए गए लाइसेंस संख्या: पी/सी/2050454/ए/एस एच/29/28/सीजी-3, दिनांक 13-12-1968 की उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[सं० 26/12/68-69/सी०जी०III]

एस० ए० शेषन,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 31st January 1972

S.O. 1471.—The Chief Engineer for Electricity, Tamil Nadu Electricity Board was granted licence No. G/A/1043530/C/XX/37/H/31.32 dated 11-12-70 for import of spares for 33 KV and 22 KV Reyrole Oil Circuit Breaker from GCA. The Chief Engineer, Tamil Nadu Electricity Board has reported that exchange control copy of the licence has been misplaced and he has requested to issue a duplicate copy of the same.

In support of their contention that applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Exchange Control copy of the licence has been lost and directs the duplicate copy of the said exchange control copy of the licence be issued.

The original exchange control copy of the licence has been cancelled. A duplicate copy of the same is being issued separately.

[No. SG/242/70.71/PLS/B.]

By Order,
SARDUL SINGH,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports,
for Chief Controller of Imports & Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1972

एस० ओ० 1471.—मुख्य अभियन्ता विद्युत, तामिलनाडु विद्युत बोर्ड को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से 33 के वी तथा 22 के वी रेरोल आयल सर्किट ब्रेकेट के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस सं० जी/ए/1043530/सी/एक्स एक्स/37/एच/31-32 दिनांक 11-12-70 प्रदान किया गया था। मुख्य अभियन्ता, तामिलनाडु विद्युत बोर्ड ने सूचना दी है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए अनुरोध किया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि लाइसेंस की उक्त मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए।

लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द कर दी गई है। उसकी अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या एस जी/242/70-71/पी एल एस/बी]

आदेश से
सरदूल सिंह,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1972.

S.O. M/s. The Hindustan Times Ltd., New Delhi were granted an import licence (Replacement licence

without exchange copy) No. P/I/3030810/S/AN/40/H/33-34 dated 1st July, 1971 for Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand only). They have applied for the issue of a duplicate Customs Purposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes copy was not registered with any Customs authorities. It was utilised for NIL and the balance available on it was Rs. 15,000/- (Rupees fiteen thousand only).

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Notary Public Union Territory, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Puroses copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9 (cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended the said orgiinal Customs Purposes copy of licence (Replacement licence without Exchange copy) No. P/I/3030810/S/AN/40/H/33-34 dated 1st July, 1971 issued to M/s. Hindustan Times Ltd., New Delhi is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes (Replacement cence) copy of the said licence is being issued separately to the licencee:

[No 18/115-V/67-68/NPCIA.]

SARDUL SINGH,

Dy. Chief Controller of Impts. & Expts.

(मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 18 मार्च 1972

एस०ओ० 1472.—सर्वश्री दि हिन्दुस्तान टाइम्स लि०, नई दिल्ली को 1500 रुपए (पन्द्रह हजार रुपए मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस (प्रतिपूर्ति लाइसेंस मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के बिना) संख्या : पी/आई/3030810/एस०/एन/40एल/33-34, दिनांक 1-7-71 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन के प्रति लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है/ अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराई गई थी इसका कुछ भी उपयोग नहीं किया गया था और इस पर उपलब्ध शेष धनराशि 15,000 रुपए (पन्द्रह हजार रुपए मात्र) है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक, दिल्ली से प्राप्त एक प्रमाणपत्र के साथ एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए यथा संशोधित, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री दि हिन्दुस्तान टाइम्स लि० नई दिल्ली को जारी किए गए लाइसेंस (प्रति पूर्ति लाइसेंस मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के बिना) संख्या : पी/आई/3030810/एसएन/40/एच/33-34, दिनांक 1-7-71 की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

3. लाइसेंसधारी को उक्त लाइसेंस की एक अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन (प्रतिपूर्ति लाइसेंस) प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० 18/115/5/67-68/ए पीसी 1-ए]

सरदूल सिंह,

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 2nd March 1972

S.O. 1473.—M/s. Indian National Scientific Documentation Central, New Delhi were granted an import licence No. G/A/1042208/R/NE/35/H30-31/ILS, dated 7th July, 1970 for Rs. 27,500 (Rupees twenty seven thousand and five hundred only). They applied for the issue of duplicate Customs Purposes/copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes/copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes/Copy was registered with the Customs authorities at Bombay and was not utilised for any amount.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes/copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the power conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7th December, 1955 as amended, the said original Customs: Purposes/Copy of Licence No. G/A/1042208/R/NE/35/H/30-31/ILS, dated 7th July, 1970 issued to M/s. Indian National Scientific Documentation Centre, New Delhi is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes/copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. I-24/Instt/AM-71/ILS/4236.]

K. N. KAPOOR,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली 2 मार्च, 1972

एस० ओ० 1473—सर्वश्री इंडियन नेशनल साइन्टिफिक डाक्यूमेंटेशन सेंटर, नई दिल्ली को 27,500 रु० (सताइस हजार पांच सौ रु० मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं० जी/ए/1042208/आर/एन ई/35/एच/30-31/आई एल एस दिनांक 7-7-70 प्रदान किया गया था। जिन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है। जहां भी उल्लेख किया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी बम्बई से पंजीकृत कराई गई थी और उसका उपयोग किसी भी धनराशि के लिए नहीं किया गया था।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क

निकासी प्रति खो गई है। अतः यथा संशोधित, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री इंडियन नेशनल साइंटिफिक डाक्यूमेंटेशन सेंटर, नई दिल्ली को जारी किए गए लाइसेंस सं० जी/ए/1042208/आर/एन ई/35/एच/30-31 आई एल एस दिनांक 7-7-70 की उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या 1-24/इंसट/ए एम 71/आई एल एस/4236]

के० एन० कपूर, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1972.

S.O. 1474.—M/s. Radiola Corporation Najafgarh Road, Industrial Area, New Delhi-15 were granted Import Licence P/D/3171854/C/XX/32/H/29.30/ Radio dated 30th September, 1969 under G. C. A. for import of Raw Materials/Components for the manufacture of Radio Receivers valued at Rs. 5,000-only.

2. They have requested for the issue of duplicate Exchange Control purposes copy of the above said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes Copy has been lost or misplaced by them. It has been further reported by the licencee that the licence had an unutilised balance of Rs. 528/ only. The licence was registered with Foreign Post Office, New Delhi.

3. In support of their contention, the applicants have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control Purposes Copy of Import Licence No. P/D/2171854/C/XX7dated 30th September, 1969 has been lost or misplaced and directs that a Duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Purposes Copy hereby cancelled.

4. The Duplicate Exchange Control Purposes Copy of the licence is being issued separately.

[No. Radio/11(1)/69-70/RM.II.]

G. D. BAHL,
Dy. Chief Controller of Imports & Export.
For Chief Controller of Imports & Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च 1172

एस० ओ० 1474.—सर्वश्री रेडियोला कारपोरेशन, 18ए नजफगढ़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-15 को रेडियो रिसीवरों के निर्माण के लिए कच्चे माल/संघटकों के आयात के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अंतर्गत 5000 रु० मूल्य के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2171854/सी/एक्स एक्स/32/एच 29-30 रेडियो दिनांक 30-9-69 प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति उनसे खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइसेंस पर 528रु० का उपयोग करना बाकी था। लाइसेंस विदेश-डाक कार्यालय नई दिल्ली में पंजीकृत कराया गया था।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदकों ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। निम्नहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2171854/सी/एक्स एक्स दिनांक 30-9-69 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि इसकी अनुलिपि आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है।

4. लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[सं० रेडियो/11(1)/69-70/आर०एम०-2]

जी० डी० बहल, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 10th April, 1972

S.O. 1475.—M/s. Marshall Sons & Co. (Mfg.) Ltd. Madras were granted an import licence No. P/D/ 2175597/C/XX/37/H/31-32, dated 10th November 1970 for import of Raw materials/Components worth Rs. 25,000/- under Free Resource. They have now requested this office to issue Duplicate Custom Copy of the said licence on the ground that original has been lost without having been registered at any Port & utilised at all. They have furnished necessary affidavit as per I.T.C. Rules in support of their request.

2. The undersigned is satisfied that original Custom Copy of Import Licence No. P/D/2175597/C/XX/37/ H/31-32, dated 10th November, 1970 has been lost and directs that a duplicate copy of the same may be issued. The original Custom Copy of the above licence is hereby cancelled.

[No. Mach-M-7(2) AM70/RM4.]

G. D. BAHL,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल 1972

एस० ओ० 1475.—सर्वश्री मार्शल सन्ज एन्ड कम्पनी (मैनु०) लि०, मद्रास को 25,000 रुपये के लिए कच्चे माल/संघटकों के आयात के लिए स्वतन्त्र स्रोतों के अन्तर्गत आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2175597/सी/एक्स एक्स/37/एच/31-32, दिनांक 10-11-70 प्रदान किया गया था। अब उन्होंने इस कार्यालय को उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस बिना पंजीकृत कराए और बिल्कुल बिना आयोग उपयोग ही खो गया है। अपने अनुरोध के समर्थन में उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नियमों के अनुसार आवश्यक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।

2. अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/डी/ 2175597/सी/एक्स एक्स/37/एच/31-32, दिनांक 10-11-70 की कुल सीमा शुल्क प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उसकी अनुलिपि प्रति जारी की जाए। उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या मशीन-एम-7(2)/एएम-70/आरएम-4]

जी० डी० बहल, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 4th April, 1972

S.O. 1476.— M/s. Somany Pilkington's Ltd 2-Wellesley Place, Calcutta-1 were granted Import licence No. P/C/2021211/S/KE/22/H/29-30, dated 4th November 1969 for Rs. 16,25,696/-. They have applied on 11th February 1972 for issue of duplicate import licence (Custom Purposes copy only) on the ground that the original import licence (Custom Purposes copy only) has been lost after Registering with the Collector of Customs, Calcutta and utilising partly for a c.i.f. value of Rs. 14,95,532/-, leaving an unutilised balance of Rs. 1,30,164/-.

2. In support of their request the applicants have filed an affidavit duly sworn in before Oath Commissioner, Delhi. The applicants have also furnished letter No. S24(M/P)-3/72A, dated 17th January 1972 in original from the Assistant Collector of Customs for Appraisement (Machy. I), Customs House, Calcutta certifying unutilised amount as Rs. 1,30,164/- against aforesaid licence (Custom Purposes copy). I am accordingly satisfied that the original licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred on me under sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7th December 1955 as amended, the sad original licence No. P/C/2061211/S/KK/33/H/29-30, dated 4th November 1969 (Customs Purposes copy only) issued to said M/s. Somany Pilkington's Ltd., is hereby cancelled.

3. A duplicate of the said licence (Custom Purposes copy only) for an unutilised value of Rs. 1,30,164/- is being issued separately.

[No. CG.IV/33(18)/68-69.]

H. D. GUPTA,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

संयक्त—मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय बम्बई

आदेश

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1972

एस०ओ० 1476.—सर्वश्री सोमानी, पिल्किंगटंस लि० 2-वेलेजली प्लेस, कलकत्ता-1 को 16,25,696 रु० के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/सी/2061211/एस/के के/33/एच/29.30 दिनांक 4-11-69 प्रदान किया गया था । उन्होंने दिनांक 11-2-72 को आयात लाइसेंस (केवल सीमाशुल्क निकासी प्रति) की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल आयात लाइसेंस (केवल सीमाशुल्क निकासी प्रति) सीमाशुल्क समाहर्ता, कलकत्ता से पंजीकृत कराने के बाद और 14,95,532 रु० के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक उपयोग करने के बाद, 1,30,164 रु० बिना उपयोग किए शेष रहते हुए खो गया है ।

2. अपने आवेदन के समर्थन में आवेदकों ने शपथ अधिकारी, दिल्ली के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । आवेदकों ने सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता, मूल्यांकन (मशीनरी), सीमाशुल्क कार्यालय, कलकत्ता से यह प्रमाणित करते हुए कि पूर्वोक्त लाइसेंस (केवल सीमाशुल्क निकासी प्रति) के प्रति 1,30,164 रु० की धनराशि का उपयोग करना शेष है, एक पत्र सं० एस 24(एम/पी)/3-72ए दिनांक 17-1-72 भी मूल रूप में प्रस्तुत किया है । तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस खो गया है । अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की उपधारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त सर्वश्री सोमानी पिल्किंगटन्स लि० को जारी किए गए उक्त मूल लाइसेंस सं० पी/सी/2061211/एस/के के/33/एच/29.30 दिनांक 4-11-69 (केवल सीमाशुल्क निकासी प्रति) को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. बिना उपयोग किए गए शेष मूल्य 1,30,164 रु० के लिए उक्त लाइसेंस (केवल सीमाशुल्क निकासी प्रति) की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्याः सी–जी-4/33(18)/68-69]

एच० डी० गुप्ता,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 10th April, 1972

S.O. 1477.—M/s. The Alkali and Chemical Corporation of India Ltd., P.O. Rishra were granted licence No. P/D/2184556, dated 22nd July, 1971 from West Germany for import of spares valued Rs. 2,00,000/-. They have requested for issue of duplicate Custom copy of the said licence on the ground that the original copy of the licence has been lost without utilising it. The licence has not been registered with any customs.

2. In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Custom copy of licence No. P/D/2184556, dated 22nd July 1971 has been lost and directs that duplicate copy of the licence in question should be issued to them. The original copy is cancelled.

3. The duplicate Custom copy of the licence is being issued separately.

[No. Ch/A-23(1)/A.M.72/R.M.3/46]

J. SHANKAR,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1972

एस०ओ० 1477.—सर्वश्री दि अल्कली एंड केमिकल कार्पो० लि०, भारत, पो० आफिस रिशरा को पश्चिम जर्मनी से फालतू पुर्जों के आयात के लिए 2,00,000 रु० के लिए लाइसेंस सं० पी/डी/2184556, दिनांक 22-7-71 प्रदान किया गया था । उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि बिना उपयोग किए ही लाइसेंस की मूल प्रति खो गई है । लाइसेंस को किसी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराया गया है ।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० पी/डी/2184556, दिनांक 22-7-71 की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई है और निदेश देता है कि विद्याधीन लाइसेंस की अनुलिपि प्रति उन्हें जारी की जानी चाहिए । मूल प्रति को रद्द किया जाता है ।

3. लाइसेंस की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं० सीएच/ए-23(1)/ए-एम०72/आर एम० 3/46]

जे० शंकर,

उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 18th February, 1972

S.O. 1478.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment, known as Messrs Sarvalle (India) Private Limited, 'Corinthian' B-5, First floor 17 Arthur Bunder Road, Colaba, Bombay-5 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (10 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of January, 1971.

[No. S. 35017/65/71-PF II.]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

श्रम और रोजगार विभाग

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1972

का० आ० 1478:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सवेला (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड 'कोरिन-थियान' बी-5, प्रथम फ्लोर, 17, आर्थर बन्दर रोड, कोलाबा, बम्बई-5 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजकों और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 की जनवरी के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस-35017(65)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1479.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment, known as Messrs Pushpaka Aviation Private Limited, Sadhana Rayon House, Dr. Dada Bhoy Nauroji Road, Bombay-1, including its branch at 103, Defence Officers Colony Nandan Bakkan, St. Thomas Mount, Madras-16, have provisions of the Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1971.

[No. S.35017/67/71/PF-II.]

का० आ० 1479:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पुष्पक एविएशन प्राईवेट लिमिटेड साधना रेयन हाउस डा० दादा भाई नौरोजी रोड, बम्बई-1 तथा इसकी शाखा-103, डिफैंस आफिसिर्स कालोनी, नन्दनबक्कन, सेंट थामस माउंड मद्रास-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के मार्च के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35017(67)/71-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 3rd March 1972

S.O. 1480.—Whereas the Central Government was satisfied that India Star Diamond Factory was situated in Bardoli area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Surat in the State of Gujarat;

And, whereas by virtue of its location in a sourse area the aforesaid factory was granted examption from the payment of the employers' special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 885, dated the 8th March, 1967;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Bardoli area in the district of Surat in the State of Gujarat has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act,

1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification against Serial No. 10, the entry "Bardoli" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted.

[No. F. S-38018(4)/71-HI(Part I).]

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1972

का० आ० 1480.—यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि मैसर्स इंडिया स्टार डायमांड फैक्टरी, बरदोली क्षेत्र में स्थित था जो गुजरात राज्य के सूरत जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था;

और, यत: उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 885 तारीख 8 मार्च, 1967 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते;

और, यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि गुजरात राज्य के सूरत जिले में वरदोली क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है;

अत:, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तंभ 3 में क्रम संख्या 10 के सामने "बरदोली" प्रविष्टि और स्तंभ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जायेगी ।

[फा० सं० एस-3018(4)/71-एचआइ]

S.O. 1481.—Whereas the Central Government was satisfied that State Electric Supply Power House was situated in Tezpur area which was a sparse are (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Darrang in the State of Assam.

And, whereas by virtue of its location in a sparse area the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chaper V of the said Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2546, dated the 1st August, 1962.

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Tezpur area in the district of Darrang in the State of Assam has now exceeded 500 and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, hereby:—

In the Schedule to the said notification against Serial No. 2 the entry "Tezpur" in column (3) and the corresponding entry in column (4) shall be omitted.

[F. No. S-38018(7)/71-HI.]

का० आ० 1481.—यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि स्टेट इलैक्ट्रिक सप्लाई पावर पाउस, तेजपुर क्षेत्र में स्थिति था जो असम राज्य के दारंग जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी आबादी 500 से कम थी) था;

और, यत: उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2546 तारीख 1 अगस्त, 1962 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 7 च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते;

और, यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि असम राज्य के दारंग जिले में तेजपुर क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है;

अत:, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तंभ 3 में क्रम संख्या 2 के सामने "तेजपुर" प्रविष्टि और स्तंभ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जायेगी ।

[फा० सं० एस-38018(7)/7/-एचआई]

S.O. 1482.—Whereas the Central Government was satisfied that,

1. R. M. Shan Saw Mill,
2. Ashoka Saw Mill,
3. Bishwakarma Saw Mill;

were situated in Tezpur area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Darrang in the State of Assam.

And, whereas by virtue of their location in a sparse area, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1263, dated the 24th April, 1963.

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Texpur area in the district of Dargaga in the State of Assam has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification against Serial No. 4 the entry "Tezpur" in column 3 and the corresponding entries in column 4 shall be omitted.

[F. No. S-38018(7)/71-HI.]

का० आ० 1482.—यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि (1) आर० एम० शान सा मिल,

(2) अशोक सा मिल,

(3) बिशवाकर्मा सा मिल,

तेजपुर क्षेत्र में स्थित था जो असम राज्य के दारंग जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था;

और यत: उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ 1263, तारीख 24 अप्रैल, 1963 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नही हो जाते;

और यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि असम राज्य के दारंग जिले में तेजपुर क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है;

अत:, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तंभ 3 में क्रम संख्या 4 के सामने "तेजपुर" प्रविष्टि और स्तंभ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जायगी ।

[सं० फा० एल-38018(7)/71-एचआई]

S.O. 1483.—In exercise of the powers conferred by section 73 F of the Employees, State Insurance Act, 1948(34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2784 dated the 5th July, 1971 the Central Government having regard to the location of the factories specified in columns (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Punjab in which the provisions of the Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employers, special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial (1)	Name of District (2)	Name of Area (3)	Name of the Factory (4)
1	Bhatinda	Bhatinda	Messrs National Industries, Industrial Area.
2	Ferozepur	Ferozepur	Messrs Sarwa Singh Saw Mills, Ferozepur Cantonment.
3	Patiala	AmbeMegera Samana	Messrs Roshan Lal Ram Lal
4	Sangrur	Sunam	Iron and Steel Factory
5	Gurdaspur	Pathankot	Iron and Steel Factory, Messrs Janta Engineering Works. Messrs Meenakshi Industries. Messrs Indian Oil Corporation Limited.

[No. F. S-38018/14/71-HI]

का० आ० 1483.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2784 तारीख 5 जुलाई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो; एतद्द्वारा छूट देती है ।

अनुसूची

क्रम सं० (1)	जिले का नाम (2)	क्षेत्र का नाम (3)	कारखाने का नाम (4)
1.	भटिण्डा	भटिण्डा	मैसर्स नेशनल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल ऐरिया ।
2.	फिरोजपुर	फिरोजपुर	मैसर्स सरवन सिंह सा मिल्स, फिरोजपुर कैंट ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	पटियाला	अम्बे, मेगरा समाना	मैसर्स रोशनलाल राम लाल आयरन एण्ड स्टील फैक्टरी। आयरन एण्ड स्टील फैक्टरी, मैसर्स जनता—
4.	संगरूर	सुनाम	मैसर्स मीनाक्षी इण्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग वर्क्स ।
5.	गुरदासपुर	पठानकोट	मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ।

[संख्या फा० एम-38017/14/71-एल० आई०]

S.O. 1484—in exercise of the powers conferred by section 73 F of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment and No. S.O. 2768 dated the 5th July, 1971 the Central Government having regard to the location of the factories specified in column (4) of fe Schedule hereto annexed in areas specified in column(3) of the said Schedule in the State of Himachal Pradesh in which the provision of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employers, special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Adt in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District.	Name of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bilaspur	Bilaspur	Messrs/Himachal Government Rosin and Turpentine Factory.
2	Kangra	Ghati	Messrs Down Streeam Batching Plant.
3	Mandi	Harabagh	Messrs Field Repair Shop.
		Pandoh	Messrs Electrical Repair and Auto Battery Shop.

[No. S. 38017/14/71-HI]

का० आ० 1484.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2768, तारीख 5 जुलाई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्तअनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिससे उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बिलासपुर	बिलासपुर	मैसर्स हिमाचल सरकार रेसिन एण्ड टरपेन्टाइन फैक्टरी
2	कांगड़ा	धाटी	मैसर्स डाउन स्ट्रीम बैचिंग प्लाट
3	मंडी	हराबाग	मैसर्स फील्ड रिपेयर शाप,
		पंडोह	मैसर्स इलैक्ट्रिकल रिपेयर एण्ड मोटो बेटरी शाप

[सं० फा० एस-380 17/14/71-एच० आई०]

S.O. 1485.—Whereas the Central Government was satisfied that

(1) Kundla Division Motor Transport Co-operative Society Ltd.
(2) Kundla Taluka Kharid Vechan Sangh Ltd.

were situated in Savarkundla area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Bhavnagar in the State of Gujarat;

And, whereas by virtue of their location in a sparse area, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2849 dated the 30th September, 1963;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Savarkundla area in the district of Bhavnagar in the State of Gujarat has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification namely:—

In the Schedule to the said notification, against Serial No. 5, the entry "Savarkundla" in column 3 and the corresponding entries in column 4 shall be omitted.

[No. F.S-38018(7)/71-III.]

का० आ० 1485.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि (1) कुंडला डिविजन मोटर ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव सोसाइटी लि०, (2) कुंडला तालुक खरीद बेचान सघ लि०, सावरकुंडला क्षेत्र में स्थित था जो गुजरात राज्य के भावनगर जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा आबादी 500 से कम थी) था ;

और यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2849, तारीख 30 सितम्बर, 1963 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि गुजरात राज्य के भावनगर जिले में सावर कुंडला क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तंभ 3 में क्रम सं० 5 के सामने "सावर कुंडला" प्रविष्टि और स्तंभ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी।

[सं० एस-380/8(4)/71-एच आई]

S.O. 1486.—Whereas the Central Government was satisfied that Messrs Ashok Stone Processing Company was situated in Bardoli area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Surat in the State of Gujarat;

And, whereas by virtue of its location in a sparse area the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employers' special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1814, dated the 17th May, 1968;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Bardoli area in the district of Surat in the State of Gujarat has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification, against Serial No. 11, the entry "Bardoli" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted.

[No. F. S-38018(4)/71-H1/Part I.]

का० आ० 1486.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि मैसर्स अशोक स्टोन प्रोसैसिंग कम्पनी, बरदोली क्षेत्र में स्थित था जो गुजरात राज्य के सूरत जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था ;

और, यतः उसकी बिखरी हुए आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1814, तारीख 17 मई, 1968 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदान के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और, यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि गुजरात राज्य के सूरत जिले में बरदोली क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तंभ 3 में क्रम संख्या 11 के सामने "बरदोली," प्रविष्टि और स्तंभ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी।

[सं० फा० एस० 380/8(4)/71-एचआई]

S.O. 1487.—Whereas the Central Government was satisfied that Messrs Bhagubhai V. Intwala was situated in Bardoli area which was a sparse area (that is an area where insurable population was less than 500) in the district of Surat in the State of Gujarat;

And, whereas by virtue of its location in a sparse area the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employers' special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2849, dated the 30th September, 1963;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Bardoli area in the district of Surat in the State of Gujarat has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification, against Serial No. 14, the entry "Bardoli" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted.

[No. F. S-38018(4)/71-H1(Part I).]

का० आ० 1487.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि मैसर्स भागूभाई बी० इंतवला, बरदोली क्षेत्र में स्थित था जो गुजरात राज्य के सूरत जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था ;

और, यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2349, तारीख 30 सितम्बर, 1963 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और, यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि गुजरात राज्य के सूरत जिले में बरदौली क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तम्भ 3 में क्रम संख्या 14 के सामने 'बरदोली' प्रविष्टि और स्तंभ 4 में का तत्स्थानी प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी।

[सं० फा० एस० 380/8(4)/71-एच. आई.]

S.O. 1488.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) No. S.O. 1840, dated the 19th April, 1971 the Central Government having regard to the location of the Hangar No. 6, Jubu Airport, Maintenance Section of the Department of Aviation, Bombay in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 30th January, 1972 upto and inclusive of the 29th January, 1973.

[No. F. 601/81/70-HI.]

का०आ० 1488.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० 1840 तारीख 19 अप्रैल, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार हेंगर सं० 6, जुहू एयरपोर्ट, मेंटिनेन्स सेक्शन, विमानन विभाग, बम्बई की ऐसा क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 30 जनवरी, 1972 से 29 जनवरी, 1972 तक जिस में वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 60/8/70-एच.आई]

S.O. 1489.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees, State Insurance Act, 1948 (34 of 1948, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S. O. 3913, dated the 18th September, 1971 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of West Bengal in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of empolyers, special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, which ever is earlier.

SCHEDULE

S. No.	Name of District.	Name of the area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Birbhum . . .	Pancharhat	Messrs. Mayurakhi Cotton Mills Limited.
2.	Burdwan . . .	Kalna(Shalipur)	(i) Messrs. Samudregarh Powerloom Society Limited. (ii) Messrs. Bhowmick Textile Mills.
		Ondal . . .	Messrs. Engineer Enterprises.
3	Darjeeling . .	Darjeeling(proper)	Messrs. L.H. Dupuis (Automobile Engineers).
4.	Jalpaiguri . . .	Alipurduar Ektfasal	Messrs. United Engineering Works. (i) Messrs. Associated Engineering Company Limited. (ii) Messrs. Eastern Motors (Proivate) Limited.

(1)	(2)	(3)	(4)
			(iii) Messrs. Northern Flour Mills. (iv) Messrs. Siliguri Flour Mills (Private) Limited.
		Manabari . .	(i) Messrs. Oodlabari Engineering Works. (ii) Messrs. Mina Saw Mills.
		Nagrakata . .	Messrs. Premier Timber and Plywood Products.
		Siliguri . . .	Messrs. Mahananda Industries (Private) Limited.
5.	Midnapur . .	Kharagpur . .	Messrs. Sree Hanuman Steel Industries.
6.	Purulia	Jhalda	(i) Messrs Samar Singh Jayeswal (Private) Limited. (ii) Messrs Achhruram Kalkhof and Company Shellac (Private) Limited.
		Rangadih . .	(i) Messrs, Hiralal Lal Chand (ii) Messrs, Motilal Basak. (iii) Messrs, Mahabir Shellac Factory.

[No. F. S-38017(12)/71-HI]

का० आ० 1489.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3913 तारीख 18 सितम्बर, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट कारखानों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट पश्चिमी बंगाल राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की और अवधि के लिए या तब तक के लिए, जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बिर्भूम	पंचारइट	मैसर्स म्यूराक्षी काटन मिल्स लिमिटेड
2.	बरदवान	कलना (शालीपुर)	(i) मैसर्स समुद्रगढ़ पावरलूम सोसाइटी लिमिटेड (ii) मैसर्स मौलिक टैक्सटाइल मिल्स
3.	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग (खास)	मैसर्स एल० एच० दुपयस (आटोमोबाइल इंजिनीयर)
4.	जलपाईगुरी	अलीपुरद्वार	मैसर्स युनाइटेड इंजिनीयरिंग वर्क्स
		इकतियासल	(i) मैसर्स एसोशिएटिड इंजिनीयरिंग कम्पनी लिमिटेड (ii) मैसर्स ईस्टर्न मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (iii) मैसर्स नार्दर्न फ्लोर मिल्स (iv) मैसर्स सिलीगुरी फ्लोर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड
		मनबारी	(i) मैसर्स ओडलाबारी इंजिनीयरिंग वर्क्स (ii) मैसर्स मिना सा मिल्स
		नागराकाटा	मैसर्स प्रीमियर टिम्बर एंड प्लाईवुड प्रोडक्टस
		सिलीगुरी	मैसर्स महानंदा इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड
5.	मिदनापुर	खड़गपुर	मैसर्स श्री हनुमान स्टील इंडस्ट्रीज

(1)	(2)	(3)	(4)
6	पुरुलिया	झलदा	(i) मैसर्स सामर सिंह जायसवाल (प्राइवेट) लिमिटेड (ii) मैसर्स अछरूराम कालखोफ एण्ड कम्पनी शैलेक (प्राइवेट) लिमिटेड
		रानागादीह	(i) मैसर्स हीरालाल लाल चन्द (ii) मैसर्स मोतीलाल बासक (iii) मैसर्स महावीर शैलेक फैक्टरी

New Delhi, the 4th March 1972

S.O. 1490.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Goneshbari Tea Company (Private) Limited, 13/5, Block 'A', New Alipore, Calcutta-53, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1970.

[No. S.35018(59)/71-PF.II(i).]

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1972

का० आ० 1490.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोनेशबारी टी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 13/5, ब्लाक 'ए' न्यू अलीपुर, कलकत्ता—53 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018(59)/71-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1491.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st November, 1971, the establishment known as Messrs Kamala Silk Mills, Thakkar Bapanagar, Post Office Box No. 1129, Mulchandani Industrial Estate, Ahmedabad, for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019/115/71-PF.II(ii).]

[सं० फा० एस-3801/7(12)/71-एच० आई]

का० आ० 1491.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 नवम्बर, 1971 से मैसर्स कमला सिल्क मिल्स, ठक्कर बापानगर, पो० आ० बाक्स नं० 1129, मूलचन्दानी इंडस्ट्रियल इस्टेट, अहमदाबाद नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(115)/71 पी एफ-2 (ii)]

S.O. 1492.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Thakur Engineering Works, Gala No. 121, 3rd Floor, Municipal Industrial Estate, Bapti Road, Bombay-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund, Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1971.

[No. S.35019(143)/71-PF.II.]

का० आ० 1492.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ठाकुर इंजीयिरिंग वर्क्स, गाला सं० 121, 3-अर्ड फ्लोर, म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाप्ती रोड, मुम्बई-8, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(143)/71-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 6th March, 1972

S.O. 1493.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dynacast Industries, 159, C.S. Track Road, Amar Brass, Kalina Bombay-29 (AS) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1971.

[No. S.35017/49/71-PF.II(i).]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1972

का० आ० 1493.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डाइनाकास्ट इंडस्ट्रीज, 159 सी एस० ट्रैक रोड, अमर ब्रास, कालीना, मुम्बई–29 (ए एस) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के मार्च के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस–35017 (49)/71/पी एफ–2(1)]

S.O. 1494. In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government af making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st March, 1971, the establishment known as Messrs Dynacast Industries, 159, C.S. Track Road, Amar Brass, Kalina Bombay-29 (AS) for the purposes of the said proviso.

[No. S.35017/49/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1494.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग क ते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1971 से मैसर्स डाइनाकास्ट इंडस्ट्रीज 159, सी० एस० ट्रैक रोड, अमर ब्रास, कालीना मुम्बई (ए० एस०), नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस–35017 (49)/71–पी एफ–2 (ii)]

S.O. 1495.—Whereas, it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Voltamp Electricals Private Limited, 69, Prince Bakhtiar Shah Road, Tollygunj, Calcutta-33 including its Registered Office at P-15, New C.I.T., Road, Calcutta-12 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of December, 1970.

[No. S.35018(57)/71-PF.II(i).]

का० आ० 1495.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वाल्टेम्प इलैक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 69, प्रिन्स बख्तियारशाह रोड, टौलीगज, कलकत्ता–33 जिसमें इसका रजिस्टर्ड कार्यालय–पी 15, न्यू सी०टी०टी० रोड, कलकत्ता–12 भी शामिल है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के दिसम्बर के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस–35018 (57)/71–पी० एफ० 2(i)]

S.O. 1496.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Providents Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of November, 1971, the establishment known as Messrs Cochin Refineries Employees' Consumer Co-operative Society Ltd., No. E. 226 Ambala Mugal (via) Tripunithura, Ernakulam District for the purposes of the said proviso.

[No. S.35019(111)/71-PF.II(ii).]

का० आ० 1496.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् नवम्बर 1971 के प्रथम दिन से मैसर्स कोचीन रिफाईनरीस इम्पलाइज कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नं० ई० 226, अम्बाला मुगल वाया त्रिपुनीथुरा, अर्नाकुलम जिला नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस 35019(111)/71-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 1497.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jagan Nath and Company, Ram Nagar, Jullundur Cantonment have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund

Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notificaion shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1971.

[No. S.35019(134)/71-PF.II.]

का० आ० 1497.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जगन नाथ एण्ड कम्पनी, राम नगर, जालंधर कंटोनमैंट नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-350/19(134)/71-पी०एफ० 2]

S.O. 1498.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Kerala Timbers and Bandsaw Mills, Pudukad, Trichur District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the thirty first day of December, 1971.

[No. S.35019(126)/71-PF.II.]

का० आ० 1498.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केरल टिम्बर्स एण्ड बैंडसा मिल्स, पुडुकड त्रिचूर जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजकों और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के दिसम्बर के इकतीसव दिन को प्रवृत्त होगी।

[सं० एस-35019(126)/71-पी०एफ०2]

New Delhi, the 16th March 1972

S.O. 1499.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharat Chemical Agency, Asian Building, 2nd Floor, Nichol Road, Ballard Estate, Bombay-1 have agreed that the provisions' of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1970.

[No. S.35017/42/71-PF.II.]

नई दिल्ली, 16 मार्च 1972

का० आ० 1499.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारत केमिकल एजेन्सी, एशियन बिल्डिंग सकंड फ्लोर निकल रोड बैलर्ड एस्टेट बम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952(1952 का 19)के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन तक एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के अक्टूबर के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017 (42)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1500.—Whereas it appears to the Central Government that the employer, and the majority of the employees in relation to the establishment known as as Messrs Sushma Fabrics Private Limited, A-24-25 Road No. 9-Wagle Industrial Estate, District Thana including its office at Sethna Building, 216-Princess Street, Bombay-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1970.

[No. S.35017(56)/71-PF.II.]

का० आ० 1500.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुषमा फेब्रिक्स प्राइवेट लि० ए-24-25 रोड नं० 9 वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट जिला थाना तथा इसका कार्यालय सेतना बिल्डिंग 216-प्रिंसिस स्ट्रीट बम्बई-2 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017 (56)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1501.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Wheel Magnets, Menezes Branganza Road, Panjim, Goa, including its branch Near Railway Crossing, Mathans Mansion Margaon, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1971.

[No. 35017/58/71-PF.II.]

का० आ 1501.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वील मैगनेट्स मैंजीस ब्रानगांजा रोड पंजिम तथा इसकी शाखा नजदीक रेलवे क्रासिंग मैथन मेन्सन, मरगांव नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के मार्च के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017 (58)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1502.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shavo Norgren (India) Private Limited, Kalwa Industrial Area Thana Belapur Road, District Thana (Mharashtra) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the 30th day of June, 1971.

[No. S.35017/76/71-PF.II.]

का० आ० 1502 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शेवो नौरगेन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटड कालवा इंडस्ट्रियल एरिया, थाना बेलापुर रोड, जिला थाना, (महाराष्ट्र) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के जून के 30 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017 (76)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1503.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and he majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Eugene and Company, 127/1, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Calcutta-14 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1971.

[No. S.35018/61/71-PF.II.]

का० आ० 1503.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूजिन एण्ड कं०, 127/1, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-14 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018 (61)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1504.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vijya Bhumi, Kulasekharam Post, Kanya Kumari District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1971.

[No. S.35019/128/71-PF.II.]

का० आ० 1504.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजया भूमि, कुलासेखरम, पोस्ट, कन्या कुमारी जिला नामक स्थापन सेसंम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस–35019(128)/71–पी०एफ०–2]

S.O. 1505.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employmees in relation to the establishment known as Messrs Amritsar Primary Cooperative Land Mortgage Bank Limited, Amritsar have agreed that the Provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1971.

[No. S.35019/148/71-PF.II.]

का० आ० 1505.— यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अमृतसर प्राइमरी को-आपरेटिव लैंड मोर्टगेज बैंक लि०, अमृतसर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०–35019(148)/71–पी०एफ० 2]

S.O. 1506.—Whereas it appears to the Central Government that the employee and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Anand Prakash, Ravinder Kumar, 824 Nai Sarak, Delhi have agreed that the provisions of Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment,

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1969.

[No. S.35019/153/71-PF.II.]

का० आ० 1506.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आनन्द प्रकाश, रविन्द्र कुमार, 824-नई सड़क, दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०–35019(153)/71–पी०एफ 2]

S.O. 1507.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ravinder Textile Traders, 736-Katra Bhangi, Chandni Chowk, Delhi-6, including its Branch office at 10-Municipal Market, Kamla Nagar, Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the 15th day of April, 1970.

[No. S 35019(154)/71-PF.II.]

का० आ० 1507.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रविन्द्र टैक्सटाइल ट्रेडर्स, 736–कटरा भंगी, चान्दनी चौक, दिल्ली–6 तथा इसका शाखा कार्यालय–10, म्युनिसिपल मार्केट, कमला नगर, दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीयसरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के अप्रैल के 15वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 35019(154)/71–पी०एफ० 2]

S.O. 1508.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kurian Abraham Rubber Factory, have Pulliyor Kurichy, Thucklay Post, Kanya Kumari District,

have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1971.

[No. S.35019(156)/71-PF.II.]

का० आ० 1508.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुरियां अलाहम रबर फैक्टरी, पुलियोर कुरीची, ठुकाचे पोस्ट, कन्याकुमारी जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोक्ता और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(156)/71-पी०एफ० 2]

S.O. 1509.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Narayan Radio Stores, Eluru Road, Vijiawada-2, Krishna District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1971.

[No. S.35019/162/71-PF.II.]

का० आ० 1509.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नारायण रेडियो स्टोर्स, इलूर रोड, विजयवाडा-2, जिला कृष्णा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं०एस-35019(162)/71-पी०एफ० 2]

S.O. 1510.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pushraj Bijay Kumar, Malgodown, Cuttack-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1970.

[No. S.35019(168)71-PF.II.]

का० आ० 1510 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पुशराज बिजयकुमार, मालगोदाम, कटक-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 की मई को प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस-35019(168)/71-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 17th March 1972

S.O. 1511.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rotary Club of Bombay C/O star Trading Corporation Dhanaraj Mahal, 2nd Floor, Appollo Bundar Road, Bombay-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the Thirty first day of March, 1971.

[No. S.35017/63/71-PF.II.]

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1972

का० आ० 1511.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोटरी क्लब आफ बम्बई मार्फत स्टार ट्रेडिंग कारपोरेशन, धनराज महल, दूसरी मंजिल, एपोलो बन्दर रोड बम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त

अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के मार्च के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस-35017(63)/71-पी० एफ० 2]

S.O. 1512.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Savalle Chemi Pvt. Ltd., Corinthian B-5, 17, Arthur Bunder Road Colaba, Bombay-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of January, 1971.

[No. S. 35017(64)/71-PF.II.]

का० आ० 1512.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सावले कैमी प्राइवेट लिमिटेड, कोरिंथियान बी 5, 17, आर्थर बन्दर रोड, कोलाबा, बम्बई-5 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारीवर्ग की बहुसंख्या इस बात से सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 की जनवरी के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस-35017(64)/72-पी० एफ० 2]

S.O. 1513.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Westerwork Industries, B-8, Commerce Centre, Tardeo Road, Bombay. 34, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1970.

[No. S-35017(70)/71-PF.II(i).]

का० आ० 1513.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेस्टर वर्क इंडस्ट्रीज, बी-8, कामर्स सेंटर, तारदेव रोड, बम्बई-34 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के मार्च, के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35017(70)/71-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 1514.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry in the matter, hereby specifies, with effect from the thirty first day of March, 1970, the establishment known as Messrs Westerwork Industries, B-8, Commerce Centre, Tardeo Road, Bombay, 34, for the purposes of the said proviso.

[No S 35017(70)/71-PF.II(i).]

का० आ० 1514.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1970 से मैसर्स वैस्टर वर्क इंडस्ट्रीज, बी-8 कामर्स सेंटर, तारदेव रोड, बम्बई-34 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस-35017(70)/71-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 1515.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mercantile Materials Private Limited, Sneha Sadan, 2nd Floor, 114-C, Churchgate Reclamation, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1970.

[No. S.35/17(72)/71-PF.II(i).]

का०आ० 1515.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मर्केन्टाइल मैटीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, स्नेह सदन, द्वितीय फ्लोर 114-सी, चर्चगेट रिक्लमेशन, बम्बई-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1922 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के दिसम्बर, के 31 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35017(72)/71-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1516.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies, with effect from the thirty first December, 1970, the establishment known as Messrs Mercantile Materials Private Limited, Sneha Sadan, 2nd Floor, 114-C, Churchgate Reclamation Bombay-20, for the purposes of the said proviso.

[No. S.35017(72)71-PF.II(ii).]

का०आ० 1516.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1970 से मैसर्स मर्केन्टाइल मैटीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, स्नेह सदन, द्वितीय फ्लोर 114-सी चर्चगेट रिक्लेमेशन, बम्बई-20 नामक स्थापन को एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35017(72)/71-पी०एफ० II(ii)]

S.O. 1517.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Delite Distrbutors "Delstar" 1st Floor, 9-9 A, Hughes Road, Bombay-26, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notificaton shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1970.

[No. S. 35017(71)/71-P.F.II(i).]

का०आ० 1517.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डिलाइट डिस्ट्रीब्यूटर्स "दलस्तार" फर्स्ट फ्लोर, 9-9-ए, ह्युगलीस रोड, बम्बई-26 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है;

यह अधिसूचना 1970 के दिसम्बर, के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी;

[सं० एस-35017(71)/71-पी०एफ० 2(i)]

S.O. 1518.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment know as Messrs Patravali and Bhagwati, Fairy Manar, 5th A Floor 13., Gunbow Street, Bombay-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1971.

[No. S-35017/75/71-PF.II.]

का०आ० 1518.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पात्रावेली एण्ड भागवंती, फैरी मैनर, 5वां-ए, फ्लोर, 13, गुनबो स्ट्रीट, बम्बई-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन नधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है;

यह अधिसूचना 1971 की जुलाई के 31वें दिन की प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017(75)/71-पी०एफ० 2]

SO. 1519.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vijay Sanitary Stores, 3684-Chowri Bazar, Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1970.

[No. S-35019/93/71 PF.II.]

का०आ० 1519.—यतः, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विजय सेनिटरी स्टोर्स, 3684, चावड़ी बाजार, दिल्ली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना, 1970 के नवम्बर, प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी;

[सं० एस-35019(93)/71-पी०एफ० 2]

S.O. 1520.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Palamcottah Co-operative House Construction

Society Limited, O-1167 Perumalpuram, Tirunelveli-7 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1970.

[No. 8/193/70-PF.II.]

का०आ० 1520.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पालम कोटा कोआपरेटिव हाउस कन्स्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड, ओ–1167, पेरूमलपुरम, तिरुनेलवेली–7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1962 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है;

यह अधिसूचना 1970 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[संख्या 8/193/70-पी०एफ०–2]

New Delhi, the 20th March 1972

S.O.1521.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2777, dated the 5th July 1971 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Haryana in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District	Name of Areas	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ambala	Abdullapur	Messrs. India Auto Sales Private Limited, Pinjore Village.
2.	Rohtak	Kundli	Messrs. Essex Farms, 17th Mile Stone Village Kundli.

[F. No. S-38017/14/71-HI]

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1972

का० आ० 1521.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2777, तारीख 5 जुलाई, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची में के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3) में विनिर्दिष्ट हरियाणा राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुये उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5–क के अधीन उद्ग्रहण्य नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये या तब तक के लिये जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अम्बाला	अबदुल्लापुर	मैसर्स इंडिया आटो सेल्स प्रइवेट लिमिटेड, पिंजोर विलेज।
2.	रोहतक	कुंडली	मेसर्स इसैक्स फार्मस 17वें मील का पत्थर गांव कुंडली।

[सं० फा० एस–38017/14/71–एच आई]

SO. 1522.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1540 dated the 27th March, 1971 the Central Government having regard to the location of the factory, namely Depot at Tondiarpet, Adyar, Ayanavaram, Tiruchirapalli and Coimbatore belonging to the Tamil Nadu State Transport Department in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 24th March, 1972 upto and inclusive of the 23rd March, 1973.

[No. F. 601(4)/70-HI.]

का० आ० 1522.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और

पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1540 तारीख 27 मार्च, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार डिपो टांडियरपेट, अडयार, आयनावरम, तिरुचिरापल्ली तथा कोयबातूर जो तमिलनाडु राज्य परिवहन विभाग से सम्बद्ध हैं की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुये उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 24 मार्च, 1972 से 23 मार्च, 1973 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिये एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० फा० 601(4)/70-एच० आई०]

S.O. 1523.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1893 dated the 26th April, 1971 the Central Government having regard to the location of the Government Automobile Workshops at Madurai and Salem belonging to Tamil Nadu State Transport Department in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said Workshops from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 5th January, 1973.

[File No. 601(75)/70-HI.]

का० आ० 1523 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1893, तारीख 26 अप्रैल, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार गवर्नमेंट आटोमोबाइल वर्कशाप, मदुराई तथा सालेम, जो तमिलनाडु राज्य परिवहन विभाग से सम्बद्ध हैं, की ऐसी क्षेत्र में जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुये उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख 5 जनवरी, 1973 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिये एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० फा० 601(75)/70-एच० आई०]

S.O. 1524.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and employment). No. S.O. 1935 dated the 26th April, 1971 the Central Government having regard to the location of the Central Workshop, Rajasthan Ground Water Board, Industrial Estate, Jodhpur in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said Workshop from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 30th January, 1972 upto and inclusive of the 29th January, 1973.

[F. No. 601/78/70-HI.]

का० आ० 1524—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग), की अधिसूचना सं० का० आ० 1935, की तारीख 26 अप्रैल, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार सेंट्रल वर्कशाप, राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड, इण्डिस्ट्रियल एस्टेट, जोधपुर का ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुये उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक को विशेष अभिदाय के संदाय से 30 जनवरी 1972 से 29 जनवरी, 1973 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है एक और वर्ष की कालावधि के लिये एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० फा० 601(78)/70-एच० आई०]

S.O. 1525.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour, & Employment) No. S.O. 1894, dated the 26th April, 1971 the Central Government having regard to the location of the Public Works Department Workshop, Bhopal in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said workshop from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 9th January, 1973.

[No. F. 601(79)/70-HI.]

का० आ० 1525.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 74च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1894, तारीख 26 अप्रैल, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार पब्लिक वर्क्स विभाग वर्कशाप, भोपाल की ऐसी क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुये उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की तारीख की समाप्ति से 9 जनवरी, 1973 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित हैं, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० फा० 601(79)/70-एच० आई०]

S.O. 1526.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Electrical and Mechanical Workshop Madras Airport, Madras under the control of the Ministry of Tourism and Civil Aviation, Government of India are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefit provided under the Employees' State Insurance Act, 1948, (34 of 1948).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation

of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1841 dated the 19th April, 1971 the Central Government after consultation with the employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from all the provisions of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st February, 1972 upto and inclusive of the 31st January, 1973.

[No. F. 601/83/70-HI.]

का० आ० 1526.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि भारत सरकार के पर्यटन और विमानन मंत्रालय के प्रबन्ध में इलैक्ट्रिकल एण्ड मकेनिकल वर्कशाप, मद्रास एयरपोर्ट मद्रास के कर्मकारो को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम; 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाएं जैसी सारतः प्रसुविधाएं प्राप्त हैं।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० 1841 तारीख 19 अप्रैल, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा उक्त कर्मशाला को उक्त अधिनियम के प्रवर्तणन से 1 फरवरी, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

[सं० फा० सं० 601(83)/70-एच०आई०]

New Delhi, the 28th March 1972

S.O. 1527.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 785 dated the 23rd February, 1968, the Central Government hereby appoints Shri J. M. Pandya as Regional Provident Fund Commissioner for the whole of the State of Rajasthan to assist the Central Provident Fund Commisioner in the discharge of his duties, *vice* Shri U. M. Patni.

[No. 17(63)/64-PF.I(i).]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1972

का० आ० 1527.—कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 785 तारीख 23 फरवरी, 1968 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री यू० एम० पटनी के स्थान पर श्री जे० एम० पांडया को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता देने के लिए, समस्त राजस्थान राज्य के लिए एतद्द्वारा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त करती है।

[सं० 17(63)/64-पी० एफ० I(i)]

S.O. 1528.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 786 dated 23rd February, 1968, the Central Government hereby appoints Shri J. M. Pandya to be an Inspector for the whole of the State of Rajasthan for the purposes of the said Act and of any Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government, or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry.

[No. 17/63/64-PF.I(ii).]

DALJIT SINGH, Under Secy.

का० आ० 1528.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 786 तारीख 23 फरवरी, 1968 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जे० एम० पांडया को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के क्षेत्रों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० 17(63)/64-पी० एफ० I (ii)]

दलजीत सिंह, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 6th March, 1972

S.O. 1529.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution the President hereby entrusts with the consent of the Government of Jammu and Kashmir, the function of Central Government under The Trade Unions Act, 1926 (16 of 1928), in relation to trade unions whose objects are not confined to, and whose head office is situated in that State to that State Government.

[No. S.13013/1/71-LR.I.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1972

का० आ० 1529.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जम्मू व कश्मीर की सहमति से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उन व्यवसाय संघों के सम्बन्ध में जिनके मुख्य कार्यालय उस राज्य में स्थित हैं और जिनके उद्देश्य उस तक सीमित नहीं हैं, उस राज्य सरकार को सौंपते हैं।

[स० एस-13013/1/71-एल० आर० आई०]

New Delhi, the 25th March 1972

S.O. 1530.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 83 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby exempts

for a period of five months or till the cessation of the operation of the Proclamation of Emergency issued by the President under Clause (I) of article 352 of the Constitution on the 3rd day of December, 1971, whichever is earlier, all the mines from the following provisions of the said Act, namely:—

(i) Section 28,

(ii) Section 29,

(iii) Sub-section (1) of section 30 and sub-section (1) of section 31 in so far as the said sub-sections restrict the number of weekly hours to fortyeight, and

(iv) Section 33,

Subject to the condition that:—

(a) no person shall be employed on more than one weekly day of rest out of every four weekly days of rest, and

(b) the exemption made by this notification shall apply only to the employment of persons on one weekly day of rest out of every four weekly days of rest.

[No. S. 29014/14/71-MI.]

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1972

का० आ० 1530.—खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) की धारा 83 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सभी खानों को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबन्धों से पांच मास की अवधि या आपात स्थिति की उद्घोषणा, जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन 1971 के दिसम्बर के तीसरे दिन जारी की गई थी, के प्रवर्तन की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्द्वारा छूट देती है, अर्थात् :—

(1) धारा 28,

(2) धारा 29,

(3) धारा 30 की उपधारा (1) तथा धारा 31 की उपधारा (1), जहां तक उक्त उपधाराएं साप्ताहिक घण्टों की संख्या अड़तालीस (घंटे) तक निर्बन्धित करती है, और

(4) धारा 33,

इस शर्त के अध्यधीन कि —

(क) कोई भी व्यक्ति, साप्ताहिक आरम्भ के प्रत्येक चार दिनों में से किसी एक आराम के साप्ताहिक-दिन से अधिक नियोजित नहीं किया जाएगा, तथा

(ख) इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट, साप्ताहिक आराम के प्रत्येक चार दिनों में से एक आराम के साप्ताहिक दिन के लिए व्यक्तियों के नियोजन पर ही लागू होगी।

[सं० एस० 290/4/(14)/71-एम आई]

ORDER

New Delhi, the 6th March 1972

1531.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messers Dehri Rohtas Light Railway Company Limited, Dalmianagar and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal. (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Messers Dehri Rohtas Light Railway Company Limited, Dalmianagar is justified in denying the benefit of the scale of pay of mason and blacksmith to Sarvashri Ram Briksha, basic tradesman mason and Ram Raj, basic tradesman blacksmith, who are performing the duties of mason and blacksmith from 1st June, 1965 and 20th June, 1970 respectively? If not, to what relief are they entitled?"

[No. L-41012/4/72-LR.III.]

B. K. SAKSENA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1972

का०आ० 1531.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स देहरी रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, डालमियानगर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 1), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स देहरी रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, डालमियानगर की सर्वश्री रामवृक्ष, बेसिक ट्रेड्समैन राज और रामराज बेसिक ट्रेड्समैन लोहार, जो क्रमशः राज और लोहार का पहली जून, 1965 और 20 जून, 1970 से काम कर रहे थे, को राज और लोहार के वेतनमान की प्रसुविधाएं देने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-41012/4/72-एल०आर०-III]

बी० के० सक्सेना, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 18th March, 1972.

S.O. 1532.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961) read with rule 31 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, the Central Government hereby specifies the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Hyderabad, to be the Iron Ore Mines Cess Commissioner who shall be responsible tor the assessment and collection of the Cess levied under the said Act in the State of Andhra Pradesh with effect from the afternoon of 2nd August, 1971 and make the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2790 dated the 19th September, 1965, namely:—

In the Schedule to the said notification against serial number 1, in column (1) for the entry Deputy Commissioner of Labour, Hyderabad," the following entry shall be substituted, namely:—

"Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Hyderabad."

[No. U/19012/8/71-M.III.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972

का० आ० 1532.—लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1963 के नियम 31 के साथ पठित लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद के श्रम आयुक्त को लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त विनिर्दिष्ट करती है जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत उपकर के निर्धारण और उसे इकट्ठा करने का 2 अगस्त, 1971 के पूर्वाह्न से उत्तरदायी होगा, और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2790, तारीख 19 सितम्बर, 1963, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

"उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 1 के सामने स्तम्भ (1) में "उपायुक्त, श्रम, हैदराबाद" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"श्रम आयुक्त,
आन्ध्र प्रदेश,
हैदराबाद।"

[सं० यू/19012/8/71-एम III]

S.O. 1533.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961), read with clause (ii) of rule 3 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Rules, 1963, the Central Government hereby appoints with effect from the afternoon of the 2nd August, 1971, the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Hyderabad to be the Vice-Chairman of the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee for Andhra Pradesh, Hyderabad, constituted by the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4260 dated the 18th November, 1968, and makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the said notification, against serial number 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Hyderabad.
Vice-Chairman".

[No. U/19012/8/71-M.III.]

C. R. NAIR, Under Secy.

का० आ० 1533.—लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर नियम 1963 के नियम 3 के खण्ड (ii) के साथ पठित लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1961 (1961 का 58) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्रम आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद को 2 अगस्त 1971 के अपराह्न से आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि सलाहकार समिति का, जो भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 4260, तारीख 18 नवम्बर, 1968, द्वारा गठित की गई थी, उपाध्यक्ष नियुक्त करती है और उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

"उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 2 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"श्रम आयुक्त,
आन्ध्र प्रदेश,
हैदराबाद। उपाध्यक्ष।"

[सं० यू/19012/8/71-एम III]

सी० आर० नायर, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 22nd March, 1972

S.O. 1534.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour & Employment) No. S.O. 3832, dated the 17th September, 1971, the service in the uranium industry, to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months from the 20th October, 1971;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares the said industry ot be a public utility service for the purpose of the said Act for a further period of six months from the 20th April, 1972.

[No. F. S. 11025/10/72-LR.I]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1972

का०आ० 1534.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14)की धारा 2 के खंड (ढ़)के उपखण्ड (VI)के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3832, तारीख 17 सितम्बर, 1971 द्वारा यूरेनियम उद्योग में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अक्टूबर, 1971 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार को राय कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़)के उपखण्ड(VI)के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अप्रैल, 1972 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० फा० एस-11025/10/72-एल०आर० I]

New Delhi, the 30th May 1972

S.O. 1535.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th May, 1972.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Chairman, Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad.

INDUSTRIAL DISPUTE No. 6 OF 1970

BETWEEN

Workmen of Bank of Baroda, Hyderabad—*Petitioner.*

AND

The Management of Bank of Baroda, Hyderabad—*Respondent.*

APPEARANCES:

Sri P. Vivekananda Rao, General Secretary, Bank of Baroda Employees' Union, A.P., *for petitioner*

Sri K. Srinivasa Murthy, Hony. Secretary & Director of Federation of A.P. Chambers of Commerce & Industry, Hyderabad, *for respondent.*

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) by its Order No. 23/84/69/LR III dt. 15th January, 1970 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for adjudication by this Tribunal, namely:

"Having regard to the provisions contained in clause 14.3(c) of the Bipartite Settlement dated the 19th October, 1966 whether the demand of the Bank of Baroda Employees' Union (A.P.) Hyderabad, for payment of overtime allowance of Sh. Ch. Appalaswamy, Watchman *cum*-peon of the Vizagapatnam Branch of the Bank for the extra hours worked by him over and above the limits prescribed under clause 14.2(c) from 19th October, 1966 onwards is justified? If so, to what relief the workman is entitled?"

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 6 of 1970 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience the concerned workman is referred to as the petitioner and the Bank of Baroda is referred to as the respondent in the course of this award.

2. The petitioner is represented by the Bank of Baroda Employees' Union, Andhra Pradesh and the General Secretary of the Union filed the claim statement contending as follows: The petitioner Appalaswamy is a watchman-*cum*-peon at the Bank's Branch office at Visakhapatnam. The Bank was extracting 8 hours of work from the petitioner though under the Bipartite Settlement arrived at between the All India Banks Employees' Association and the Indian Banks Association on 19th October, 1966 as per clause 14.3(c) the petitioner has to put in work as laid down in clause 14.2 (c) of the said settlement. From clause 14.3(c) of the said settlement it is clear that the working hours of Watch and Ward staff members shall be 8 hours in a period of 24 hours except in the cases of watchman-*cum*-peon and peons working as watchman or armed guard. In the case of Watchman-*cum*-peon the working hours as laid down in clause 14.2(c) of the said settlement are applicable for the period during which he works as a peon and for the period during which he works as a watchman or armed guard and also of a peon who is required to work as watchman. This lays down the working hours of all the subordinate staff other than those of Watch and Ward Staff and Drivers. As such the watchman-*cum* peon is not excluded from the working hours applicable to the peons under clause 14.2(c) of the said settlement. So the watchman-*cum*-peon will be required to put in 7 hours of work on week days and 4½ hours on Saturdays as per clause 14.3(c) irrespective of the fact whether he works as a peon or as a watchman and or armed guard as laid down in clause 14.2(c). In Chapter XX of the said settlement, which deals with combine designations, part time employees, temporary employees etc., in para 20.1 clearly lays down that if an employee on a regular assignment performs certain duties which entitled him to special allowance the same will not be disturbed. So the logical conclusion could be drawn that in so far as double designatories are concerned the workmen are entitled for all benefits of a designation among the two designations. The peons in Banks do not work as watchman and watchmen as peons. It is only through this particular combined designation of watchman-*cum*-peon the Baks are given by the said settlement the benefit of getting from a watchman-*cum* peon the work of a peon and also of a watchman. But this does not in any way give the right to the Banks to exploit the employee to work for 8 hours simply because he would be discharging the duties of a peon and also a watchman whenever he is called upon. The respondent has been overlooking completely the provisions of clause 14.3(c) of the said settlement in respect of the petitioner and it has been extracting working hours relating to the watchman during the period when he worked as a peon and also as a watchman. To substantiate the claim of the petitioner as to the violation of the said settlement the petitioner submits that the respondent violated the provisions of clauses 14.6 and 14.7 of the said settlement and extracted overtime beyond the maximum stipulated at 175 hours

of overtime work in a year. The respondent had been making gross violation of clauses of the said settlement. The respondent has been denying the public holidays to the petitioner. The petitioner has to get overtime wages for the hours of work he was made to put in from 19th October, 1966 beyond the hours of work he has to put in as per clause 14.2(c) of the said settlement.

3. The respondent in its counter while extracting the relevant clauses of the said settlement contended as follows: This Tribunal has no jurisdiction to deal with this matter as the issue involved the correct interpretation of clauses 14.2(c) and 14.3(c) of the said settlement and the difficulty or doubt in regard to the interpretation of the said clauses should have been referred to such Labour Court/Tribunal or National Tribunal as it might have thought fit for the interpretation of clauses 14.2(c) and 14.3(c) of the said settlement under Section 36A of the said Act. This Tribunal has also no jurisdiction to try this case unlike the Labour Court exercising power under Section 33(C)(2) of the said Act. It is not an executing Court with powers to order execution of the provisions of the said settlement. The petitioner who is substantively a watchman must normally be treated as a member of the Watch and Ward Staff as controlled by clause 14.3(c) and entitled to lesser hours of work under clause 14.2(c) only when he works as a peon. In other words a watchman-*cum*-peon will be a member of the subordinate staff other than driver and watch and ward staff on the days on which he works as peon and watchman-*cum*-peon will be a member of the Watch and Ward Staff on the days on which he works as a watchman for the purpose of his respective hours of work. Since it could not have been the intention of the contracting parties to provide in the said settlement that the hours of work of a watchman-*cum*-peon, irrespective of the nature of duties he has to perform (whether of a peon or of a watchman), will be 7 hours per day on week days (excluding Saturdays) and 4½ hours per day on Saturdays. A special clause, namely, clause 14.3(c) has been envisaged in the settlement. It is amply clear from the fact that the specific provision in respect of the hours of work of the Watch & Ward Staff is made in clause 14.3(c) and it is provided therein that the hours of work of the Watch & Ward Staff shall be 8 hours in a period of 24 hours. It is, therefore, obvious that what is intended is that a Watchman-*cum*-peon when he works as a peon is a member of Subordinate Staff for the purpose of hours of work and he is a member of the Watch & Ward Staff when he works as a Watchman. So clauses 14.2(c) and 14.3(c) if read together mean that the hours of work of a watchman-*cum*-peon when he works as a watchman shall be 8 hours, that is, the hours of work of a member of the Watch and Ward Staff and 7 hours when he works as a Peon, that is, the hours of work of a member of the Subordinate Staff, that is substantively appointed as a peon. The petitioner was properly required to work for 8 hours when he was doing the duties of a watchman and for that purpose he has been considered the member of the Watch and Ward Staff. The interpretation given by the Union that the watchman-*cum*-peon is not excluded from the working hours applicable to the peons under clause 14.2(c) is not correct. Clause 14.12 referred to by the Union is not relevant in the present dispute. The Union have referred to Chapter XX of the said settlement merely to confuse the issue because clause 20.1 of the said settlement is irrelevant in the present dispute. Whenever the petitioner was required to work as a watchman he was treated as a member of the Watch and Ward Staff and was properly required to work for 8 hours and whenever he was required to work as a peon he was properly required to work for 7 hours on week days and 4½ hours on Saturdays. From the Annexure A enclosed to the counter showing the actual working hours of the petitioner from 9th October, 1966 to 20th February, 1969 it is clear that the petitioner was required to put in the hours of work applicable to the Watch and Ward Staff when he worked as a watchman and he was required to put in the hours of work pertaining to the peons whenever he was required to work as peon. On the occasions the petitioner had to work over and above the respective stipulated hours of work he was paid overtime accordingly. The Union has referred to clauses 14.6 and 14.7 merely to confuse the issue and this is not included in the terms of reference. There are no arrears of overtime wages to be paid to the petitioner. The allegation that the petitioner was not granted public holidays is outside the terms of reference and therefore not relevant. The allegation that the Bank has been denying public holidays to the petitioner is denied. Clauses 14.13(a), (b) and (c) deal with the weekly off and holidays for the Watch and Ward Staff. The wording of clause 14.13(c) is such that by necessary implication it may be said that a watchman-*cum*-peon for the period during which he works as a watchman would not be entitled to any intervening holiday observed by the Bank because during that period he would be considered to be a member of the Watch and Ward Staff. The watchman-*cum*-peon is paid in addition to the salary payable, which is the same as peon, special allowance of Rs. 7.00 per month, payable to watchman (being a member of the Watch and Ward staff) irrespective of the fact that at times watchman-cum-peon is required to work as peon and during that time his hours are as that of a peon. So the intention of the contracting parties was to treat watchman-*cum*-peon as dealt with Watch and Ward Staff under clause 14.3(c), especially a member of the Watch and Ward Staff giving the management their right to take the work of a peon from a Watchman-cum-peon as and when the Banks are required. The petitioner is being paid speial allowance of Rs. 7.00 per month throughout the month, although he is required to work as watchman on occasions as and when it is necessary. The Union cannot claim overtime allowance to the petitioner. The vague allegations made by the Union in respect of violations generally made by the Bank are untrue, baseless and irrelevant.

4. Now the dispute that is referred to for adjudication by this Tribunal is having regard to the provisions contained in clause 14.3(c) of the Bipartite Settlement dated the 19th October, 1966 whether the demand of the Bank of Baroda Employees Union (A.P.) Hyderabad, for payment of overtime allowance of Sh. Ch. Appalaswamy, watchman-*cum*-peon of the Visakhapatnam Branch of the Bank for the extra hours worked by him over and above the limits prescribed under clause 14.2(c) from 19th October, 1966 onwards is justified? If so, to what relief the workman is entitled?

5. In the counter one of the contentions urged is that this Tribunal has no jurisdiction to decide the present dispute. It is contended by the learned counsel for the respondent that it is only the 3rd schedule to the said Act which refers to the matters which are within the jurisdiction of this Tribunal, that the present kind of dispute is not referred to therein, that the present claim is virtually on the basis of settlement and that this matter comes under Secton 33(C) of the said Act which refers to recovery of money due from an employer and that it is only the labour Court which has jurisdiction and so this Tribunal has no jurisdiction to decide the present dispute the petitioner's representative on the other hand contended that there is no computation of money value and so Section 33(C) of the said Act does not come in that it is only the interpretation of the clauses that is involved in the present case and so this Tribunal has jurisdiction. As contended by the petitioner's representative it is only the interpretation of clauses 14.3(c) and 14.2(c) of the said Settlement that is involved in the present case and all that has to be seen is whether the petitioner should work for 8 hours if he works as watchmen and for 7 hours when he works as peon in view of his designation as watchman-*cum*-peon or whether he should work only for 7 hours whether he worked as watchman-or peon. So the question of recovery of any money due under any settlement that is contemplated does not arise in this case and so Section 33(6) of the said Act has nothing to do with the present dispute. Practically this dispute relates to the hours of work of the petitioner considering the nature of work done by the petitioner. I do

not find much force in the objection raised by the respondent that this Tribunal has no jurisdiction to decide the present dispute. So the objection raised by the respondent about jurisdiction of this Tribunal to decide the present dispute is overruled.

6. Coming to the merits of the case on the side of the petitioner W.Ws.1 to 3 were examined and Ex. W.1 was marked and on the side of the respondent M.W.1 was examined and Ex. M.1 was marked. The petitioner has been working as Watchman-*cum*-peon in the Visakhapatnam Branch of the respondent. The petitioner has been doing the duties of a peon or a watchman as the case may be as seen from the annexure Ex. M.1. Ex. W.1 is the letter of appointment given to the petitioner who has been examined as W.W.3. From Ex. M.1 and from the evidence of M.W.1 who was previously working as Agent of the respondent branch at Visakhapatnam it is seen that whenever the petitioner worked as a watchman he was asked to work for 8 hours and that whenever he worked as a peon he was asked to work for 7 hours and that whenever the petitioner worked for more than 8 hours as watchman and more than 7 hours as peon, he was being given overtime allowance. Now the contention of the petitioner is that even though he is working as watchman-*cum*-peon, he is not excluded from the wroking hours as applicable to the peons under clause 4.2(C) of the said settlement and so he has to put in only 7 hours of work on all the days except on Saturdays and 4½ hours of work on Saturdays, whereas the Bank had been extracting work for 8 hours a day whenever the petitioner worked as watchman and so the petitioner is entitled to the overtime allowance for the hours he worked over and above the 7 hours. The contention of the respondent is that whenever the petitioner was required to work as watchman he was treated as member of the Watch and Word Staff and so properly required to work for 8 hours and that whenever he was required to work as a peon he was required to work for 7 hours on week days and 4½ hours on Saturdays as applicable to a peon and so there is no question of paying any overtime allowance whenever he worked as a watchman for 8 hours.

7. W.W.1 (Sri V. Satyanarayana Murthy) is working as Shroff-*cum*-Godown Keeper in the respondent's branch at Hyderabad. He says that for a Godown Keeper 8 hours are the working hours, that the working hours of a shroff are 6½ hours with a rest of ½ hour that because he was designated as Shroff-*cum*-Godown Keeper he has to work for 6½ hours and that if he is asked to go to the godowns after 6½ hours of work, he will go but he will be entitled to overtime allowance. He himself says that there was no occasion for him to work in both departments for more than 6½ hours. His evidence is of not much use so far as the present dispute is concerned. W.W.2 (Sri Mohammed Yousufddin) is working as Watchman-*cum*-peon in Central Bank of India, Secunderabad Branch. He says that usually he works for 7 hours in all every day, that in this branch there is shift system, that he does the work of watchman-*cum*-peon simultaneously, that he would be rarely working as a watchman exclusively, that even on those days he worked for 7 hours per day, that whenever he works for more than 7 hours on any day he is paid overtime allowance and that even if he attends to the watchman's duties for more than 7 hours, he is paid overtime allowance. He says that shift is from 8-15 A.M. to 12-00 NOON in the morning and in the evening it is from 4-30 to 7-45 P.M every day except on Saturday when the Bank works from 8-15 A.M. to 12-45 P.M., that the watchman has no shift hours, that as a watchman he works during the above working hours and that in between the morning and evening sessions and in the night no watchman watches the premises as the Agent resides there. So his evidence is to the effect that even though he is a watchman-*cum*-peon he usually works only for 7 hours in all every day and that in his branch there is shift system. W.W.3 (Sri Ch. Appalaswamy) says that two peons one watchman and himself were appointed when the respondent's Branch was opened at Visakhapatnam, that he used to do the work for 8 hours without any interval or rest, that he is now doing peon's duty, that whenever a peon or a watchman applied for leave he would be asked to do their duties. He also says that he never used to be given lunch break properly and that he never used to be given holidays and that the respondent's Branch at Visakhapatnam has not been observing the maximum overtime hours and it is also suggested to M.W.1 that he has not been observing the rules about giving holidays etc., and from this it is contended by the petitioner's representative that the respondent's branch at Visakhapatnam had been committing irregularities but it in not necessary to consider the question whether the petitioner was not being given any holidays etc, because they are not relevant for the purpose of this case. Now the evidence of W.W.3 is to the effect that whenever the petitioner worked as watchman he was asked to work for 8 hours, M.W.1 says that when the petitioner was working as a peon he was required to work for 7 hours on week days and 4½ hours on Saturdays, that if he worked as peon beyond 7 hours he would be paid overtime wages, that as watchman he was required to work 8 hours per day and that if he worked as watachman beyond 8 hours he would be paid overtime.

8. Now the point that needs consideration is whether the petitioner though designated as watchman-*cum*-peon is entitled to work only for 7 hours whether he worked as watchman or peon as contended by the petitioner or whether the petitioner has to work for 8 hours whenever he is asked to work as peon and whether he has to work for 7 hours only whenever he works as peon as contended by the respondent. Now it is seen that a settlement was arrived at between the Bank Management and their workmen on 19th October, 1966. So far as hours of work and overtime are concerned they are referred to in Chapter XIV of the settlement and the relevant clauses for the purpose of the present dispute are clauses 14.2(c) and 14.3(c) and it would be useful to extract these clauses for the purpose of seeing whether the contention of the petitioner is correct or whether the contention of the respondent is correct.

"Clause 14.2

	Weeks days (excluding Saturdays)	Saturdays.
	(hours per day)	
(a)		
(b)		
(c) Members of the subordinate staff other than Drivers and Watch & Ward Staff.	7	4½
(d)		

Clause 14.3

(a)

(b)

(c) The hours of work of a member of the Watch Ward Staff shall be 8 hours in a period of hours PROVIDED that the hours of work of a "Watchman-*cum*-Peon" for the period during which he works as a peon, as also of a peon, for the period during which he is required to work as a watchman' or 'Armed Guard' shall be the same as those laid down in clause 14.2(c) above."

9. As per clause 4.2(c) the members of the Subordinate Staff other than drivers and Watch and Ward Staff have to work for 7 hours per day excluding Saturdays and 4½ hours on Saturdays. So this clause shows that these working hours do not relate to the Watch and Ward Staff. Clause 14.3(c) shows that the members of the Watch and Ward Staff should work for 8 hours in a period of 24 hours and the proviso to Clause 14.3(c)

makes it clear that so far as the watchman-*cum*-peon is concerned for the period during which he works as a peon, as also of a peon, for the period during which he is required to work as a watchman or Armed Guard the working hours shall be the same as those laid down in Clause 14.2(c). A combined reading of clause 14.2(c) and 14.3(c) shows that the members of the subordinate staff other than watch and ward staff should work for 7 hours in a week excluding Saturday and 4½ hours on Saturdays and that so far as the Watch and Ward Staff is concerned they have to work for 8 hours and that so far as watchman-*cum*-peon is concerned if he works as peon his working hours will be 7 hours excluding Saturdays and 4½ hours on Saturdays as per clause 14.2(c).

10. Now it has to be seen whether if a watchman-*cum*-peon works as a watchman he should work only for 7 hours as contended by the petitioner or for 8 hours as contended by the respondent. If it was the intention of the parties that whenever a person is designated as a *watchman-cum-peon he should work only for 7 hours* whether he works as a peon or as a watchman then in clause 14.2 (c) itself it would have been made clear by stating that members of the subordinate staff "including watchman-*cum* peon." But the very fact that the watchman-*cum*-peon is not specifically mentioned in Section 14.2(c) and in view of the fact that the reference is made to the working hours of the watchman-*cum-peon under the proviso to Clause 14.3(c) it is clear* that the intention of the parties was that whenever the watchman-*cum*-peon worked as a peon his working hours should be as per clause 14.2(c) and so the proviso to clause 14.3(c) has been added. Clause 14.3(c) also shows that the watchman had been included under the watch and ward staff and that is the reason why so far as the person who works as watchman-*cum*-peon is concerned, in order to make it clear that when such a person works as a peon his working hours would be only as per clause 14.2(c) the proviso to clause 14.3(c) has been added. It is also now seen that for the purpose of extracting the work of a peon or a watchman from a person during the absence of a peon or watchman some persons have been designated as watchman-*cum*-peons so that their services may be requisitioned and posted as watchmen or as peons as the case may be. So whenever such a person works as a peon he has necessarily to work for 7 hours only on a week days excluding Saturdays and for 4½ hours on Saturdays as provided under clause 14.2(c) and that whenever he works as a watchman he should work for 8 hours as provided in clause 14.3(c) for a member of watch and ward staff. So the proviso to clause 14.3(c) makes it clear that a watchman-*cum*-peon can be asked to work for 7 hours only if he works as a peon but not otherwise. So I agree with the contensions of the respondent that so far as the petitioner is concerned he has to work for 8 hours whenever he is posted as a watchman and that he has to wark for 7 hours only when he is posted as a peon. The contention of the petitioner that he has to work only for 7 hours whether he is posted as a peon or watchman and that he is entitled to overtime over and above the 7 hours is not correct.

11. For all the aforesaid reasons on the dispute referred to for adjudication, I hold that having regard to the provisions contained in clause 14.3(c) of the Bipartite Settlement dated 19th October, 1966, the demand of the Bank of Baroda Employees Union, Andhra Pradesh, Hyderbad for payment of overtime allowance to Ch. Appalaswamy, Watchman-*cum*-peon of the Visakhapatnam Branch of the Bank for the extra hours worked by him over and above the limits prescribed under clause 14.2(c) from 19th October, 1966 onward, is not justified and that in as much as overtime allowance had been paid to the petitioner whenever he worked for more than 8 hours as a watchman and whenever he worked for more than 7 hours as a peon, the petitioner is not entitled to any further relief.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 9th day of May, 1972.

(Sd.) P. S. ANANTH,
Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses examined for petitioner :	*Witnesses examined for Respondent :*
W.W. 1. V. Satyanarayana Murthy.	M.W. 1. D. Krishna Rao.
W.W. 2. Mohd. Yousufuddin.	
W.Ws 3. Ch. Appalaswamy.	

Documents exhibited for petitioner :	*Documents exhibited for respondent :*
Ex. W. 1 Appointment order dt. 29.10.1964 of Sri Ch. Appalaswamy issued by the Bank of Baroda, Visakhapatnam.	Ex. M. 1. Annexure 'A' showing the duties performed by the claimant (Ch. Appalaswamy).

(Sd.) P. S. ANANTH,
Industrial Tribunal.

[No. 23/84/69-LR.III.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 30th May 1972

S.O. 1536.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudium (Andhra Pradesh), and their workmen which was received by the Central Government on the 25th May, 1972.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Chairman, Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 24 OF 1969

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.

APPEARANCES:

Sri A. Lakshmana Rao, Advocate, for *Workmen*

Sri K. Srinivasa Murthy, Secretary of Federation of A. P. Chambers of Commerce and Industry, for *Management.*

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour

and Employment) by its Order No. 7/6/69-LRII dt. 27th August, 1969 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for adjudication by this Tribunal, namely.

"Having regard to the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry prescribed for the Technical/Supervisory Staff of the Engineering Department under Chapter VIII, whether the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudium, is justified in allotting Sri M. A. Hannan, Junior Charge-hand, Sand Gathering Station, Kothagudem Division in Grade 'D' of Rs. 205—337. If not, to what relief the workman is entitled and from what date?"

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 24 of 1969 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience the Workman is referred to as the petitioner and the Management is referred to as the Respondent in the course of this Award.

2. The petitioner is a workman of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem. The General Secretary of the Andhra Pradesh Collieries Mazdoor Sangh filed a claim statement contending as follows:— The petitioner was promoted as Junior charge Hand by order dated 29th July, 1966 in the then existing grade of Rs. 48—100 under the Coal Award with a commencing salary of Rs. 75.00 per month with effect from 1st August, 1966. The Wage Board for Coal Mining Industry prescribed eight grades for technical and supervisory staff and the Management of Singareni Collieries Company Limited placed the said workman in Grade 'D', that is, Rs. 205.00—337.00 which is illegal improper and contrary to the recommendations of the Wage Board During the conciliation proceedings the contention of the Management that the matter was subjudice since this issue is pending before the Central Government Industrial Tribunal at Hyderabad is incorrect. The matter which is pending before the said Tribunal is what further modifications to the Wage Board Recommendations are necessary to make them applicable to the Collieries in Andhra Pradesh. It is evident from this that fixation of appropriate category as per the Wage Board recommendations as accepted and implemented by the Management is not the subject matter for adjudication. The present dispute raised is against improper implementation of the Wage Board Recommendations. In Chapter VIII of Volume I at page 78 of the Wage Board recommendations (8) grades i.e. A to H are prescribed for the Technical and Supervisory Staff. It was admitted by the Management's representative at the time of conciliation that the petitioner belonged to the Engineering Department coming under the category of Technical and Supervisory Staff and that the grade of pay was fixed as per the recommendations of the Wage Board. While stating so the Management failed to establish as to how their action in having placed the workman in question in grade 'D', is justified and appropriate. At page 79 under the heading Engineering Department under Serial No. 6 the existing designation is shown as Assistant Foreman Electrical/Mechanical or Junior Shift-in-Charge Electrical/Mechanical, Asst. Electrician and the new designation is shown as Assistant Foreman Electrical/Mechanical and the grade is shown as 'C' and the new consolidated basic scale of pay is shown as Rs. 245—10—305—15—440. The petitioner being Junior Charge Hand comes under the category of Assistant Chargeman and he is entitle to grade 'C'. The contention of the Management at the time of conciliation that this grade of Rs. 205—337 is corresponding one to the old grade of Rs. 48—100 is also not correct. For instance, the clerks who were in the grade of Rs. 48—100 are placed in Grade II of Rs. 205—325 under the Wage Board recommendations by which it is evident that the grades are allotted basing on the different sections keeping in view the actual duties and the prewage board wages. Having agreed that the petitioner comes under the Technical and Supervisory cadre belonging to the Engineering Department, the grade prescribed by the Wage Board for the workmen belonging to the Engineering Department should only be given. So the Singareni Collieries Company Limited may be directed to place the petitioner in grade 'C' i.e. Rs. 245—440 with effect from 16th August, 1967.

3. The respondent is the Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem. In their counter they contended as follows. Since the claim statement has not been filed by the Andhra Pradesh Singareni Collieries Mazdoor Sangh which is a party to the dispute and since the claim statement has been filed by one Andhra Pradesh Colliery Mazdoor Sangh which is not a party to the dispute, there is no obligation on the part of the respondent to file any reply. However the counter is filed bringing out the correct facts. The reference made by the Government of India is not maintainable as the reference is based on the recommendations of the Wage Board for the Coal Mining Industry which is not a statutory one. The Government of India during 1962 constituted Central Wage Board for the Coal Mining Industry in India. During early 1967 the Wage Board submitted its recommendations and the Government of India by their resolution dated 21st September, 1967 accepted certain recommendations as specified therein. In view of the broad agreement on various categorisations which took place in the presence of Sri Kanti Mehta and Sri Lal, Members of the Wage Board during February, 1966 between the Union and the Management the Respondent implemented the recommendations of the Wage Board as approved by the Government of India. The presumption of the petitioner that the recommendations of the Wage Board are accepted by workmen and the management to prefer a claim of this nature is not correct. The contention of the petitioner that the Management has accepted the recommendations of the Wage Board is denied. The acceptance of the recommendations by the Government does not give the recommendation any statutory backing nor they are mandatory in nature. The essential pre-requisites for deciding the Wage structure are to consider the capacity of industry to pay and the principles laid down by the Supreme Court in deciding it based on region-*cum*-industry wise. The Wage Board for Coal Mining Industry had not followed the said principles laid down by the Supreme Court inasmuch as it had not recommended the Wage structure based on region-*cum*-industry wise basis. Further they have not taken the capacity of the industry to bear the additional financial burden and have not recommended the wage structure taking into consideration the large and flourishing concerns on one side and the small, uneconomic and struggling units on the other. In the absence of these, the recommendations of the Wage Board suffer from a fatal infirmity. The reference is also bad in law since the matter of revision of grades for this category of workmen is spending before the Industrial Tribunal, Hyderabad in I. D. No. 30 of 1967. Without prejudice to the preliminary objection the Management submits that the demand of the workmen is not justified even on merits. The petitioner was placed in the pre-wage board grade of Rs. 48—3—54—4—70—EB—5—100 with effect from 29th July, 1964. The Wage Board has prescribed 8 grades A to H for Technical and Supervisory staff vide page 78 of Chapter VIII of Volume I of the Wage Board Report. The Coal Award has not drawn any distinction or fixed any grade for Technical or Supervisory Staff and others. Having regard to his previous grade and technical competency the petitioner was allowed grade of Rs. 205—7—247—10—337. The clerks in Grade II and other categories of workmen who were in the prewage board grade of Rs. 48—100 were allowed a grade of Rs. 205—325. The Management placed the petitioner in an appropriate corresponding grade of Rs.

205—337 in the same manner as it had placed the other workmen in the technical and supervisory cadre. As the demand is raised by the Union it is for the Union to prove that the workman deserves higher grade as the demand of the petitioner is that being the Junior Charge Hand he comes under the category of Junior Assistant Chargemen. The contention of the workmen that he should be given the grade of Rs. 245—440 is not justified. The table at page 79 giving categorisations of some of the Engineering Department Personnel is not exhaustive and there are many other categorisations of workmen who are not covered in this table to which the Management have given the corresponding grade in accordance with the table given at page 78 for Technical and Supervisory Staff. Moreover the designations mentioned in the Wage Board Report in the said table are not in conformity with the practice prevailing in the Singareni Collieries. That was the main reason why the Wage Board had taken the trouble of recommending 8 different grades for Technical and Supervisory Personnel with a view to fix the salaries of personnel who are not specifically covered by the Wage Board recommendations. It may also be noted that the Wage Board grades have a definite relation to the pre-wage board grades of the workers. The Wage Board in recommending various grades at page 79 to some of the personnel of the Engineering Department have not given the pre-wage board grade in which these workmen were placed for whom the grades recommended by them are applicable. The Management does not have on its rolls any person in the Engineering Department with designation as Chargeman or Junior Assistant Chargeman. The grade of Rs. 245—440 has been allowed in the respondent Collieries in relation to the pre-wage board grade to the chargehands who are much more senior to the workman concerned in the dispute. As such the demand of the petitioner for placing him in a grade higher than what has been given to him by the Management cannot be justified and if the demand is acceded to, it will have a chain of reactions wherein the whole wage structure and even other departments too will have to be modified. The grades in which the monthly rated Technical and Supervisory Personnel are to be fitted should be in accordance with the 8 grades recommended by the Wage Board at page 78 and the grade of Rs. 205—337 which has been allowed to the petitioner corresponding to his pre-wage board grade is one of them. The allegations of the Union that the action of the Management is *malafide* and unjust and contrary to the recommendations of the Wage Board are denied.

4. The dispute that is referred to for adjudication by this Tribunal is having regard to the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry prescribed for the Technical/Supervisory Staff of the Engneering Department under Chapter VIII, whether the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem, is justified in alloting Sri M. A. Hannan, Junior Charge-hand, Sand Gathering Station, Kothagudem Division in Grade 'D' of Rs. 205-337. If not to what relief the workman is entitled and from what date?

5. Before considering the above dispute referred to this Tribunal for adjudication, some of the legal objections raised by the respondent may be disposed of. Though in the counter an objection was taken that the reference itself is not maintainable since the reference is based on the recommendations of the Wage Board for the Coal Mining Industry which is not statutory, the learned counsel for the respondent represented that the respondent is not pressing this objection in view of the decision reported in KIRLAMPUDI SUGAR Mills Ltd. *v.* Industrial Tribunal, A.P. [1971 (II) LLJ, page 491 (Supreme Court)]. So there is no need to consider further about this objection.

6. The next objection that is raised in the counter is that since the matter of revision of grades of this category of workmen is pending before this Tribunal as I.D. No. 30 of 1967 this reference is bad in law. So far as this objection is concerned the learned counsel for the respondent did not seriously argue. Even otherwise it is now seen that so far as I.D. No. 30 of 1967 is concerned the dispute referred to is "subject to the views expressed and recommendations made by the Central Wage Board for Coal Mining Industry and the agreement between the Management of Singareni Collieries Company Limited and their Trade Unions referred to, in paragraph 3 to 6 of chapter IX of the Wage Board's report, what further modifications and changes in the categorisation and wage structure recommended by the said Wage Board for West Bengal and Bihar Coal Fields are necessary to make the said categorisation and wage structure applicable to the workmen of Singareni Collieries Company Limited, having regard to the special conditions obtaining in the Andhra Pradesh Coal Fields". So far as the present dispute is concerned it only relate to the question of having regard to the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry, whether the respondent is justified in placing the petitioner in grade 'D'. So the present dispute has nothing to do with the dispute referred to in Industrial Dispute No. 30 of 1967 as rightly contented by the learned counsel for the petitioner.

7. The next objection that is raised in the counter is that the essential pre-requisites for deciding the wage structure are to consider the capacity of the industry to pay and that the wage board has not taken the capacity of the industry to bear the additional financial burden and so the recommendations of the Wage Board becomes a nullity in view of the pronouncements and principles laid down by the Supreme Court in its various decisions. It is also contended by the learned counsel for the respondent that even if the Wage Board's recommendations are not a nullity still the respondent can raise an objection that it has no capacity to pay as laid down in 1971 (II) LLJ, page 491 (Supreme Court). Some evidence has also been let in to show that the Company is working at a loss and it is contended by the learned counsel for the respondent that if the present claim is allowed then there will be chain of reactions wherein the whole wage structure of the Engineering Department and even other departments too will have to be modified and that the Company will not be in a position to meet these demands in view of the fact that the Company has no financial capacity. The learned counsel for the respondent also relied upon the judgement in Writ Petition No. 4076/70 High Court of Andhra Pradesh dated 20th January, 1972 in support of his contention that if a Company has no financial capacity to pay any additional demand, then no additional demand can be granted. He produced a certificate copy of the judgement in the said Writ Petition for my persual and a persual of it shows that the Industrial Tribunal held that as the Company in that case as already working at a loss it did not make much difference if they paid Rs. 5.00 more as monthly House Rent allowance to workers drawing less than Rs. 125.00 per month and Rs. 10.00 to those drawing Rs. 125.00 and more per month. While considering this finding of the Industrial Tribunal his Lordship after referring to the decisions reported in Hindustan Times Ltd., *v.* Their workmen (Air 1963 Supreme Court, page 1332), Workmen or Bajrang Jute Mills *v.* Bajrang Jute Mills (Air 1970 Supreme Court, page 878) and in Hydro (Engineers) Pvt. Ltd. *v.* Workmen (Air 1969 Supreme Court, 182) observed that the question of industries capacity to pay is certainly a relevant consideration in the matter of payment of a fair wage fixed by a Wage Board and that inspite of financial incapacity the Company undertook to implement the recommendations of the Board not that under those circumstances his Lordship did not think that there was any justification for imposoing further burden on the industry to pay anything more than a fair wage, specially when an industry to pay anything more than a fair wage, specially when an industry has no capacity to pay and his Lordship finally disagreed with the finding of the Industrial Tribunal as regards the payment of House Rent Allowance and observed that no further House Rent allowance was payable.

8. The respondent has examined M.W.2 (Sri U Shivaraj) who is the Senior Inspector, Post Audit Section in the Accounts Department of the Company at Kothagudem. He says that the wage increase and other expenditure resulting in the increased cost of production are not fully compensated by the price increase of coal and that the cost of production is increasing by 10 to 15 per cent year by year on account of the rise of prices of stores and that the increment given to the employees of the Company on 15th August, 1970 are not compensated by any prices increase. The respondent also got the deposition of one Sri M. Ranganatham, examined as M.W.2 in Industrial Dispute No. 29 of 1969, marked as Ex. M6 in order to show the financial capacity of the respondent Company. A perusal of Ex. M6 shows that this witness produced the balance sheet for the years 1965 to 1970 marked as Exs. M3 to M7 in Industrial Dispute No. 29 of 1969 and with reference to Ex. M2 he stated that total loss shown during the year 1965-66 was Rs. 2.91 lakhs and that in the year 1969-70 it was Rs. 2.11 lakhs. He had also stated that if two Junior Chargehands in question are given higher grade there will be chain reactions in the higher category persons and that there is danger of higher grade people demanding next higher grade, that if all the sixty persons are given higher grade it would involve an additional burden of Rs. 72,000 per year for the Company. So if this is a case where if any higher grades are asked for without any reference to the Wage Board recommendations then it may be said that the respondent Company would not be in a position to meet the additional burden in view of the loss that the Company had been suffering. But this is case where the respondent had accepted the recommendations of the Wage Board and it had implemented the same and while implementing the recommendations of the Wage Board the petitioner was fixed in Grade 'D' whereas the petitioner's contention is that even as per the recommendations of the Wage Board the respondent should have fitted him in Grade 'C' fixed by the Wage Board as regards the Engineering Department. So under these circumstances the respondent cannot raise the objection about the financial incapacity to pay any additional burden. All that has to be seen in the present case is having regard to the recommendations of the Wage Board whether the respondent is justified in placing the petitioner in Grade 'D' instead of placing him under Grade 'C' which is the grade that is claimed by the petitioner. If it is found that while implementing the recommendations of the Wage Board the respondent ought to have fixed the petitioner in Grade 'C' then the respondent should be directed to place the petitioner in Grade 'C'. So I hold that the objection raised by the respondent that it has no financial capacity to pay is not tenable because the respondent had already implemented the recommendations of the Wage Board and already stated, all that has to be now seen is whether the petitioner is entitled to grade 'C' as contended by him or only to Grade 'D' as contended by the respondent.

9. Now it has to be seen whether the respondent is justified in placing the petitioner in Grade 'D' or whether he should be placed in Grade 'C'. The petitioner has been examined as W.W.1. He says that he is working as Junior Chargehand since 1966, that Ex. W1 is the order appointing him as Junior Chargehand, that he was put in the grade of Rs. 48—100, that he supervises the work of Fitters, Electricians etc., who are working in after the Wage Board recommendations he is placed in the grade of Rs. 205—337, that the Fitters working under him were in VIIth category and they were drawing Rs. 129.00 prior to the implementation of the Wage Board recommendations and that after the implementation of the Wage Board recommendations they are getting total emoluments of Rs. 250.00 whereas his emoluments after the Wage Board recommendations were implemented amount to Rs. 233.00 per month. According to him he is entitled to be placed in Grade 'C' but not in grade 'D'. W.W.2 (Sri K. Azariah) is working as Mechanical Fitter since 1965. He wants to say that W.W.1 allots work to him and that W.W.1 supervises the work of the persons like electricians etc., working in his section. Though he says in chief examination that W.W.1 supervises the work of others, when he is asked whether W.W.1 gives instructions in regard to the work to be done by electricians he says that he does not know. Now the evidence adduced on the side of the petitioner and the contentions of the petitioner are to the affect that since he is doing the supervisory work and since he is working in the Engineering Department, as per the scale of pay for the members working in the Engineering Department as shown at page 79 of Central Wage Board for the Coal Mining Industry Volume I, he is entitled to be placed in Grade 'C' in the scale of Rs. 245—440 but not in the Grade 'D' in the scale of Rs. 205—337.

10. M.W.1 (Sri K. Dharma Reddy) is working as Junior Engineer in the Aerial Ropeway and Sand Gathering Station where W.W.1 and W.W.2 are working. He says that prior to the Wage Board the petitioner was in the scale of Rs. 48—100, that the petitioner was a Welder in the VIIth Vategory before he was promoted to this scale, that he was placed in the Grade of Rs. 205—337 after the implementation of the Wage Board, that there was no distinction in the grade between a Technical and Non-Technical staff, that there are 8 grades recommended for Technical and Supervisory Staff as shown at page 78 of the Wage Board's recommendations, that all the workers in Rs. 48—100 grade were placed in the Grade of Rs. 205—337, that there is no designation of Junior Chargehand at page 79 of the Wage Board's recommendation in the Engineering Department, that Ex. M1 is the Circular issued by the General Manager, that there is no designation of Junior Assistant Chargemen in the Company either prior to or subsequent to the Wage Board, that the table at page 79 of the Wage Board's recommendations is not exhaustive of all the categories and grades of Engineering Department, that the Company has given corresponding grade to all workmen who are not specifically mentioned in the Wage Board's recommendations, that the grade of Rs. 245—440 is given to Chargehands who were in the grades of Rs. 150—185 and Rs. 70—158 prior to the Wage Board, that they were superior to Rs. 48—100 people, that he gives instructions to the Assistant Foremen in regard to the work and he allots work to the Assistant Foremen in regard to the work and he allots work to the various workers including the petitioner and that the petitioner does not have knowledge of mechanical or electrical machines. So his evidence is to the effect that the petitioner does not have any knowledge of mechanical or electrical machines and that he is not having any supervisory capacity and that it is the Assistant Foremen who allots work according to his (M.W.1) instructions. He says that it is not correct to suggest that Junior Chargehand is the same as Junior Assistant Chargemen. He also says that it is not correct to suggest that the lowest grade in the Engineering Department as recommendedV by the Wage Board is Rs. 245—440. According to him the lowest grade in their Company in the Engineering Department is Rs. 205—337. He also says that there was no Junior Chargehand in the Sand Gathering Station prior to the petitioners promotion and that in Ex. M1 there are Tracers and Maistries who are placed in the Grade of Rs. 180—273 and that that is the Minimum under the Engineering Department. M.W.2 is working as Senior Inspector, Post Audit Section of the Company at Kothagudem. He says that the Junior Chargehands were in grade of Rs. 48—100 previously and that while implementing the Wage Board the grade of Rs. 205—337 was given as recommended for the Technical and Supervisory Staff and that the Chargehands who were in the Grades of Rs. 70—158 and Rs. 115—200 were senior to the Junior Chargehands. So the evidence of M.W.1 and M.W.2 is to the effect that since the petitioner was in the old grade of Rs. 48—100 he was given new grade 'D' and that the Chargehands who were seniors to the Junior Chargehands and who were in the gardes of Rs. 70—158 and Rs. 115—200 were given grade 'C' in the scale of Rs. 245—440.

11. Now it is contended by the learned counsel for the Petitioner that the supposed promotion in effect amounts to demotion, that prior to the Wage Board the petitioner was in old category IX and he was promoted as Junior Chargehand, that after the implementation of the Wage Board recommendations old category IX is fixed in new category VI and the Junior Chargehands are placed in grade 'D' prescribed for Technical and Supervisory Staff whereas the petitioners should have been fixed under Grade 'C' and that Junior Assistant Chargemen shown as Item No. VI under the heading Engneering Department at page 79 of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry Volume I is the same as Junior Chargehand and that if the petitioner was continued in his old scale the petitioner would be drawing more pay than what has given now to him and that the respondent ought to have fixed the petitioner only in grade 'C' but not in Grade 'D'. On the other hand it is contended by the learned counsel for the respondent that when there are member of scales perior to the Wage Board's recommendations several persons in the several grades have to be fitted in their respective grades as per the Wage Board recommendation, that even persons who were in the scale of Rs. 70-100 and who were in category 6 like the persons who were in the scale of Rs. 48-100 were also placed in grade 'D' just like the petitioner and that if the petitioner's contention is accepted then those persons also would similarly ask for revision of the grades and that it is only by taking into consideration the scales of pay and the old categories as they existed prior to the Wage Board recommendations the petitioner and others were fixed up on the relevant grades following the recommendations of the Wage Board and that there is no justification for the petitioner in asking the respondent to place him in grade 'C'.

12. A persual of page 78 of the Wage Board recommendations shows that while fixing the wage structure in the Technical and Supervisory Staff and their scales of pay the Wage Board bearing in mind the responsibilities and duties of the Technical and Supervisory Staff the Wage Board divided it into 8 grades *i.e.* A to H and fixing the scales of basic pay as shown therein Nodoubt a persual of page 79 of the Wage Board recommendations shows that taking into consideration that no specific scales of pay were prescribed by the Mazumdar Tribunal, the Wage Board had to recommend the scales of pay for the employees in the Engneering Department as shown in the table and that the Wage Board treating the Assistant Foreman Electrical/Mechanical Junior Assistant Chargemen, Shift In-charge Elec/Mech and Assistant Electrican as Assistant Foremen Electrical/Mechanical fixed grade 'C' to it does not mean that it is only minimum scale that has been fixed for the staff working in the Engneering Department as is now contended for the petitioner. From the evidence it is seen there had been different scales of pay and different categories prior to the Wage Board recommendations and the Wage Board recommendations do not cover all the different categories in this company. Though the petitioner now wants to equate the designation of Junior Chargehand to the new designation of Assistant Foremen Electrical/Mechanical mentioned in the Wage Board recommendations, the evidence in this case and the nature of the work done by the petitioner shows that he cannot come under the new designation or under the existing designation shows in page 79 of the Wage Board recommendations. The old category in which the petitioner was working prior to the Wage Board recommendations and the scale of pay that he was drawing also should be taken into consideration for the purpose of implementing the recommendations of the Wage Board. Now the evidence shows that the Chargehands who were in the grades of Rs. 70—158 and Rs. 115—200 were placed in grade 'C' for which the scale of pay is Rs. 245—440. Admittedly the petitioner was in the old scale of Rs. 48—100 in old category VI. The evidence also shows that there were others also in the same old category VI who were in the old scale of pay of Rs. 70—100 and that they were also placed in grade 'D'. So virtually the petitioner's present request appears to be that he wants the same grade 'C' that is given to the persons who were in the scales of Rs. 70—158 and Rs. 115—200. certainly it could never have been the intention of the Wage Board to fix any minimum scale for the Engineering Department in such a way as to make the persons in the old scales of pay of Rs. 48—100 and Rs. 70—100 and Rs. 70—158 and Rs. 115—200 draw the new scale of pay of Rs. 245—440. All that can be said in the present case is that the Wage Board had taken into consideration only certain existing designations at the time of making the recommendations and given them new designations and fixed the grade and the new consolidated basic scale of pay in respect of those grades so far as the Engineering Department is concerned. So it does not mean that every person working in Engineering Department is concerned. So it does not mean that every person working in Engneering Department should be only placed in Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 245-440. It is the scale of pay that was drawn prior to the recommendations of the Wage Board and also the old categories in which those persons were working that should be taken into consideration and the fitment should be made as per the recommendations of the Wage Board as per the scale of basic pay and grades A to H fixed for the Technical and Supervisory Staff and scales of pay as shown at page 78 of the recommendation of the Wage Board. Now the evidence of M.W.1 is that all the workers working in the old scale of Rs. 48-100 were placed in the grade of Rs. 205-337 and the evidence of M.W.2 that while implementing the Wage Board the grade of Rs. 205-337 was given as recommended for the Technical and Supervisory Staff. When persons who were in the scales of Rs. 70-158 and Rs. 115-200 were placed in grade 'C' in the scale of Rs. 245-440 the present claim of the petitioner that even though he was in the old scale of Rs. 48-100 he is entitled to be placed in grade 'C' but not grade 'D' is not at all justified. Considering the recommendations of the Wage Board I am satisfied that the petitioner was rightly placed in Grade 'D' by the respondent and that he is not entitled to be placed in grade 'C'.

13. For all the afore said reasons I hold on the dispute that is referred to for adjudication that having regard to the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry prescribed for the Technical/Supervisory Staff of the Engneering Department under Chapter VIII the Management of Singareni Collieries Company Limited' Kothagudem is justified in alloting Sri M. A. Hannan, Junior Chargehand, Sand Gathering Station, Kothagudem Division in grade 'D' of Rs. 205-337 and so the workman is not entitled to any relief.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 24th day of April, 1972.

(Sd.) P. S. ANANTH,
Industrial Tribunal.

Appendix of Evidence

Witness examined for Workmen:

W.W.1.—M. A. Hannan.

W.W.2.—K. Azariah.

Documents exhibited for Workmen:

Ex.W.1.—Promotion Order of Junior Chargehand date 29th July, 1966 in respect of Hannan.

Witnesses examined for Employers:

M.W.1.—K. Dharma Reddy.

M.W.2.—U. Shivaraji.

Documents exhibited for Employers:

Ex. M1.—Circular date 27th January, 1968 issued by the Management in respect of implementation of the recommendation of the Central Wage Board for monthly rated staff.

Ex.M.2.—Daily attendence Report of Sand Gathering Station date 22nd December, 1970.

Ex.M.3.—Men on roll of aerial ropeway drive station as on 22nd December, 1970.

Ex. M.4.—Lr. of Khazanuya addressed to the Jr. Engneer, Sand Gathering St. requesting for four days pay leave.

Ex.M5.—Lr. of M. A. Hannan, Jr. Chargehand, addressed to the Jr. Engneer, Sand Gathering St. requesting to sanction leave for three days.

Ex.M.6.—M.W.2 of M. Ranganatham recorded on 5th April, 1971 in I.D. No. 29 of 1969.

(Sd.) P. S. ANANTH,
Industrial Tribunal.

[No. 7/6/69-LRII.]

S.O. 1537.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Belampalli Division, Post Office Belampalli (Andhra Pradesh), and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th May, 1972.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri P. S. Ananth, B.Sc., B.L., Chairman, Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad.

INDUSTRIAL DISPUTE 43 OF 1971

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited Bellamapalli Division

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Bellamapalli Division

APPEARANCES:

Sri Shyam Mohan, Personnel Officer, *for Management.* Sri B. Ganga Ram, Vice-President, S. C. Workers' Union, Bellampalli, *for workmen.*

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rhabilitation (Department of Labour and Employment) by its Order No. 7/36/70-LRII, dated 15th May, 1971, referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the said Act) for adjudication by this Tribunal, namely:

"Whether the management of Singareni Collieries Company Limited, Bellamapalli Division No. 2 Incline is justified in refusing the benefit of gratuity to the medically unfitted worker Shri Boddula Rajam, Pope Slicer, No. 2 Incline who was retired on 18th April, 1961? If not, to what relief is the workmen entitled?"

This reference was taken on file as Industrial Dispute No. 43 of 1971 and notices were issued to the parties. For the purpose of convenience the Workmen is referred to as the petitioner and the Singareni Collieries Company Limited, Bellamapalli Division is referred to as the respondent in the course of this award.

2. The petitioner is represented by the Singareni Collieries Workers Union, and the Vice-President of the said Union file a claim statement contending as follows: The petitioner was working as a Pope Slicer in No. 11 incline, Bellamapalli. He met with an accident while on duty during the year 1960, and his left leg was fractured and he was under treatment for one year and he was medically made unfit with effect from 19th March, 1961. On 10th October, 1961, he was paid a sum of Rs. 48.62 towards gratuity for two years but his gratuity for 28 years was not paid on the plea of participating in illegal strike of 1959. The Management had agreed to condone the break of service of all workers on account of illegal strike of 1959, through a memo of settlement dated 9th October, 1969 before the Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi and as per this settlement all those who had retired after 1959 were paid the difference of gratuity for their service prior to 1959 but in this case, the Management did not agree to pay gratuity. The contention of the Management that the settlement dated 9th October, 1969 applies to those who are in service on or after 9th October, 1969 is not correct since all the workers who retired after 1959, have been paid the difference of gratuity. The action of the Management in refusing to pay gratuity to the petitioner is quite unjustified. So the petitioner should be paid full gratuity.

3. The respondent filed its counter contending that a sum of Rs. 510.51 was already sanctioned towards the difference of gratuity in April, 1965, condoning the break in service due to the petitioner's participation in the illegal strike of 1959, that the petitioner did not receive the amount, that as the amount was already sanctioned prior to 1969 the memo of settlement dated 9th October, 1969 is irrelevant to the issue and that the Management is ready to pay the difference of gratuity if the petitioner approached the management and that the management never refused to pay the difference of gratuity.

4. The dispute that is referred to this Tribunal for adjudication is whether the management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division No. 2 incline is justified in refusing the benefit of gratuity to the medically unfitted worker Shri Boddula Rajam, Rope Slicer, No. 2 incline who was retired on 18th April, 1961? If not to what relief is the workmen entitled?

5. After the issue of notices to the parties and after filling of the claim statement on behalf of the petitioner and after filing of the counter by respondent, when the matter was posted for enquiry to 28th January, 1972 it was represented by Sri B. Ganga Ram, Vice-President of the Union, that talks of settlement were going on. So the matter was adjourned from time to time at request and finally on 15th May, 1972 the said Vice-President of the Union sent a petition stating that the Union is withdrawing the claim and so the reference may be disposed of accordingly and in the petition it is stated that the Management had paid a sum of Rs. 510.51 ps. in full and final settlement of the gratuity amount payable to him as per the rules. The respondents' representative has endorsed "no objection" on the petition.

6. The dispute that is referred to for adjudication by this Tribunal refers to the payment of gratuity. Now the petitioner has received the gratuity amount due to him and the representative of the petitioner has filed a petition for withdrawing the claim. In view of this there is no question of holding any further enquiry in this case. In as much as the parties have settled the matter and since the petitioner himself wants to withdraw the claim made by him through the Union, permission is granted for withdrawing he claim made by the petitioner.

Awawrd is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 16th day of May, 1972.

P. S. ANANT,

[No. 7/36/70-LRII.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 5th June, 1972

S.O. 1538.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 3), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Amlabad Colliery, the managing Agent of whom are Messrs Karamchand Thapar and Brothers (Private) Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th May, 1972.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
(NO. 3)
AT DHANBAD

REFERENCE NO. 43 OF 1969

PRESENT:

B. S. Tripathi,
Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the Amlabad Colliery

Vs.

Their workmen.

APPEARANCES:

For employers: None.

For workmen: None

INDUSTRY: Coal STATE: Bihar

Dhanbad, dated the 24th May, 1972.

AWARD

1. This is a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947. The Centre being of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Amlabad Colliery, the Managing Agents of which are Messrs Karamchand Thapar and Brothers (Private) Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule annexed thereto, referred the same to this Tribunal for adjudication. The Schedule is extracted below:—

SCHEDULE

"Whether the management of Amlabad Colliery, the Managing Agents of which are Messrs Karamchand Thapar and Brothers (Private) Limited, Post Office Bhowra, District Dhanbad, was justified in retiring the following workmen on completion of their 58th year of age?'

1. Shri Rameshwar Pandey, U/G Incharge
2. Shri Saheb Jan Mian, Mining Sirdar.
3. Shri Sripati Lal Chakravarty, U/G. Incharge.
4. Shri Mathura Rewani, Mining Sirdar.
5. Shri Joti Bourin, Haulage Khalasi.
6. Shri Kukhan Roy, Haulage Khalasi.
7. Shri Jailal Napit, Line Mistry.
8. Shri Dantoo Mahato, Line Mazdoor.
9. Shri Warda Napit, Pump Khalasi.
10. Shri Abdul Mian, Mechanical Helper.
11. Shri Ebrahim Mian, Tyndal Mazdoor.
12. Shri Sakhi Dusadh, Banksman.
13. Shri Akaloo Bhuia, Surface Trammer.
14. Smt. Fulmani Napit, Creche Kamin.
15. Smt. Sakhia Rajwaria Creche Kamin.

If not, to what relief are the workmen entitled and what should be their age of retirement?"

2. The dispute in question was raised by the Congress Mazdoor Sangh, Bihar and in the present proceeding the written statement on behalf of the workmen was filed on 7th February, 1970 by the General Secretary of Congress Mazdoor Sangh, Bihar. The written statement on behalf of the employers was filed on 6th January, 1970. According to the case made out by the workmen in their written statement, the management of the colliery in question were not justified in retiring the workmen listed in the schedule to the reference on completion of 58 years of age and as such the said workmen should be allowed to resume their respective duties with full back wages and allowances as if they were continuing in their employment. The case of the employers on the other hand is that the workmen in question were rightly retired from services on completion of their 58 years and 58 years should be fixed as age of retirement. In that view of the matter it is stated that the action of the management in retiring the concerned workmen on the completion of 58 years was fully justified, and they are, therefore, not entitled to any relief in the present reference. In their respective written statements both the parties have given reasons in support of their respective claims.

3. After submission of written statements by the parties the proceeding was adjourned from one date to the other and ultimately on 1st January, 1972 it was adjourned to 4th March, 1972 for hearing. On 4th March, 1972 neither party appeared nor any step was taken on their behalf. The proceeding was, however, adjourned to 14th April, 1972. On the latter date also neither party appeared nor any step was taken on their behalf. On this date too the Tribunal adjourned the proceeding to 24th May, 1972 for hearing. On 24th May, 1972 also neither party appeared nor any step was taken on their behalf. This clearly indicates that neither party is interested in the disposal of the reference on merits and accordingly I pass 'NO DISPUTE' award in the present reference.

4. Let the award be submitted to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

Sd.) B. S. TRIPATHI,
Presiding Officer,
Central Govt. Industrial Tribunal-*cum*-Labour Court No. 3, Dhanbad.

[No. 2/98/68-LRII.]

S.O. 1539.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Godhpur Colliery of Messrs Godhur Colliery Company, Post Office Kusunda, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st May, 1972.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 1), DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

REFERENCE NO. 95 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Godhur Colliery of M/s. Godhur Colliery Company, P.O. Kusunda, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen.

PRESENT:

Shri A. C. Sen, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For the Workmen.—Shri B. N. Singh, Advocate.

STATE: Bihar INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, the 23rd of May 1972

AWARD

The present reference arises out of Order No. L/2012/182/71-LRII dated New Delhi, the 24th of December, 1971 passed by the Central Government in relation to an industrial dispute between the parties mentioned above. The dispute is in relation to the matters specified in the schedule to the aforesaid order which runs as follows:

2. The matter has been settled out of Court. A hur Colliery of Messrs Godhur Colliery Company, Post Office Kusunda, District Dhanbad in stopping Shri Shyam Lal Lohar, Mechanical Fitter from work with effect from the 28th May, 1971 and subsequently terminating his services with effect from the 28th June, 1971 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?".

2. The matter has been settled out of Court. A compromise petition dated 11th May, 1972 was filed on 11th May, 1972. I have gone through the terms of settlement, which appear to be quite reasonable. I do not find any reason why those terms should not be accepted. I accordingly make an award on the basis of the terms and conditions laid down by the petition of compromise. Let the petition of compromise form a part of the award. A copy of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action.

(Sd.) A. C. SEN,
Presiding Officer.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

REFERENCE No. 95 OF 1971

Employers in relation to the management of Godhur Colliery.

AND

Their workmen.

That without prejudice to the contensions of the parties contained in their respective written statement the disputes concerning the above Reference have been amicably settled between the parties on the following terms:—

(1) That the services of Shri Shyamlal Lohar, the concerned workman, will stand terminated with effect from 28th June, 1971.

(2) That Shri Shyamlal Lohar will be paid a sum of Rs. 2417.13 (Rupees Two thousand four hundred seventeen and paise thirteen) only in full and final settlement of all his claim and demand till the date of the settlement. The amount has been paid today. The receipt whereof is acknowledge.

(3) That Shri Shyamlal Lohar will have no other or further claim against the management on any other account.

(4) That there remains no dispute between the parties which needs any further adjudication by the Honourable Tribunal.

(5) That both parties agree that the above terms are fair and reasonable.

It is, therefore, humbly prayed that this settlement may kindly be accepted and an Award be passed in terms thereof.

For the management of
Godhur Colliery.

L.T.I. of Shri Shyamlal Lohar.
For Workman
(Sd.) B. N. SINGH,
Advocate

(Sd.) J. C. DHAR,
Manager.
Godhur Colliery,

(Sd.) S. S. MUKHERJEE,
Advocate.

[No. L/2012/182/71-LRII.]

New Delhi, the 7th June, 1972.

S.O. 1540.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1). Dhanbad, in the industrial dispute between the employers tin relation to the management of Lodna Colliery of Messrs Lodna Colliery Company (1920) Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st May, 1972.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDST. RIAL TRIBUNAL (No. 1), DHANBAD.

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

REFERENCE NO 8 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Lodha Colliery of Messrs Lodha Colliery Company (1920) Limited, Post Office, Jharia, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen.

PRESENT:

Shri A. C. Sen, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers.—Shri J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser, Bharat Coking Coal Ltd.

For the Workmen.—Shri J. D. Lall, Advocate with Shri Motilll Prashad, workman concerned.

STATE: Bihar INDUSTRY: Coal

Dhanbad, the 23rd May, 1972.

AWARD

The present reference arises out of Order No. L/2012/55/71-LRII dated New Delhi, the 3rd June, 1971, passed by the Central Government in relation to an industrial dispute between the parties mentioned above. The dispute is in relation to the matters specified in the schedule to the aforesaid order which runs as follows:

"Whether the action of the management of Lodna Colliery of Messrs Lodna Colliery Company (1920) Limited, Post Office, Jharia, District Dhanbad, in dismissing Shri Moti Lall Prasad, Clerk, with effect from the 18th January, 1971, is justified. If not, to what relief is the workman entitled ".

2. It appears that the dispute has been settled by the parties out of Court. The memorandum of settlement dated 23rd May, 1972, signed by the parties has

been filed today. The memorandum ends with the prayer that an award be given in terms of the settlement. I have gone through the memorandum of set tlement. The terms of settlement are very reasonable. I do not find any reason why the said terms should not be accepted. I accordingly give an award on the basis of the terms contained in the memorandum of settlement, which do form part of the award. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) A. C. SEN,
Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 1), AT DHANBAD

IN THE MATTER OF:

REFERENCE NO. 8 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to Lodna Colliery of M/s. Lodna Colliery Co. (1920) Ltd.

AND

Their Workmen.

Memorandum of Settlement

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated:

(1) That Shri Moti Lal, Pd. (Clerk) the workman concerned in the present Reference shall be reinstated by the management of Lodna Colliery of M/s. Lodna Colliery Company (1920) Ltd. on and from 22nd May, 1972, without any back wages.

(2) That the period introducing from the date of dismissal (which gave rise to the present Reference) till the date of resumption of duty shall, for the purpose of continuity of service, be treated as leave without pay, but the workman concerned will be eligible to proportionate leave or quarterly bonus provided he puts in proportionate qualifying attendance during the remaining period of current year or current quarter, as the case may be.

(3) In the event of the failure of the concerned workman report for work within a fortnight from 22nd May, 1972 the workman concerned shall have no right for re-employment etc. under this agreement.

(4) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no substituting dispute adjudication in the present reference.

(5) Theh parties shall bear their own cost of proceedings.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Settlement and to give its Award in terms thereof.

For the Employer. *For the Worker.*
(Sd.) Illegible.

(Sd.) ILLIGIBLE,
Manager. Advocate.
Lodna Colliery:

For Bharat Coking Coal Ltd
(Sd.) J. N. P. SAHI,
Labour and Law Adviser.
Bharat Coking Coal Ltd.
(Sd.) MOTILAL PRASAD,
Workman concerned.

Dated 23rd May, 1972.

[No. L/2012/55/71-LRII.]

S.O. 1541.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sendra Bansjora Colliery of Messrs the Sendra Bansjora Colliery Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 31st May, 1972.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

REFERENCE NO. 31 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Sendra Bansjora Colliery of Messrs. The Sendra Bansjora Colliery Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri A. C. Sen, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers.—Shri J. N. P. Sahi, Labour and Law Adviser, Bharat Coking Coal Ltd.

For the Workmen.—Shri S. Dasgupta, Joint General Secretary, Colliery Mazdoor Sangh.

STATE: Bihar. INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, the 25th May, 1972.

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-2012/104/71-LR.II, dated New Delhi, the 28th July, 1971, passed by the Central Government in relation to an industrial dispute between the parties mentioned above. The dispute is in relation to the matters specified in the schedule to the aforesaid order which runs as follows:

"Whether the action of the management of Sendra Bansjora Colliery of Messrs. The Sendra-Bansjora Colliery Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad, in suspending from duty and stopping from work of Shri Raso Bauri, Miner from 11th January, 1971 and 6th March, 1971 respectively and subsequently, dismissing him with effect from 19th April, 1971 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The dispute has been amicably settled between the parties out of Court. A memorandum of settlement dated 25th May, 1972 has been filed to-day. It has been signed by all the parties concerned. I have gone through the terms mentioned in the memorandum. They appear to be quite reasonable. I do not find any reason why they should not be accepted. Let an award be made on the basis of the terms and conditions of the memorandum of settlement, which do form part of the award. A copy of this award may be forwarded to the Central Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) A. C. SEN,
Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of reference No. 31 of 1971

PARTIES:

Employers in relation to SENDRA BANSJORA COLLIERY of M/s. Sendra Bansjora Colliery Co. Pvt. Ltd.

AND

Their Workmen.

Memorandum of Settlement

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated:—

(1) That Sri Raso Bauri (Miner) the workman concerned in the present Reference shall be reinstated by the management of Sendra Bansjora Colliery of M/s. Sendra Bansjora Colliery Co. Pvt. Ltd. on and from 1st June, 1972 without any back wages.

(2) That the period intervening from the date of dismissal (which gave rise to the present reference) till the date of resumption of duty shall, for the purpose of continuity of services, be treated as leave without pay, but the workman concerned will be eligible to proportionate leave or quarterly bonus provided he puts in proportionate qualifying attendance during the remaining period of current year or current quarter, as the case may be.

(3) In the event of the failure of the concerned workman to report for work within a fortnight from 1st June, 1972 the workman concerend shall have no right for re-employment etc. under this agreement.

(4) The above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

(5) The parties shall bear their own cost of proceedings.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this settlement and to give its Award in terms thereof.

For the Employer

(Sd.) Illegible.
Agent

Sendra Bansjora Colliery

For the Workmen.

Jt. General Secy.
Colliery Mazdoor Sangh

For Bharat Coking Coal Ltd.

(Sd.) J. N. P. SAHI,
Labour and Law Adviser,
Bharat Coking Coal Ltd.

Dated 25th May, 1972.

[No. L/2012/104/71-LRII.]

New Delhi, the 8th June 1972

S.O. 1542.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employees in relation to the management of Damra Colliery of Messrs Katras Jherriah Coal Company Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th May, 1972.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

REFERENCE No. 69 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Damra Colliery of Messrs Katras Jherriah Coal Company Limited,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Sri S. N. Bagchi Presiding Officer.

APPEARANCE:

On behalf of Employers
Sri D. Narsingh, Advocate.

On behalf of Workmen
Sri Raj Deo Singh, General Secretary of the Union, with Sri U. C. Roy, Legal Adviser.

STATE: West Bengal. INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. L-1912/18/71-LR.II, dated 5th May, 1971, the Government of India, in the Ministry of Labour , Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Damra Colliery of Messrs Katras Jherriah Coal Company Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the management of Damra Colliery of Messrs Katras Jherriah Coal Company Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan was justified in dismissing from service Shri Ramdhari Singh, Civil Peon with effect from the 28th October, 1970? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. Notices were issued to both the parties. The management filed its statement of case on 27th June, 1971 and workman on 24th July, 1971. The management stated *inter alia* that the workman Sri Ramdhari Singh, designated as Peon was on duty at Damra Colliery as night guard in the second shift on 7th September, 1970 from 4 P.M. to 12 MID-NIGHT and was found sleeping on 7th September, 1970 during his shift at about 9.15 P.M. As the misconduct was very grave, he was served with a chargesheet dated 9th September, 1970 calling upon him to show cause why disciplinary action should not be taken against him under Clause 27(10) of the Standing Orders in terms of which "sleeping on duty" is misconduct. The workman gave reply to the chargesheet. There was an enquiry in the presence of the workman. Statements of witnesses for the management were recorded as well as the workman's statement. He had no witness for examination. The management's witnesses were allowed to be cross-examined by the workman and he cross-examined the first two witnesses and declined to cross-examine the third. After the enquiry was over the Enquiry Officer submitted his report observing that he had found the workman guilty of the misconduct as stated in the chargesheet. Before the first enquiry was over, the workman was again found sleeping on duty as night guard during 22nd/23rd September, 1970 when he was on duty in the third shift from 12 mid-night to 8 A.M. He was levelled with another chargesheet on 23rd September, 1970 calling upon him to show cause why disciplinary action should not be taken against him under the same Standing order being No. 27(10). The workman submitted his reply to the second chargesheet denying all the charges levelled therein. There was an enquiry on the second chargesheet with due notice wherein the workman participated. After the

statements of management's witnesses were recorded the statement of the workman. The workman produced no witness on his behalf. After considering the materials, the enquiry officer submitted his report in which he found the workman guilty of the misconduct stated in the charge. The General Manager, the top Executive Officer of the company considered the proceeding of the two enquiries and recommendations on the two enquiries and agreed with the findings of the enquiry officer containing in the two reports and ordered dismissal of the workman. Thereafter the manager informed the workman by letter dated 24/28th October, 1970 that the General Manager had ordered his dismissal for his misconduct on two charges with immediate effect.

3. The management also raised a question as to the competency of the reference as being not an industrial dispute on the score that the workman concerned at no time raised the dispute as under reference before the management. So they challenged the jurisdiction of this tribunal to entertain the reference and to adjudicate on the point under reference.

4. The union representing the workman through the General Secretary, Khan Mazdoor Sangh in its statement of case filed on 24th July 1971 alleged that for demanding overtime wages, khoraki, night allowance by the workman of the management, the management, the management was angry with the workman and planned to dismiss him and dismissed him on false and fabricated charges. The workman after dismissal applied for the copy of the enquiry proceedings but the Manager refused to supply with the copy. The management has no ground or justification for dismissing the workman with effect from 28th October 1970, and that the workman deserves to be reinstated in his job with full back wages and other statutory benefits. The union ultimately prays that the dismissal of Ramdhary Singh should be held as unjustified on the part of the employer and the management should be directed to reinstate the workman in his post with all monetary benefits from the date of his dismissal till the date of his reinstatement.

5. On 1st September 1971 the management presented a rejoinder to the written statement submitted on behalf of the workman. In the relevant paragraph 11 the management again reiterated that the dispute raised by the union by its letter addressed to the Assistant Labour Commissioner, Asansol on 14th December, 1970 did not amount to an industrial dispute. The other matters in the rejoinder are not relevant.

6. Both the sides were represented by their learned Counsel. Upon hearing the learned Counsel of both the sides and perusing the statement of case filed by the parties and the rejoinder the following points arise for decision:

(i) Did the workman raise any dispute over the subject matter under reference with the management?

(ii) Did the union representing the workman raise any dispute before the management and thereafter made the demand to the Government?

(iii) Is the dispute under reference an industrial dispute? If not has the tribunal jurisliction to entertain the same for adjudication?

(iv) Was the dismissal of the workman justified?

Decision

Points (i), (ii) and (iiii):

7. These three points are considered together. The management in its statement of case in paragraph 2 stated that the workman never raised with the management any demand over the matter in dispute. The union representing the workman in its statement of case filed on 24th July 1971 did not traverse the management's statement in paragraph 2 of its statement. The management in its rejoinder filed on 1st September 1971 in paragraph 11 stated that the dispute raised by the union by its letter to the Assistant Labour Commissioner, Asansol on 14th December, 1970 did not amount to an industrial dispute. The union representing the workman in its statement filed on 12th April 1972 in paragraph 3 stated "with reference to paragraph 11 of the employer's rejoinder it is submitted that the union had put up the matter before the management as per letter No. KMS/177 of 26th November 1970 through registered post Acknowledgement due which was refused by the employers (shall be filed on 15th May 1972)". The employer filed another rejoinder with reference to the allegation in paragraph 3 of the union's statement filed on 12th April 1972. In paragraph 3 of such statement it is said, with reference to Union's letter dated 26th November, 1970, that the matter stated in paragraph 3 of the union's rejoinder filed on 12th April 1972 was vague and unconvincing. On the date of hearing, a registered letter with acknowledgement due was filed in an envelope. The envelope, Ext. W3, was addressed to the Superintendent Personnel, Katras Jherriah Coal Company, Dishergarh, Distt. Burdwan. It bears two post marks (i) Ukhra dated 10th December, 1970 and another 'Dishergarh dated 5th December, 1970. On the back of the envelope there is an endorsement "Refused" with the date 7th December, 1970 bearing an undecipherable initial. The closed envelope was opened in the Court room in presence of the parties. It is a replica of Ext. W2, the copy addressed to the Superintendent Personnel, by the union relating to the dismissal of the workman. After reiterating the facts and characterising the dismissal as victimisation the union requested the Superintendent Personnel of the Colliery concerned to reconsider the matter of dismissal of the workman and to reinstate him with full back pay. On behalf of the management it was submitted by Mr. Narsingh the learned Advocate that assuming that the envelope contained the copy of the letter Ext. W2, the union did not in its statement filed on 12th April 1972 disclose as to whom the letter was addressed and used a very vague term 'management' and that if the union specifically stated that the letter was addressed to the Superintendent Personnel and that it was refused by him, the management could have produced the Superintendent Personnel for examination as an witness on behaf of the management. So Mr. Narsingh submitted that upon such vague assertion of facts the tribunal should not accept that Ext. W3 containing the copy of the letter Ext. W2 was tendered to the Superintendent Personnel and was refused. It cannot be now disputed that a registered letter duly addressed and posted with acknowledgement due if comes with an endorsement 'refused' raises a presumption, which, however, is rebuttable, that the letter was tendered to the addressee and he refused to accept the letter. Mr. Narsingh's argument was that if the clerk of the office of the Superintendent Personnel would have been produced, he could have stated whether or not the particular envelope was tendered to him who was, in official course of business, to accept all letters addressed to the Superintendent Personnel of the colliery concerned. Mr. Narsingh however missed the point that the postal peon should be presumed to have done his official duty in regular course of business. So, mere production for examination of the clerk of the Superintendent's office would not discharge the burden to dislocate the presumption raised on the endorsement 'refused' appearing on the back of the envelope subscribed by the postal peon when the envelope containing the letter was properly addressed and registered with acknowledgement due. The postal peon is likely not to deny the performance of his official duty in regular course of business. However, Mr. Narsingh, learned Counsel for the management did not press the point further. It is clear, therefore, irrespective of the question whether the workman raised the demand

before the management or not, the union had on behalf of the workman raised the demand before the management and the management did not accede to their demand. Therefore, in this case the mischief of law as laid down in Sindhu Resettlement Corporation *vs.* Industrial Tribunal Gujrat, 1968 I LLJ p. 834 does not apply nor the decision in the case of Feeder Lloyds & Co., *vs.* Lt. Governor, Delhi reported in F.L.R. 1970(20) p. 383. So, I hold that there is an industrial dispute relating to the subject matter under reference and the Government has lawfully referred the dispute for adjudication by this Tribunal which has the jurisdiction to entertain and adjudicate upon the matter in dispute referred to it for adjudication.

Point (iv):

8. The union nowhere challenged the propriety, legality and conformity with the principles of natural justice in regard to the two domestic enquiries in which the workman concerned was found guilty of misconduct leading to his dismissal. The burden of the song of the union's case has been that because the workman demanded certain allowances of the management, the management was enraged with the workman and manufactured two false charges against him and through interested witnesses got the false charges proved against the workman leading to his dismissal. The union, therefore, contended that it was a case of victimisation. Accordingly, the union attempted to make out that the dismissal of the workman should be held invalid and improper smacking of victimisation and the tribunal should, on setting aside the order of dismissal, reinstate the workman to his post with back wages and other benefits.

9. The charge against the workman was 'sleeping while on duty'. There can be no doubt and dispute now that not only under the Standing Orders but also under the law as laid down by the Labour Appellate Tribunal in the case of Ford Motor Co. of India Ltd. and S. K. K. Nail, 1952 I LLJ p. 388, that sleeping while on duty is a grave misconduct. The first charge is Ext. M2 and it is replied by the workman *vide* Ext. M2(1). The chargesheet is dated 9th September 1970. The management alleged that the peon while on guard duty in depot area on 7th September 1970 in 2nd shift, was found sleeping on a sand heap near a pit top at about 9-15 p.m. by the Engineer, wherefor he was charged under paragraph 27(10) of the Standing order. He was asked to show cause why disciplinary action should not be taken against him. The reply by the workman was that the charge was false, *malafide* and concocted. The workman hammered nine times the ghanta and walked up to sand heap and slept within 15 minutes as alleged was quite impossoble since the sand heap was wet. The engineer made a false report. There had been a hot discussion between the workman and the Engineer over cables and other machines that were lying near the alleged place of occurrence in presence of Havildar. The engineer was also bearing a grudge against the workman as the workman never gave any "salam" to the engineer. There was an order for enquiry, (Ext. M2) which was to be held on 25th September 1970 but was on the prayer of the workman shifted to 28th September 1970 *vide* Ext. M2(4). The enquiry was held by the enquiry officer. The management examined three witnesses, first is Barid Baran Mukherjee, Engineer, who was cross-examined by the workman. His evidence in examination in chief shows that at about 9-30 p.m. on 7th September 1970 when the second shift was on he came round the yard of the manager's office and saw the workman lying flat on a heap of sand. The engineer stood by the side of the sleeping workman for a few second and focused his torch on his face. He was found fast asleep. He was awakened by the engineer. Thereafter the engineer came back to his quarter *via* his office. There was never any discussion with the workman over any matter. He never expected any 'salam' from any meneal and he was only concerned in doing his duty. It was false to suggest that he bore a grudge against the workman for his not extending salam to the engineer. In cross-examination the witness stated that he had no discussion with the workman on the night of 7th September 1970 regarding machines and cables that were lying on the open near the place where the workman was on guard duty. That the sand heap was wet was not suggested to the witness in cross-examination by the workman. The second witness is Kanai Das, Winding Engineer Khalasi. He was on duty in the second shift on 7th September 1970 at pit No. 8. At about 9 p.m. the witness saw the workman sitting on a sand heap and smoking a Bidi. At about 9.25 p.m. the engineer came to inspect the work of pit No. 9, *via* the sand heap when the workman was lying flat on the sand heap. The witness found the workman sleeping on the sand heap. The engineer awakened the sleeping workman and left the place thereafter. The witness also came back to his post. This witness heard the workman's striking the bell 9 times at 9 p.m. The witness saw Ramdhari the workman sitting on the sand heap at 9 p.m. I found engineer near No. 8 pit at about 9-20 p.m. when Ramdhari was lying flat on the sand heap and was sleeping. To the witness it was suggested that the sand was wet and he denied. The third witnesss is Puja Sankar Dubey, Havildar. He came to say that on 7th September 1970 in his presence there was no discussion between workman and the engineer regarding the machine and cables. He was not cross-examined by the workman. The workman made his statement. He admitted that he was on guard duty on the second shift on 7th September 1970. He said that he was smoking a Bidi sitting on the sand heap at about 9 p.m., after finishing the striking of the bell. At about 9-15 p.m. the engineer came and asked him why he was sleeping on the sand heap. The workman replied that he was not sleeping but was sitting on the sand heap. Then the engineer went away. On that day that means on 7th September 1970 the workman had no altercation with the engineer about the cable and the machine and on previous occasion also he had no altercation with the engineer on any subject. He had no witness to prove his plea in defence. So, the plea in defence to the charge of the workman was that because the engineer bore a grudge against the workman and because there was hot discussion between the workman and the engineer on 7th September 1970, the false charge was engineered against the workman. In his written explanation and oral statement there was nothing regarding the workman's making any demand of any allowance of the management at any time and refusal of the management to accede to that demand. In the statement of case filed by the union on behalf of the workman it was stated that because the workman made demand of night allowance and other monetary benefits of the management, the management got enraged with the workman and manufactured the false charge. In reply to the chargesheet the defence of the workman was that because he had a hot discussion 7th September 1970 with the engineer and because he never salamed the engineer, the engineer bore grudge with the workman and made a false report against him and he was charged falsely for having had slept while on duty. The workman before the enquiry officer, clearly admitted that he had no discussion on 7th September 1970 or on any previous occasion. The workman never made a case before the enquiry officer that because he made a demand of certain monetary benefits of the management, the management was enraged with the workman wherefor the workman was levelled with the false charge. The enquiry report was submitted by the enquiry officer who on considering the materials found the workman guilty of the offence charged *vide* Ext. M2(16).

11. Before the enquiry on first charge had commenced, the workman was again chargesheeted on 23rd September 1970 by the Manager for having had slept on 22nd September 1970 at about 12-40 A.M.

while deputed as magazine guard from 12 a.m. to 8 a.m. It should be 12 mid-night to 8 a.m. as would appear from the evidence on record. In the charge-sheet it was also referred that he chargesheeted for the same offence earlier. So in the chargesheet it was stated that he was guilty of gross negligence of duty and was charged under paragraph 27(10) of the Standing Orders. He was asked to show cause, Ext M2(7). In his explanation the workman stated that he went to the magazine at about 8 p.m. and slept there. Kharka Bahadur Thapa, came at 9 p.m. and he was awakened by him at 12 o'clock. At about 10-30 p.m. Sri Dubey came to him and saw him sleeping. Dubey stole his torch. He was awakened at 12 O'clock when his duty started. At that time one Paresh Nath Dubey came in whose hand the torch was found. The workman demanded back his torch and questioned Paresh Nath why he had stolen the torch. This enraged Paresh Nath who then gave out that as the workman was sleeping on duty Paresh Nath took away the torch. He further stated that at 12-40 O'clock he was not sleeping but was working. The charge was brought against the workman as there was rivalry between him and Paresh Nath Dubey. The workman was a witness in a case against Dube-ji's party. Upon the explanation an enquiry was ordered to be held on 28th September 1970 *vide* Ext. M2(8). At the request of the workman the date of enquiry was shifted to 1st October 1970 *vide* Ext. M2(10). On 1st October 1970 the enquiry officer held the enquiry in presence of the workman. On 1st October 1970 the management examined Paresh Nath Dubey, L/Naryak, Kharka Bahadur Thapa Watchman, Jagainder Jha, Watchman and Puja Sankar Dubey, Havildar. Dilip Kr Sarcar, Magazine clerk. Paresh Nath Dubey was cross-examined by the workman, so also Kharka Bahadur and Jaginder Jha. Cross-examination of Puja Shankar Dubey was declined by the workman, so also of Dilip Kumar Sarkar The workman refused to sign the statement of Dilip Kumar Sarkar and Sri Paresh Nath Dubey as recorded by the enquiry officer. Then the workman made a statement. The workman said that he had no witness in proof of his plea in defence. The statement was that at about 12-15 p.m. he was awakened by Sri Jaginder Jha and he took charge from him. Since then he was sitting and at about 12-40 O'clock Paresh Nath Dubey came at the magazine for surprise visit. The workman asked Paresh Nath to return his torch. Paresh Nath refused to return the torch to the workman as he found the workman sleeping while on duty at about 12-40 a.m. The workman said that he was sitting from 12 O'clock of the night to 8 a.m. next morning, 22/23rd September, 1970 and that he did not sleep at any time. Two months before the date of occurence he had one altercation with Paresh Nath Dubey about the workman's duty hours. After that there was no altercation with Dubey. Jaginder Jha said that at 12 O'clock of the night on 22nd September 1970 he gave charge to the workman and went to his quarter. Upto 12-15 a.m. of 22nd September 1970/23rd September 1970 the workman was sleeping. He was awakened by Jaginder Jha from whom he took charge. To the witness Joginder Jha the workman suggested that after the workman was awakened from his sleep he found his torch light missing and enquired of Joginder Jha if he knew anything of the torch light. Jaginder Jha said in his cross-examination that he never knew that Ramdhari had a torch light and that a Ramdhari never enquired of him about his torch light. So upto 12-15 O'clock of the night when the workman Ramdhari was asleep and was at that time awakened by Jaginder, Ramdhari's torch light was not missing. Then the question is whether his torch light was stolen by Paresh Nath Dubey witness No. 1 for the management and if at all Paresh Nath Dubey stole the workman's torch light, it must have occured after 12-15 O'clock of the night of 23rd September 1970. According to workman at 12-40 O'clock of the night Paresh Nath Dubey came to the spot when the workman was working on a surprise visit when the workman demanded of Paresh Nath the torch belonging to the workman which had been stolen by Paresh Nath. So between 12-15 O'clock of the night to 12-40 O'clock of the night that means after Jagindar had awakened the workman and the workman was wide awake his torch was stolen. If his story is to be believed the workman should be held to be throughly incompetent as a watchman since from a wide awake watchman none can hardly steal his torch particularly when the thief is known to the workman. So, let us come to Paresh Nath Dubey's statement. He said at about 12-40 a.m. when he inspected the Magazine he found the workman sleeping. He took the workman's torch. The workman was in deep sleep. Kharka Bahadur was also sitting at that time and in presence of Kharka Bahadur Paresh Nath Dubey took away the torch of the sleeping workman, deputed to magazine for guard duty. Kharka Bahadur, witness No. 2 for the management said that he was deputed as a magazine guard from 9 p.m. to 5 a.m. of 22nd September 1970. While he was on duty Paresh Nath Dpbey came for a surprise visit and found Ramdhari peon on guard duty asleep and took away the workman's torch. Thereafter Dubey awakened the workman and remarked "Ehi duty hota hai". The workman cross-examined both Paresh Nath and Kharka Bahadur and in cross-examination both the witnesses affirmed their statement made in examination in chief regarding the workman's sleeping while on duty at about 12-40 a.m. of 23rd September 1970. Sri Puja Shankar Dubey said that at about 2 a.m. of 23rd September 1970 Paresh Nath Dubey reported to the witness that the workman Ramdhari Singh was found sleeping while on duty and that he took away the torch of Ramdhari while he was found sleeping on duty. Dubey deposited the torch with the witness and the witness deposited the torch with the Welfare Officer on the morning of 23rd September 1970. The witness was not cross-examined by the workman. Dilip Sarkar magazine clerk was deputed to work on the third shift of 22nd September 1970 at about 1 a.m. when he reached at the magazine, he heard Ramdhari Singh, workman, threatening Paresh Nath Dubey with dire consequences if Paresh Nath would take any action against the workman. The witness saw Ramdhari the workman sitting on a spreadover blanket and Paresh Nath Dubey standing by his side. The witness took no interest in the affair and went inside the magazine room. Cross-examination of this witness was declined by the workman. On these materials the enquiry officer gave a report Ext. M2 (13) dated 7th October 1970 finding the charge established. The Manager forwarded the two chargesheets and the two enquiry reports with his remark, Ext. M2(14) to the General Manager who after considering all the materials ordered that the workman should be dismissed. On 23rd October 1970 Superintendent Personnel, recorded the order of dismissal Ext. M2 (15). The dismissal order was to take effect from the date of service of the same on the workman. Ext. M2(16) is the dismissal order under the signature of the Manager which was to take effect on and from 28th October, 1970. Ext.M2(17) is the Standing Order for the Coal Minning Industry governing all the collieries affiliated to Indian [illegible] Paragraph 27 clause (10) of th[illegible] shows 'sleeping on duty' is a misconduct. The Standing order does not provide for supplying any copy of the domestic enquiry report to a workman charged with any disciplinary offence by the management.

12. Now, I have analysed and considered the materials of the domestic proceedings. The two repeated offence committed by the workman were definitely established against him. He failed to establish any reasonable probability of his plea as taken in defence to the charges that were enquired into in the two separate proceedings. I have already mentioned that the *bonafides* of the enquiry and the legality and propriety of the enquiry were never challenged and it was never suggested even in the statement of case and in the rejoinder filed by the union

that both the enquiries were vitiated by non observance of the rules of natural justice. On the other hand, I find that the workman was given adequate opportunities to cross-examine the management's witness and to produce his own witness for establishment of his pleas in defence to the charges. The two enquiries were very fairly conducted and were not tainted with *malafides*. There is nothing in record to justify interference either with the findings of the enquiry officer or of the heirarchy of officers right upto the General Manager. The workman asked for copies of the enquiry report. The Manager refused to supply as there was no provision in the Standing orders. I do not find any ground for interference with the order of dismissal. For the union it was alleged by the officer representing the union for the workman that because the wrokman demanded his dues of the management, the management got infuriated with the workman and engineered false charges against him and that upon false evidence the management dismissed the workman. So, it was attempted to argue that it was a case of victimisation of the workman for which the tribunal should interfere with the order of dismissal and should set it aside and reinstate the workman to his post with all monetary benefits from the date of dismissal to the date of his reinstatement. Now, as Section 11A of the Industrial Disputes Act stands, such a plea can not now be entertained, nor evidence in support of such a plea can now be taken in these proceedings. When the workman was chargesheeted for two separate offence committed on two separate dates, he took specific pleas in defence and failed to establish the reasonable probability of those pleas. On the other hand, the materials on record apply justify to find those pleas as unsubstantial. If the workman would have taken such a plea as that now taken in the statement of case filed by the union representing the workman and as that that was argued by Sri Singh for the union, and if the enquiry officer failed to bestow any consideration on such plea and on the evidence, its adduced, however slender that would have been adduced by the workman to establish such plea, then the enquiry reports might have suffered from perversity, if not bias. But, the workman did not raise the plea in the two domestic proceedings on the score of victimisaton in the manner and to the extent raised in the statement of case filed for the workman by the union. So, the plea now taken and which was not taken in the two domestic enquiries cannot be considered in view of the existing provision of Section 11A of the Industrial Disputes Act.

13. In the result, I do not find any reason to interfere with the order of dismissal of the workman, nor do I find any reason to hold that the workman, by the dismissal order was victimised, nor do I find anything to hold that the two domestic proceedings suffered from illegalities and improprieties. So, I conclude that the management of the colliery concerned was justified in terminating the service of the workman and that the workman is not entitled to any relief.

This is my award.

(Sd.) S. N. BAGCHI,
Presiding Officer.

Dated, 18th May, 1972.

[No. L/1912/18/71-LRII.]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Delhi, the 23rd February 1972

S.O. 1543.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of New Ghusick Colliery of Messrs Ghusick and Muslia Collieries Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of New Ghusick Colliery of Messrs Ghusick and Muslia Collieries Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan in locking out the mine with effect from 8 A.M. of the 7th February, 1972, *vide* their notice dated the 4th February, 1972, is legal and justified? If not, to what relief are the workmen of the colliery entitled?"

[No. L/19012/21/72-LRII.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी 1972

का० आ० 1543.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स घुसिक एण्ड मुस्लिया कोलियरीज लिमिटेड की न्यू घुसिक कोलियरी, डाकघर कालीपहाड़ी, जिला बर्दवान, के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिणयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स घुसिक एण्ड मुस्लिया कोलियरीज लिमिटेड की न्यू घुसिक कोलियरी, डाकघर कालीपहाड़ी, जिला बर्दवान के प्रबन्धमण्डल की अपने तारीख 4 फरवरी 1972 के नोटिस द्वारा 7 फरवरी 1972 के प्रातः 8 बजे से खान में

तालाबन्दी करने की कार्यवाही अवैध और न्यायोचित है। यदि नहीं, तो कोलियरी के कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? "

[संख्या एल/19012/21/72-एल० आर०-2]

S.O. 1544.—Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. L/19012/21/72-LRII, dated the 23rd February, 1972, an industrial dispute between the employers in relation to the management of New Ghusick Colliery of Messrs Ghusick and Muslia Collieries Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan (West Bengal) and their workmen has been referred to the Industrial Tribunal Calcutta, for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the lock-out in existence in the said Colliery in connection with the said dispute.

[No. L/19012/21/72-LRII-(i).]

BALWANT SINGH, Under Secy.

का० आ० 1544.—यतः मैसर्स घुसिक एण्ड मुस्लिया कोलियरीज लिमिटेड की न्यू घुसिक कोलियरी, डाकघर काली पहाड़ी, जिला बर्दवान (पश्चिम बंगाल) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या एल 19012/21/72-एल०आर०-2, तारीख 23 फरवरी, 1972 द्वारा औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित किया जा चुका है;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त कोलियरी में उक्त विवाद के सम्बन्ध में विद्यमान तालाबन्दी के जारी रखे जाने को एतद्द्वारा प्रतिषिद्ध करती है।

[संख्या एल 19012/21/72-एल० आर०-2(i)]

बलवन्त सिंह, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st May 1972

S.O. 1545.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1 dated the 17th November, 1971, published at page 1 of the Gazette of India Part II Section 3, Sub-section (ii) dated the 1st January 1972,—

(i) in clause 1, *for* 1971 read 1972;

(ii) in caluse 2—

(a) *for* "sub-item (e)" *read* "sub-item (f)";

(b) *for* "(f)" *read* "(g)";

(iii) in clause 3—

(a) *for* "sub-item (c)" *read* "sub-item (f)";

(b) *for* "(f)" *read* "(g)".

[No. 54/13/70-P&D.]

O. P. TALWAR, Dy. Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 मई, 1972

का० आ० 1445.—भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और नियोजन विभाग) की, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख प्रथम जनवरी, 1972 के पृष्ठ 1 पर प्रकाशित अधिसूचना सं० का० आ० तारीख 17 नवम्बर, 1971, में,—

(i) खंड 1 में, 1971 के लिए 1972 पढ़िए ;

(ii) खंड 2 में—

(क) "मद (ङ)" के स्थान पर मद (च) (;)

(ख) 'च' के स्थान पर '(छ)';

(iii) खंड 3 में—

(क) 'उपमद (ङ)' के स्थान पर (उप-मद (च)';

(ख) '(च)' के स्थान पर '(छ)'।'

[सं० 54/13/70-पी एंड डी]

ओ० पी० तलवाड़, उप सचिव।

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 27th December, 1971

S.O. 1546.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 4 of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951, the Central Government hereby appoints for the Union Territory of Delhi, Shri Harish Chandar, Assistant Settlement Commissioner, as Competent Officer for the purpose of discharging the duties assigned to the Competent Officer by or under the said Act, within the said Territory, with immediate effect.

[No. P/F.1(3)/Admn.II/70.]

JANKI NATH,
Settlement Commissioner (C), and
Ex-officio Under Secy.

(पुनर्वास विभाग)

मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त कार्यालय

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर 1971

एस० ओ० 1546.—निष्क्रान्त हित (पार्थक्य) नियम 1951 की धारा 4 उपधारा (i) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दिल्ली प्रशासन क्षेत्र के लिए तत्काल ही श्री हरीशचन्द्र सहायक बन्दोबस्त आयुक्त को सक्षम अधिकारी नियुक्त करती है ताकि वे उन कार्यों को कर सके जो सक्षम अधिकारी के

पद के लिए उक्त अधिनियम के द्वारा या अन्तर्गत उक्त प्रशासन के लिए निर्धारित की गई हैं।

[सं० पी/एफ संख्या 1(3)/एडमिन II/70]

जानकी नाथ,

बन्दोबस्त आयुक्त (सी) तथा पदेन अवर सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 20th June 1970

S.O. 1547.—Whereas the post of the Director of Audit and Accounts, Posts and Telegraphs, Stores, Workshops and Telegraphs Check, Calcutta, who is the disciplinary authority according to the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. S.R.O. 639, dated the 28th February, 1957, as amended by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, No. S.O. 3777 dated the 5th September, 1969, has been kept in abeyance on and from the 1st May, 1969. Now therefore the President, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 hereby specifies:—

(i) the Director of Audit and Accounts, Posts and Telegraphs, Calcutta, as the disciplinary authority under clause (b) of sub-rule (2) of rule 12, and

(ii) the Accountant General, Posts and Telegraphs as the appellate authority under rule 24,

of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 in respect of employees of the erstwhile office of the Director of Audit and Accounts, Posts and Telegraphs Stores, Workshops and Telegraphs Check, Calcutta.

[No. F.1(34)-EG.I/70.]

K. N. SINGH, Director.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून 1970

का० आ० 1547.—यतः, निदेशक संपरीक्षा और लेखा, डाक-तार स्टोर, कर्मशाला और तार जांच, कलकत्ता, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3777 तारीख 5 सितम्बर, 1969 द्वारा यथा संशोधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 639 तारीख 28 फरवरी, 1957 की अनुसूची के अनुसार अनुशासनिक अधिकारी हैं, का पद 1 मई, 1969 को और से प्रास्थगन में रखा गया है।

अतः अब राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपरीक्षा और लेखा, डाक-तार, स्टोर, कर्मशाला और तार जांच कलकत्ता के भूतपूर्व निदेशक के कार्यालय के कर्मचारियों की बाबत,

(i) निदेशक संपरीक्षा और लेखा, डाक-तार, कलकत्ता को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में, और

(ii) डाक-तार महालेखापाल को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 24 के अधीन अपीली प्राधिकारी के रूप में

विनिर्दिष्ट करते हैं।

[सं० फा० 1 (34)-ई जी-I/70]

कुलदेव नारायण सिंह, निदेशक।

(राजस्व और बीमा विभाग)

बीमा

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5484.—आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 50) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 10 दिसम्बर, 1971 को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए तारीख के रूप में, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० फा० 66(4)/बीमा 1/71]

का० आ० 5487.—आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51) की धारा 5 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 10 दिसम्बर, 1971 को, उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए तारीख के रूप में, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० फा० 66(4)/बीमा/1/71]

ए० राजगोपालन,

विशेष कर्तव्यारूढ अधिकारी और पदेन अवर सचिव।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

INCOME-TAX

New Delhi, the 17th December 1971

S. O. 1548—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of their Notification No. 258/1971 of even number dated the 1st September, 1971 the Central Board of Direct Taxes hereby directs that in the Annexure A to the aforesaid Notification dated the 1st September, 1971, the entries

under columns (2) and (3) against S. Nos. 16 and 21 shall be substituted by the following:—

S. No.	Commissioners of Income tax	Additional Commissioners of Income Tax.
1	2	3
16	Commissioner of Income-tax, Bihar, Patna.	Addl. Commissioner of Income-tax (Recovery), Patna.
21	Commissioner of Income-tax West Bengal V, Calcutta.	Addl. Commissioner of Income-tax (Recovery II) Calcutta.
	Commissioner of Income-tax Orissa, Bubaneswar.	

This notification shall take effect fron the 1st January, 1972.

[No. 353 (F. No. 187/8/71-IT (AI)]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(आय-कर)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1971

एस० ओ० 1548.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी तारीख 1 सितम्बर, 1971 की उसी संख्या वाली अधिसूचना सं० 258/1971 को भागत : उपान्तरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि पूर्वोक्त अधिसूचना, तारीख 1 सितम्बर, 1971 के उपाबन्ध क में, क्र० सं० 16 और 21 के सामने स्तम्भ (2) और (3) के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

क्र० सं०	आयकर आयुक्त	अपर आयकर आयुक्त
1	2	3
16	आयकर आयुक्त बिहार, पटना ।	अपर आयकर आयुक्त (वसूली), पटना ।
21	आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल 5, कलकत्ता 1	अपर आयकर आयुक्त (वसूली 2), कलकत्ता ।
	आयकर आयुक्त, उड़ीसा, भुवनेश्वर ।	

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त होगी ।

[सं० 353 (फा० सं 187/8/71-आ० क० (ए 1)]

New Delhi, the 23rd December 1971

S.O. 1549.—In partial modification of Notification No. 258 dated 1st September, 1971 as revised by Notification No. 270 dated 10th September, 1971 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that with effect from 1st January, 1972 the Additional Commissioner of Income-tax (Recovery), Jaipur, shall also perform all the function of Additional Commissioner of Income-tax, Jaipur.

[No. 358(F.No.187/8/71-IT(AI).]

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1971

एस०ओ० 1549.—अधिसूचना सं० 270, तारीख 10-9-71 द्वारा यथा पुनरीक्षित अधिसूचना सं० 258, तारीख, 1-9-71 को भागत : उपान्तरित करते हुए और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि अपर आयकर आयुक्त (वसूली), जयपुर भी 1-1-72 से अपर आयुक्त, जयपुर के सभी कृत्यों का पालन करेगा ।

[सं० 358 फा० सं० 187/8/71-आक (ए1)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th December 1971

S.O. 1550.—In exercise of the powers conferred by Section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby modifies its notification No. 8(F. No. 187/14/71-IT(AI), dated 5th October, 1971 as under:—

Against S. No. 62-A, under column 6, *for* Addl. C.I.T., A.P.I., Hyderabad *read* Addl. C.I.T., A.P., Hyderabad

[No. 11(F.No. 187/14/71-IT(AI).]

B. MADHVAN, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर 1971

का० आ० 1550.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 8 (फा० सं० 187/14/71-आ क (ए1), तारीख 5-10-71 को एतद्द्वारा निम्न प्रकार उपान्तरित करता है :—

क्र० सं० 62-क के सामने, स्तंभ 6 के नीचे, अपर आयकर आयुक्त, आंध्रप्रदेश, 1, हैदराबाद के स्थान पर, अपर आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद पढ़े ।

[सं० 11 फा० सं० 187/14/71-आक(ए 1)]

बी० माधवन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972